राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 227

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

वह दिन दूर नहीं, जब सीधे मैदान पर लैंडिंग करनी होगी

>> 14

हर एसिड सर्वाइवर अपने पीछे की जिंदगी को भूल आज सुखन भरी दुनिया में जीने की जुगत में जुटी हैं। यह काम कितना कठिन है, इसे केवल वही महसूस कर सकती हैं। इनके इस हौसले को हम सलाम करते हैं! पेज-11

फांसी के मामले में अंतहीन मुकदमेबाजी नहीं चलेगी : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि फांसी की सजा में फाइनेलिटी (सजा का अंतिम होना) बेहद जरूरी है। दोषी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह इस पर कभी भी सवाल उठा सकता है। मृत्युदंड में अंतहीन मुकदमेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणी फांसी की सजा पाए अमरोहा कांड के दोषी सलीम और उसकी प्रेमिका शबनम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गुरुवार को भले ही कोर्ट ने टिप्पणी अमरोहा कांड के दोषियों के मामले की सुनवाई के दौरान की हो, लेकिन दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषियों के मृत्युदंड टालने के लिए अपनाए जा रहे रवैये को देखते हुए टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली दुष्कर्म कांड के मामले में कुल चार दोषी हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और निचली अदालत उन्हें फांसी देने के लिए एक फरवरी की तिथि भी तय कर चुकी है लेकिन दोषी मामले में देरी करने के लिए एक-एक कर अर्जी दाखिल कर रहे हैं। कुख्यात रंगा-बिल्ला, उजागर-करतार सिंह, मकबूल भट्ट समेत कई मामलों में फांसी को टालने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाया जाता रहा है।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावन खेड़ी गांव निवासी शबनम ने 2008 में प्रेमी सलीम के साथ मिल कर अपने माता पिता सहित परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में दस माह का बच्चा भी शामिल था। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से शबनम व सलीम को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी माफ करने की गुहार लगाई है जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। दोषियों के वकील ने गरीबी और जेल में उनके अच्छे आचरण का हवाला देते हुए फांसी की सजा माफ करने की अपील की। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट को शबनम के जेल में व्यवहार को देखते हुए उसमें सुधार होने की गुंजाइश के मद्देनजर मौत की सजा माफ करनी चाहिए। यह भी कहा कि उसका एक बच्चा है।

इन दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी का जेल का व्यवहार पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वह जेल के स्कूल में पढ़ाती है। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होती है। कोर्ट ने कहा कि क्या इससे दस महीने के बच्चे की हत्या का जुर्म खत्म हो गया।

- अमरोहा कांड के दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- शीर्ष अदालत ने कहा-मृत्युदंड में सजा का अंतिम होना बेहद जरूरी

प्रतीकात्मक फोटो

कोर्ट कानून के मुताबिक चलता है और कानून अपराधी के लिए होता है। न्यायाधीश के पास किसी भी अपराधी को माफ करने का अधिकार नहीं होता है। न्यायाधीश तो पीड़ित और समाज को न्याय देने के लिए है।

सरकार ने कहा, कोर्ट फांसी के बारे में जल्द तय करे टाइम लाइन

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह मंत्रालय की बुधवार को दाखिल अर्जी का जिक्र करते हुए कहा, कोर्ट फांसी के मामले में टाइम लाइन तय करे। कोर्ट समाज व पीड़ित को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी करे। कोर्ट ने कहा, ये दलीलें वे उस अर्जी पर सुनवाई में रखें। अभी मौजूदा मामले पर बहस करें।

हत्यारे अनाथ होने के आधार पर दया की कर रहे गुहार

उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषियों की याचिका का विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा, यह तो उसी तरह की बात है कि मां-बाप को मारने वाला अनाथ होने की दुहाई देकर दया की भीख मांगे। कोर्ट ने हर पहलू पर विचार के बाद मौत की सजा दी थी। उसे रद करने का कारण नहीं है।

निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट जारी करने वाले जज का तबादला पेज>>5

जागरण विशेष

एक और सुपर मॉम! मुक्केबाज हेड कांस्टेबल रीना

चंडीगढ़ : बॉक्सिंग में जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने रीना को हाल ही में प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल बनाया है। दो बच्चों की मां रीना 25 पदक जीत चुकी हैं। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

राज ठाकरे ने बदला झंडा, बेटे को उतारा राजनीति में

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने पार्टी का झंडा (नीले, हरे एवं भगवा रंग की पट्टियों पर रेल का इंजन) बदलकर हिंदुत्व का रंग (भगवा रंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर) गाढ़ा करने का संकेत दिया है। साथ ही पुत्र अमित को भी राजनीति में उतार दिया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

झारखंड में सीएए के समर्थन में निकले जुलूस पर हमला

लोहरदगा : झारखंड के लोहरदगा जिले में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर हमला किया गया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने तोड़फोड़ और अगजनी भी की। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

चीन ने वुहान और हुआंगगांग में पूरी तरह से बंद की आवाजाही

बीजिंग : चीन ने रहस्यमय कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र माने जा रहे एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले वुहान और 75 लाख की आबादी वाले हुआंगगांग शहरों में आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। सांस लेने में परेशानी का कारण बनने वाला यह वायरस चीन के कई शहरों को चपेट में लेने के बाद अमेरिका तक पहुंच गया है।

विश्व कप की तैयारी
पहला टी-20
भारत vs न्यूजीलैंड
दोपहर 12:20 बजे से
स्थान : ऑकलैंड
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

370 हटाने का फैसला वापस लेना मुमकिन नहीं : केंद्र

सुप्रीम सुनवाई ▶ सरकार बोली, अस्थायी थी जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता

संविधान पीठ ने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वापस लेना मुमकिन नहीं है और अब इस बदलाव को स्वीकार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस तर्क का भी जोरदार तरीके से विरोध किया कि जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ विलय नहीं हुआ था। सरकार ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अनुच्छेद 370 की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के सामने केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के पांच अगस्त 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात जजों की बड़ी पीठ को सौंपने की मांग का भी विरोध किया। इसके बाद पीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा,वह इस पर विस्तृत आदेश पारित करेगी।

- कोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को सौंपने पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) नामक एनजीओ, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कुछ अन्य ने इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की मांग की है। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के दो फैसले (1959 का प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर और 1970 का संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर) एक-दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए पांच जजों की मौजूदा पीठ इस पर सुनवाई नहीं कर सकती है।

जस्टिस रमना, संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र की तरफ से उपस्थित अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, अनुच्छेद 370 पर फैसला अब अपरिवर्तनीय है और इसे स्वीकार करना ही विकल्प है।

वेणुगोपाल ने कहा, इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है कि जम्मू-कश्मीर का भारत संग विलय नहीं हुआ था या जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच विलय का कोई दस्तावेज नहीं है। जम्मू-कश्मीर का विलय नहीं हुआ होता तो अनुच्छेद 370 की जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने इस संबध में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के सचिव रहे वीपी मेनन द्वारा लिखित किताब 'द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स' का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, विलय के दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता वास्तव में अस्थायी थी। हम राज्यों के संघ हैं। इस दस्तावेज पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे।

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि वह इस मामले को बड़ी पीठ को नहीं सौंपने के केंद्र सरकार के तर्क से सहमत हैं। लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर का संविधान और संधि पूरी तरह खत्म हो गई है।

मप्र में दो युवकों के खाते में आए 274 करोड़ रुपये आयकर विभाग सक्रिय

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के दो युवकों के नाम पर मुंबई स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में खुले खाते में 274 करोड़ रुपये जमा होने और फिर इस राशि को निकाल लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस लेनदेन को लेकर आयकर विभाग ने युवकों को साढ़े चार करोड़ रुपये का टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया है। दोनों युवकों सामान्य नौकरीपेशा हैं और इस लेनदेन की जानकारी मिलने से हैरान हैं। पहेली बने 274 करोड़ रुपये की छानबीन में आयकर विभाग जुट गया है। इस रकम के लेनदेन में कुछ हीरा कंपनियों के नाम सामने आए हैं।

सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने मामले की गोपनीय छानबीन शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक की बांद्रा रिक्लेमेशन शाखा में रवि गुप्ता (भिंड निवासी) के नाम से खोले गए खाते में 132 करोड़ व कपिल शुक्ला (रीवा निवासी) के खाते में 142 करोड़ रुपये जमा हुए और चार-पांच माह में निकाल भी लिए गए। रकम का लेनदेन अगस्त 2011 से जनवरी 2012 के बीच हुआ। यह राशि कहां से आई और कहां गई, इसका राजफाश होना बाकी है। दोनों खातों के लेनदेन के ब्योरे से पता चला है कि यह रकम 30 लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक करीब ढाई दर्जन कंपनियों से आई और 10-15 करोड़ रुपये की रकम इकट्ठा होते ही आधा दर्जन कंपनियों में एकमुश्त डाली गई। इनमें से ज्यादातर उस वक्त डायमंड कंपनियों के बतौर पंजीबद्ध थीं, जो बाद में बंद हो गईं।

दोनों युवक भी संदेह के घेर में पेज>>7

'कश्मीर पर बयानबाजी से इमरान की कुंठा जाहिर'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दो दिन पहले दावोस में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्लूईएफ) में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विभिन्न नेताओं से मुलाकात में जिस तरह से कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की, उसे भारत ने सिरे से खारिज किया है। कहा कि इमरान की बयानबाजी से कश्मीर पर उनकी कुंठा जाहिर होती है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ लंबे-लंबे झूठ गढ़े, पर वैश्विक मंच पर वह कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में नाकाम रहा। इसके अलावा, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर 'मदद' करने के सुझाव को नकारते हुए साफ किया कि कश्मीर भारत-पाक का द्विपक्षीय मामला है और इसमें तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है।

कश्मीर और भारत के कुछ कानूनी उपायों के जरिए दक्षिण एशिया की भयावह तस्वीर पेश कर रहे इमरान खान को गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक सलाह दी है कि वह पहले अपने देश के अंदरूनी हालात पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि पाक से रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब पड़ोसी देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाये और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को इसके बारे में संतुष्ट कर दे।

दावोस में इमरान ने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य होने की बात भी कही थी। उन्होंने अपने देश को एक बेहतरीन कारोबारी स्थल के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। यह कहा था कि अगर भारत के साथ रिश्ते सुधर जाते हैं तो पाक की आर्थिक संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। उनके इस बयान को कई लोगों ने पाक के रुख में भारत को लेकर आ रही नरमी के तौर पर देखा है, लेकिन भारत सिर्फ पीएम खान के एक भाषण से अपने विचार नहीं बनाएगा।

रविश कुमार फाइल

भारत की दो टूक, अपने अंदरूनी हालात पर ज्यादा ध्यान दे पाकिस्तान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा,'पाक पीएम के बयान के लहजे से हम वाकिफ हो चुके हैं और उनकी बात से साफ है कि वह हताशा में बयान में दे रहे हैं। वह निराशा की तरफ जा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि वैश्विक समुदाय उनके दोहरेपन को बखूबी समझ चुका है। अगर वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर हैं तो क्यों नहीं आतंकी समूहों व आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनको कश्मीर व भारत की अंदरूनी स्थिति को लेकर डरावने बयान देने बंद करना चाहिए और अपने देश के भीतर के हालात पर ध्यान देना चाहिए।'

ट्रंप को भी जवाब, भारत को कश्मीर पर तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पेज>>3

असम में 644 उग्रवादियों ने किया समर्पण

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में आठ प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि उग्रवादी संगठन उल्फा (आई), एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, भाकपा (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ और एनएलएफबी के सदस्यों ने एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया।

पुलिस महानिदेशक ज्योति महंता ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, 'राज्य के लिए और असम पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। आठ उग्रवादी समूहों के कुल 644 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है।' इस मौके पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वह उन लोगों से अपील करते हैं जो अभी भी मुख्यधारा के बाहर हैं, वह आगे आएं और भारत को एक सशक्त देश बनाएं। बिना शांति के प्रगति संभव नहीं है। सभी देश विभिन्न क्षेत्रों में महारथ हासिल कर रहे हैं। इससे शांति स्थापित होती है और हमें भी यही करना है।

- उल्फा (आइ) समेत आठ प्रतिबंधित संगठनों ने 177 हथियार डाले
- सीएम सोनोवाल की उन लोगों से आगे आने की अपील जो मुख्यधारा से हैं बाहर

गुवाहाटी जिले में गुरुवार को 600 से अधिक उग्रवादियों द्वारा समर्पित किए गए हथियार और गोला-बारूद का निरीक्षण करते सीएम सर्बानंद सोनोवाल (बीच में)। एपी

उन्होंने कहा कि लोग इस बात से खुश हैं कि आप असम के विकास के लिए मुख्यधारा में लौट आए हैं। आपने उन सभी को प्रेरित किया जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करेगी। उल्लेखनीय है कि सरेंडर करने वाले सर्वाधिक उग्रवादी नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ बेंगाली (एनएलएफबी) के हैं। इसके बाद आदिवासी ड्रैगन फाइटर के 178 और नेशनल संथल लिब्रेशन आर्मी के 87 हैं। अन्य सरेंडर करने वालों में 50 उग्रवादी उल्फा (आइ) के भी हैं।

गाजियाबाद में सड़क पर विमान की आपात लैंडिंग

गाजियाबाद में गुरुवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के टू सीटर विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। बाद में विमान को गाड़ी पर लादकर ले जाया गया। यह विमान एनसीसी और वालंटियर के इस्तेमाल में आता है। (खबर पेज-5 पर) अनिल बराल

नया कश्मीर

सेना करियर काउंसलिंग कैंप लगाकर बदल रही है युवाओं की सोच, खेल, पढ़ाई और कौशल विकास के क्षेत्र में संभावनाओं की दी जा रही है जानकारी

आतंकवाद से जंग के साथ ही युवाओं का भविष्य संवार रही सेना

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर में लगातार सामान्य हो रहे हालात के बीच सेना आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ नए कश्मीर की नींव भी रख रही है। स्थानीय बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के साथ मुख्यधारा में शामिल कर उनमें राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए सेना ने एक विशेष कार्ययोजना बनाई है। इस कार्ययोजना का खाका स्थानीय लोगों की मदद से ही तैयार किया गया है। शिक्षा, रंगमंच, कौशल विकास, प्लेसमेंट, नशा उन्मूलन और खेल समेत कई क्षेत्रों में युवाओं को आगे ले जाने के लिए कश्मीर के विभिन्न जिलों में करियर काउंसलिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आतंकियों के फरमान को ठेंगा दिखा अपने बच्चों को सेना के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बदलाव का आलम यह है कि स्थानीय लोग भी अपनी तरफ से कैंप लगाने के लिए सहयोग का प्रस्ताव लेकर पहुंच रहे हैं।

कश्मीर में बांदीपोरा में सैन्य अधिकारी युवाओं की काउंसलिंग करते हुए। सौजन्य : पीआरओ

अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती में कमी आई है। आतंकियों के समर्थन में रैलियां बंद हो चुकी हैं। मारे जाने वाले आतंकियों के जनाजों में नजर आने वाली और पत्थरबाजी करने वाली भीड़ भी गायब हो चुकी है।

ऐसे खुल गया सिलाई सेंटर : समाज सेवी सलीम रेशी ने कहा, बीते दिनों कुलगाम गया था। वहां कुछ आतंकवाद पीड़ित महिलाओं ने अपनी बेबसी बताई, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। मैंने कहा, क्या आप सिलाई कढ़ाई का काम करोगी तो उन्होंने कहा हां। मैंने निकटवर्ती सैन्य शिविर के एक अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने इन महिलाओं के घर के पास ही एक सिलाई सेंटर खुलवाने में मदद की।

मिल गया पुणे का टिकट : सेना के सहयोग से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पहुंचने वाले यावर ने कहा, मैं शुरू से ही फिल्म निर्माण में करियर बनाना चाहता था, पर पुणे पहुंचना मुश्किल था। एक दिन पता चला कि हैदरबेग, पट्टन स्थित सैन्य शिविर में पुणे से कुछ लोगों को बुलाया गया है। इन लोगों ने एक सप्ताह का कैंप लगाया था, मैंने वहां दाखिला लिया। इस बीच मैंने ग्रेजुएशन की और पुणे का टिकट भी ले लिया।

पत्थरबाजी करने वाले हाथों में बल्ला : एक महिला समाजसेवी ने कहा, डाउन-टाउन में आप सेना द्वारा किसी खेल प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में सोच सकते हैं, शायद नहीं। लेकिन ऐसा हो चुका है। सेना ने यहां क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया और पत्थरबाजी करने वाले हाथ बैट लेकर मैदान में पहुंच गए। नशा उन्मूलन पर भी बारामुला, कुपवाड़ा में एक पखवाड़े का कार्यक्रम चलाया।

जम्मू-कश्मीर के 250 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाया पेज>>6

बिहार में इस्तीफे के बाद भी शिक्षक कर रहे नौकरी, ले रहे वेतन

सुनील राज, पटना

फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर जिलों में नियोजित शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा देने के बाद भी सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। निगरानी ब्यूरो को हर जिले से ऐसी शिकायतें मिली हैं। फर्जी प्रमाणपत्र पर शिक्षकों के नियोजन के मामले में 2015 से निगरानी ब्यूरो जांच कर रही है। इसी क्रम में चौंकाने वाली जानकारी सामने आयी है। सूत्रों की माने तो एमेनेस्टी योजना के तहत दो बार में करीब तीन हजार शिक्षकों ने नियोजन इकाइयों को त्याग पत्र सौंपे थे।

शिक्षक सरकारी स्कूलों में दे रहे सेवा : सूत्रों की मानें तो त्यागपत्र देने वाले तीन हजार शिक्षकों में से करीब 22 सौ शिक्षक जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों की मदद से फिर से नौकरी पाने में सफल रहे हैं। वहीं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा, जिन शिक्षकों का त्यागपत्र स्वीकार किया जा चुका है। उनसे भविष्य में सेवा नहीं लेने का आदेश पहले ही दिया गया है। बावजूद अगर किसी जिले में ऐसे शिक्षक दोबारा नियोजित किए गए हैं तो कानूनी कार्रवाई के साथ ही वेतन मद में ली गई रकम की वसूली भी होगी। दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।

- करीब तीन हजार नियोजित शिक्षकों ने दिया था त्यागपत्र
- डीईओ-डीपीओ की मिलीभगत से दोबारा कर रहे नौकरी

यह है मामला : 2006 में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत 352812 शिक्षकों को नौकरी दी गई। 2014-15 में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्र वालों को नौकरी दी गई है। 2015 में पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को जांच का निर्देश दिया।

698 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं 70 विधानसभा सीट के लिए। 24 जनवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इसलिए शुक्रवार को ही स्पष्ट हो पाएगा कि चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार बचते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 24 जनवरी 2020

गठबंधन से बदल रही राजधानी की राजनीतिक पहचान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

गठबंधन की सियासत से दिल्ली की राजनीतिक पहचान भी बदल रही है। यहां हमेशा से सत्ता पर एक ही सियासी दल काबिज रहता आया है। अब सत्ता साझा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं।

यही वजह है कि इस दफा पहली बार कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को साथ मिला लिया है। दूसरी तरफ, भाजपा ने परंपरागत सहयोगी शिरोमणि अकाली दल बादल को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के रूप में नए साथी बना लिए हैं। इसमें दो राय नहीं कि इस बार के चुनाव परिणाम दिल्ली का सियासी चेहरा भी बदल सकते हैं।

मुगलकाल से सत्ता का केंद्र रही दिल्ली का चुनाव सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं होता। यहां से पूरे देश को एक संदेश जाता है। इसलिए यहां के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें होती हैं। इस बार यह चुनाव भी कुछ अलग ही रंग लिए हुए है। 2015 के विधानसभा चुनाव में आप ने अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए 70 में से 67 सीटें हासिल कर लीं। भाजपा ने तो तीन सीटें किसी तरह हासिल भी कर लीं, लेकिन कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। इस बार भी तीनों दलों के लिए यह चुनाव खास अहमियत रखता है। एक तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप सत्ता को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, वहीं कांग्रेस अपना वजूद बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। वह किसी भी तरह से दिल्ली की राजनीति में वापसी करना चाहती है। भाजपा के लिए दिल्ली की सत्ता हासिल करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि देशभर में हुए कई राज्यों के विधासनभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। हरियाणा में भी जैसे-तैसे ही सत्ता बचाने में कामयाब रह पाई।

भाजपा किसी भी हालत में दिल्ली की सत्ता चाहती है। इसके लिए भाजपा ने पूरी फौज दिल्ली में उतारने का निर्णय लिया है। भाजपा ने दिल्ली में देशभर के 100 से अधिक सांसदों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 स्टार प्रचारकों को भी उतारा है।

राजनीतिक परिदृश्य

- कांग्रेस ने क्षेत्रीय दल के साथ किया समझौता, भाजपा ने परंपरागत सहयोगी छोड़ बनाए नए साथी

कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाए हुए है। कांग्रेस ने टिकट भी काफी सोच-विचारकर दिया है। सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी सहित कांग्रेस ने भी 40 स्टार प्रचाकरों को मैदान में उतार दिया है। क्षेत्रवार रणनीति तैयार की गई है। जाटों वाले इलाके में जाट प्रचार करेंगे तो पूर्वांचलियों के लिए अलग रणनीति बनाई गई है। वैसे आप ने सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह से घोषणाओं की घेराबंदी की है, भाजपा और कांग्रेस उसकी काट के तरीके तलाश रही है। इनकी कोशिश का असर कितना होता है यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल तीनों पार्टियां हर दांव-पेच आजमाने में लगी हैं।

दिल्ली में गठबंधन का चुनाव : सभी पार्टियां चाहती हैं कि दिल्ली की सत्ता में उनका प्रतिनिधित्व भी हो। इसके लिए कांग्रेस ने पहली बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को चार सीटें दी हैं। दिल्ली में बिहार की पार्टी पहली बार मैदान में कांग्रेस के साथ गठबंधन में उतरी है। बिहार की अन्य क्षेत्रीय पार्टी जदयू भी भाजपा के साथ गठबंधन में दिल्ली के चुनावी मैदान में है। भले ही जदयू को भाजपा ने दो ही सीट दी हों लेकिन साफ संकेत हैं कि पूर्वांचलियों को साधने के लिए वह हर कदम उठाने के लिए तैयार है। भाजपा ने एक सीट लोजपा को भी दी है। वैसे यहां यह बता दें कि बिहार की दोनों ही पार्टियों ने बिहार के गठबंधन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में गठबंधन की मांग रखी थी, जिसे भाजपा और कांग्रेस को मानना पड़ा। दूसरी तरफ वर्षों से चले आ रहे भाजपा-अकाली गठबंधन में छेद हो गया है। दिल्ली में इस बार अकाली दल चुनावी मैदान में नहीं उतरी।

शाहीन बाग में मुझे नहीं, शाह को जाने की जरूरत : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सीएए-एनआरसी के मुद्दे पर शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन की सियासत की जद में आप भी आ गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों के साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं, एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएए और एनआरसी खतरनाक हैं। इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए।

शाहीन बाग नहीं जाने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा, यदि मेरे जाने से सीएए वापस लिया जाता तो मैं जरूर चला जाता। उन्होंने कहा कि वहां गृहमंत्री अमित शाह को जाना चाहिए। शाह को वहां बैठे लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। इसके साथ ही केजरीवाल ने जोड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि देश में मंदी का दौर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इन पर बात होनी चाहिए। इनका रास्ता निकाला जाना चाहिए लेकिन यहां एनआरसी और सीएए पर बात हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन बिल की जरूरत क्या थी?

बता दें कि शाहीन बाग में बीते करीब डेढ़ माह से महिलाएं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) व नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं हैं। बीते डेढ़ माह से रास्ता बंद होने से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और अब इसमें आप भी कूद गई है।

बता दें कि एक कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वह शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। सिसोदिया के इस बयान पर भाजपा ने सवाल उठाया तो राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि इसमें सिसोदिया ने क्या नई बात कह दी है। उन्होंने इसे मुस्लिम महिलाओं से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिले से बीस बार कह चुके हैं कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे।

गारंटी कार्ड जारी करने वाले की क्या गारंटी : चोपड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के झूठे प्रचार के पांच साल बीते। उनके पिछले घोषणा पत्र के ज्यादातर वादे केवल कागजों में रहे और अब उन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए गारंटी कार्ड का ड्रामा किया है। सवाल यह है कि गारंटी कार्ड जारी करने वाले केजरीवाल की अपनी गारंटी क्या है? उन्होंने कहा था कि सुरक्षा नही लूंगा, सरकारी कार नहीं लूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा, नए कॉलेज खोलूंगा, क्या हुआ इन वादों का?

चोपड़ा राजेंद्र नगर में विधानसभा उम्मीदवार रॉकी तुसीद एवं बाबरपुर विधानसभा से पार्टी उम्मीदवार अन्वीक्षा त्रिपाठी जैन के चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जेएनयू और जामिया में पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर निहत्थे छात्रों की बेरहमी से पिटाई की और उन पर झूठे केस बनाकर थानों में बंद कर दिया। लेकिन केजरीवाल उन बच्चों से न मिलने गए और न ही उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया।

चुनावी हलचल

शिअद (बादल) से रमिंदर सिंह स्वीटा बाहर

नई दिल्ली : पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण शिरोमणि अकाली दल (शिअद) बादल ने रमिंदर सिंह स्वीटा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्वीटा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) के सदस्य व खरीद सब कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें इस पद से भी हटा दिया गया है। शिअद (बादल) दिल्ली इकाई के सरपरस्त अवतार सिंह हित और अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका की उपस्थिति में कार्यकारिणी समिति ने यह फैसला किया। कालका ने कहा कि कांग्रेस सिख विरोधी है। कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे में हजारों सिखों की हत्या की गई। उन्हें बेघर किया गया। अकाली दल ने शुरू से कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया है। वहीं, स्वीटा निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ जाकर मिल गए हैं। वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। इसे ध्यान में रखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। (जासं)

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में 39 मामले दर्ज

नई दिल्ली : मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय व संबंधित कार्यालयों की सख्ती के बावजूद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले रुक नहीं रहे हैं। इसी क्रम में 39 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में 275 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 266 मामलों में एफआइआर व नौ मामलों में डीडी एंट्री की गई है। ये सभी मामले चुनाव प्रचार के लिए बैनर-पोस्टर लगाकर संपत्तियों को बदरंग करने के आरोप से जुड़े हुए हैं। इनमें से 251 मामले गैर राजनीतिक लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जबकि तीन प्रमुख राजनीतिक दलों के खिलाफ (जासं)

चुनाव में दम दिखाएंगे दिल्ली के नए दबंग

नई दिल्ली : दिल्ली के सियासी दंगल में राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार हुंकार भरने लगे हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। इस सियासी दंगल में जीत-हार का फैसला करने वाले मतदाताओं में युवाओं की भूमिका अहम होगी। हाल के महीनों में 18 की दहलीज पार कर मतदान का अधिकार हासिल करने वाले नए दबंग भी अपना दम दिखाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनाव में नए युवा मतदाता करीब 62 हजार बढ़े हैं, जो इस बार पहली बार मतदान कर चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय भी युवाओं व नए मतदाताओं को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। (जासं)

झूठ बोलने में केजरीवाल नंबर वन : शाह

वार ▶ पांच साल पहले के वादे सीएम भले ही भूल चुके हों, जनता कभी नहीं भूल सकती

गृहमंत्री ने केंद्र की 112 योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं करने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप और कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने आधे घंटे के संबोधन में अनुच्छेद 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात जनता के सामने रखी। साथ ही कहा कि पांच साल पहले के वादे अरविंद केजरीवाल भले ही भूल चुके हों, लेकिन जनता कभी नहीं भूल सकती। केजरीवाल के कारण केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याण से जुड़ी 112 योजनाओं से आज दिल्ली की जनता वंचित है। केजरीवाल ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो उसमें वह नंबर वन होंगे।

अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने एक हजार विद्यालय व 20 नए कॉलेज बनाने की बात कही थी। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही थी। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आठ लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन नए रोजगार तो दूर की बात, जो लोग नौकरी में थे, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। शाह ने कहा कि अभी सभास्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल में कहीं भी मुफ्त वाई- फाई का सिग्नल नहीं पाया। इंतजार करते-करते मेरे मोबाइल की बैट्री खत्म हो गई पर मुफ्त वाई-फाई नहीं मिला।

शाह ने कहा कि अन्ना हजारे के जिस लोकपाल कानून को लागू करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, उसे वह कब का भूल चुके हैं। इसके विपरीत जिस लोकपाल कानून को नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया, उसे भी लागू नहीं होने दे रहे हैं। केंद्र सरकार जहां भी फ्लाईओवर बना रही है, वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार अड़चन डाल देती है। मुफ्त में पानी देने की बात दिल्ली सरकार करती है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा को निर्मल बना दिया। दिल्ली की जनता अगर भाजपा को मौका देगी तो यमुना को भी निर्मल बना देंगे।

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनी को नियमित कर दिया। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस कार्य में काफी अड़ंगे लगाए। केंद्र सरकार ने तीन

मटियाला विस क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। जागरण

बार अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने की फाइल दिल्ली सरकार के पास भेजी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इस बार हम लोगों ने बिना दिल्ली सरकार को फाइल भेजे ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया। नियमित होने के बाद सिर्फ पांच हजार रुपये में मकान की रजिस्ट्री हो जाएगी। पांच हजार में तो आजकल टेलीविजन भी नहीं खरीदा जा सकता है। दिल्ली सरकार आज आयुष्मान भारत योजना से यहां की जनता को वंचित रखे हुए है। सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने तय किया कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा तो कांग्रेस कह रही थी कि ऐसा करने से खूनखराबा होगा। लेकिन, एक बूंद खून गिरे बिना केंद्र सरकार ने कश्मीर को हमारे देश का मुकुटमणि बनाया और अनुच्छेद 370 को हटाया। इसी तरह कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन आने वाले चार महीने में अयोध्या में हम लोग भव्य राम मंदिर का भी निर्माण करेंगे। कांग्रेस वोट बैंक के कारण पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति जानती है। नागरिकता संशोधन कानून हो या तीन तलाक का मुद्दा कांग्रेस सिर्फ विरोध करती है। पाकिस्तान के नेता कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं।

गृह मंत्री ने जेएनयू प्रकरण पर कहा कि वहां कुछ लड़के भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भारत माता के टुकड़े करने की बात कहेगा, उसे हर हाल में जेल ही भेजा जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान व अन्य पड़ोसी देशों से आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध व इसाई शरणार्थी भारत में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को इससे भी एतराज है।

तीन विस क्षेत्रों में रोड शो कर मुख्यमंत्री ने मांगा समर्थन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पश्चिमी दिल्ली में राजनीतिक हस्तियों का पहुंचना जारी है। जनता से समर्थन मांगने के लिए विभिन्न दलों के नेता इलाके में पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो इलाके के तीन विधानसभा क्षेत्रों में करीब पांच घंटे तक चला। इस दौरान खुली जीप में विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से प्रत्याशी तो बदलते गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम हर जगह देखा गया।

मुख्यमंत्री ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र से रोड शो की शुरुआत की। सुबह आठ बजे से ही घासीपुरा में लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुरक्षा-व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किये गए थे। सुबह दस बजे जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे चारों ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर 'अच्छे बीते पांच साल, लगे रहे केजरीवाल' के नारे लगाने लगे। इसके बाद रोड शो की शुरुआत की गई। घासीपुरा के बाद प्रेम विहार मेन मार्केट, नंगली विहार, अर्जुन पार्क, बुध बाजार रोड से होते हुए रोड शो राणाजी एंक्लेव पहुंचा। रोड शो के दौरान लोग अपने घरों की छत पर आ गए थे। अरविंद केजरीवाल इस दौरान सभी से समर्थन देने की अपील करते नजर आए। इसके बाद रोड शो अर्जुन पार्क मेट्रो स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ। रोड शो के दौरान मटियाला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुलाब सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ खुली जीप में थे। मटियाला के बाद मुख्यमंत्री सीधे उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के लिए पहुंचे। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो की शुरुआत डीडीए फ्लैट बिंदापुर से हुई। यहां भी आप कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद था। चारों ओर आप के झंडे दिखाई दे रहे थे। रोड शो केशवराम पार्क, बिंदापुर जेजे कॉलोनी, ओल्ड जानकीपुरी, कुंभकार कॉलोनी, बिंदापुर मटियाला रोड से होते हुए वाणी विहार पहुंचा। इस दौरान लोग अपने घरों से मुख्यमंत्री पर फूलों की वर्षा करते नजर आए। इसके बाद शुक्र बाजार होते हुए नवादा मेट्रो स्टेशन पर रोड शो समाप्त हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश बाल्यान थे।

उत्तम नगर के बाद मुख्यमंत्री विकासपुरी पहुंचे और रोड शो में हिस्सा लिया। यह रोड शो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया। रोड शो जी-1, ए-1, ए-2, ए-3 से होते हुए गुरुद्वारा रोड, हस्तसाल रोड, कृष्णा कालोनी टी कैंप, हस्तसाल एलआइजी होते हुए विकासपुरी के कई ब्लॉक में पहुंचा। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। इस दौरान विकासपुरी से आप प्रत्याशी महेंद्र यादव मुख्यमंत्री के साथ थे।

बग्गा की पढ़ाई, सोशल मीडिया पर छाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

साइबर वार

दिल्ली विधानसभा चुनाव जितना जमीन पर लड़ा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा पार्टियां सोशल मीडिया पर ताकत झोके हुए हैं। शायद यही कारण है कि पार्टियां प्रतिद्वंद्वी दलों के प्रत्याशियों को ट्रोल करने में जुट गई हैं। इसकी एक बानगी गुरुवार को देखने को मिली। भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा से संबंधी हैशटैग अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। हैशटैग बग्गा समेत बग्गा जीतेगा, बग्गा हारेगा, बग्गा फॉर हरिनगर सरीखे हैशटैग से समर्थन व विरोध में जमकर ट्वीट किए गए। दरअसल, बग्गा चीन से किए गए एक डिप्लोमा कोर्स के चलते ट्रोलर के निशाने पर थे।

बग्गा ने हलफनामे में अपनी सभी जानकारियां दी हैं। इनमें उन पर किए गए सभी केस, उनकी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भी है। इसमें उन्होंने बताया है कि चीन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से 2017 में उन्होंने नेशनल डेवलेपमेंट कोर्स किया है। यह यूनिवर्सिटी ताइवान में मौजूद है। इस कोर्स में राष्ट्रीय विकास, पॉलिसी स्टडी, फॉरेन पॉलिसी समेत अन्य चीजों को लेकर पढ़ाया जाता है। इस दस्तावेज की फोटो ट्विटर पर अपलोड होने भर की देरी थी और उधर बग्गा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए। इनमें लोगों ने तंज कसा कि दिवाली के मौके पर चीन के सामान का विरोध करने वाले वहीं से पढ़ाई किए हैं। हालांकि, बग्गा ने सफाई में मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे डिप्लोमा पर सवाल उठाने वाले लोग खुद साक्षर हैं या नहीं। वे चीन और ताइवान के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं, जो हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ होते हैं। यह एक महीने का कोर्स था। मुझे ताइवान सरकार से नामांकन के लिए निमंत्रण मिला था। मैं कोर्स पूरा करने के लिए दिसंबर 2017 में एक महीने के लिए वहां रहा।

इस कोर्स के अलावा तेजिंदर बग्गा ने एक और कोर्स का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि वह नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर प्रीपेटरी प्रोग्राम कर रहे हैं। इग्नू की वेबसाइट के मुताबिक, यह कोर्स उन छात्रों को ऑफर किया जाता है, जो बैचलर करना चाहते हैं, लेकिन 10+2 पास आउट नहीं हैं।

कांग्रेस और आप एक ही सिक्के के दो पहलू : नड्डा

जासं, नई दिल्ली : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस व आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले कहते थे कि केंद्र सरकार उन्हें काम ही नहीं करने दे रही है। फिर अब क्यों कह रहे हैं कि अच्छे बीते पांच साल।

नड्डा महरौली से भाजपा प्रत्याशी कुसुम खत्री के समर्थन में किशनगढ़ में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर केजरीवाल व कांग्रेस के नेता वोट बैंक बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस ने जो समस्याएं नासूर की तरह खड़ी की थी, भाजपा ने सात माह में उनका समाधान कर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर आप लोगों से ज्यादा खुशी, वहां के लोगों में है। आप व कांग्रेस के लोग जम्मू-कश्मीर को लेकर हायतौबा मचाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू में घरेलू हिंसा, एंटी करप्शन व पॉक्सो समेत तमाम कानून लागू नहीं थे, लेकिन अब वहां देश का हर कानून लागू है। उन्होंने कहा कि गांधीजी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, उन्हें देश में लाकर नागरिकता दी जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए के जरिये लाखों लोगों को नागरिकता का हक दिया है।

नेशनल कैपिटल

नई दिल्ली में गुरुवार को गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मौके पर राजपथ पर भारत की शक्ति और शौर्य का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रिहर्सल के दौरान आकाश मिसाइलें लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। ध्रुव कुमार

फुल ड्रेस रिहर्सल में संस्कृति के साथ दिखा पराक्रम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : 71वें गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में देश की संस्कृति के साथ पराक्रम दिखा। राजपथ से लेकर लाल किले तक के इस परेड में इस बार 22 झांकियां देश में विविधता में एकता के सूत्र को परिभाषित कर रही थीं तो परेड में पहली बार शामिल चिनूक व अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) की महिला दस्ते के बाइक पर कारनामे ने लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया।

गुरुवार को रिहर्सल ठीक वैसे ही किया गया, जैसे 26 जनवरी को राजपथ पर परेड होगी। इसे देखने के लिए भोर से ही लोग राजपथ की ओर बढ़ चले थे। जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कई किलोमीटर पहले ही गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। लोगों ने उत्साह के साथ परेड को देखा। राज्यों की झांकियों में वहां की विशेषता के साथ संस्कृति और विकास के आयामों को उकेरा गया था। झांकियों के साथ नृत्य करता दल गुजर रहा था। बहादुर बच्चों, पूर्व सैनिकों, सैनिक पदकों से सम्मानित सैनिकों का दस्ता निकला।

नर्सरी दाखिले की आज जारी होगी पहली सूची

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली

नर्सरी दाखिले को लेकर शुक्रवार को पहली सूची आएगी। निजी स्कूलों को 17 जनवरी तक पंजीकृत बच्चों की सूची अंकों के साथ जारी करनी थी। हालांकि इस बीच कई निजी स्कूल अपनी सीटों को भरने के लिए जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिक्षा निदेशालय की सूची से पहले अपनी अलग सूची जारी कर दी और फोन करके अभिभावकों को जल्द से जल्द फीस भरने का दबाव बना रहे हैं।

एक्टिविस्ट व एडमिशन नर्सरी डॉट कॉम के प्रमुख सुमित वोहरा ने बताया कि कई स्कूल तो वेटिंग लिस्ट में भी इस कदर मनमानी कर रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले कर रहे हैं। इतना ही नहीं अभिभावकों से डोनेशन की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्वाइंट प्रणाली से लेकर सूची जारी करने और दाखिला लेने तक में स्कूल सिर्फ मनमानी कर रहे हैं। हालांकि शिक्षा निदेशक को इस संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।

अभिभावक इस बातों का रखें ध्यान

- सारे मूल दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
- जन्म प्रमाणपत्र की तीन से चार कॉपी रखें।
- कम से कम दो स्कूलों की फीस अपने पास तैयार रखें।
- स्कूल बच्चे का आधार कार्ड नहीं मांग सकते, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी।
- जिन स्कूलों ने सूची ऑनलाइन नहीं जारी की है और स्कूल के बाहर बोर्ड पर लगाई है, पहले वहां जाएं।
- दाखिला दिलाने में अगले साल का इंतजार न करें, क्योंकि बच्चे की उम्र में अपर एज कटऑफ लग चुका है।
- अगर आपको स्कूल के बाहर कोई डोनेशन लेकर दाखिला दिलाने को कह रहा है को साफ मना कर दें।

अभिभावकों ने आरोप लगाया कि किसी भी शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं की है। निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस भी स्कूल से शिकायत मिली है, उस जोन के उप शिक्षा निदेशक को कार्रवाई करने को कहा है।

प्रचार के रंग

विधानसभा चुनाव में अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह-तरह के तरीके अपना रही हैं

अब जादूगर भी करेंगे भाजपा का प्रचार

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में जैसे-जैसे तेजी आ रही है, इसके विभिन्न रंग दिख रहे हैं। भाजपा ने अपने प्रचार के लिए जादूगरों को जोड़ने का फैसला किया है। जल्द ही वे जादू शो के जरिये भाजपा का प्रचार करेंगे।

भाजपा नेताओं का कहना है कि अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए अलग-अलग माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। सड़कों पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अभियान चल रहा है। इसके साथ ही पारंपरिक प्रचार माध्यमों से भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी है। जादू भारत की पुरानी व लोकप्रिय कला है। इसलिए इसका उपयोग चुनाव प्रचार में करने का फैसला किया गया है। जादूगर अपनी कला के माध्यम से मोदी सरकार की उपलब्धियां को लोगों के सामने रखेंगे। मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों को भी जनता के सामने रखकर उन्हें इसका महत्व बताएंगे। जादूगर आप और कांग्रेस की पोल भी खोलेंगे।

प्रचार के लिए भोपाल से भी जादूगरों की टीम दिल्ली आई है। जादूगर प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर नेताओं के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर रहे नेता उन्हें अपनी जरूरत बताकर उसके अनुसार स्क्रिप्ट तैयार करने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें चुनाव आयोग के दिशानिर्देश की भी जानकारी दी जा रही है ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं हो। भाजपा नेताओं का कहना है कि बाजार, पर्यटन स्थल, मेट्रो स्टेशन व बस स्टॉप के आसपास जादू के शो आयोजित किए जाएंगे। आने वाले दिनों में प्रचार के कुछ और आकर्षक तरीके आजमाए जाएंगे।

चाय पर चर्चा के मुकाबले आप ने लांच की काम की चाय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा के चाय पर चर्चा कार्यक्रम को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने काम की चाय अभियान लांच किया है। इसमें अहमदाबाद के मशहूर चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लोरे अपने साथियों के साथ विधानसभा क्षेत्रों में चाय के स्टॉल लगाकर लोगों को चाय पिलाएंगे और केजरीवाल सरकार की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में जानकारी देंगे। आप कार्यालय में इन्होंने स्टॉल लगाया और अपनी चाय को स्वास्थ्य की चाय नाम दिया। पहले दिन करीब तीन हजार लोगों ने यहां मुफ्त चाय पी है। मूलरूप से अहमदाबाद निवासी प्रफुल्ल बिल्लोरे 'एमबीए चायवाला' के नाम से मशहूर हैं। प्रफुल्ल का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित होकर उन्होंने खुद उनके लिए मुफ्त में प्रचार करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 'एमबीए चाय वाला' स्टाल का उद्घाटन किया।

9280 शत्रु संपत्ति पाकिस्तानियों द्वारा, जबकि 126 शत्रु संपत्ति चीनी नागरिकों द्वारा भारत में छोड़ी गई हैं। 2 जनवरी 2018 को गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में यह जानकारी दी थी, जिनका कुल मूल्य एक लाख करोड़ रुपये है।

न्यूज गैलरी

भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी की जमानत पर फैसला आज

नई दिल्ली : भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व सीएमडी (मुख्य प्रबंध निदेशक) संजय सिंघल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। संजय सिंघल के वकीलों ने बहस के दौरान कहा कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में पूरा सहयोग किया है। जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, वह पेश हुए। इसके अलावा केस से संबंधित सभी दस्तावेज और साक्ष्य ईडी के कब्जे में हैं और अब सिंघल को न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। वहीं ईडी की शिकायत थी कि सिंघल ने जांच में सहयोग नहीं किया है। जांच जारी है, तो जमानत नहीं देनी चाहिए। (जासं)

एयर एशिया में अनियमितता पर ईडी से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली : एयर एशिया में विदेशी निवेश की मंजूरी दिए जाने में हुई अनियमितता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सीबीआइ की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने मामले में ईडी को पक्षकार बनाया और सील कवर में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी। राज्यसभा सदस्य सुब्रहमण्यम स्वामी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि एयर एशिया को विदेशी निवेश की मंजूरी दिए जाने में मनी लांड्रिंग हुई है। नियम की अनदेखी कर विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी दी गई है। (राब्यू)

कांग्रेस ने बेरोजगारी रजिस्टर के लिए शुरू किया अभियान

रणनीति ▸ सीएए, एनआरसी के जवाब में एनआरयू की उठाई मांग, युवा कांग्रेस को सौंपा अभियान का जिम्मा

राहुल गांधी भी आर्थिक मुद्दों और बेरोजगारी पर देशव्यापी अभियान 28 जनवरी को जयपुर से शुरू करेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सीएए, एनआरसी पर सरकार को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर (एनआरयू) लाने की मांग उठाई है। आर्थिक मंदी के साथ बढ़ती बेकारी पर सरकार की घेरेबंदी के लिए पार्टी ने अपनी युवा इकाई को देश में एनआरयू लाने की आवाज बुलंद करने का जिम्मा सौंपा है।

पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को युवा कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर लाने की मांग का अभियान शुरू किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वी, प्रवक्ता अंबरीश पांडेय और प्रभारी सचिव कृष्णा अलावरु ने यह अभियान शुरू किया। एनआरयू अभियान के लिए युवा कांग्रेस ने एक टोल-फ्री मोबाइल नंबर भी जारी किया जिस पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कुशल और अकुशल कामगारों से मिस्ड कॉल करने को कहा जाएगा।

अंबरीश पांडेय ने कहा कि मिस्ड कॉल में आने वाले सभी बेरोजगार लोगों की सूची सरकार को सौंपी जाएगी और प्रधानमंत्री से एनआरयू जल्द शुरू करने का अनुरोध किया जाएगा।

राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर लाने का यह अभियान पूरे बजट सत्र की समाप्ति तक चलाया जाएगा। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक मंदी और बेकारी के कारण रोजाना 36 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। मगर सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर ध्यान देने के बजाय सीएए, एनआरसी पर भटकाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए युवा आवाज उठा रहे हैं कि हमें एनआरसी नहीं बल्कि एनआरयू चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अलावरु ने कहा कि बेरोजगारी 45 साल के रिकार्ड स्तर पर है, तो आर्थिक हालत आइसीयू में जाने के करीब है और यह मोदी की बनाई आपदा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आर्थिक मुद्दों और बेरोजगारी पर सरकार की घेरेबंदी के लिए देशव्यापी अभियान 28 जनवरी को जयपुर से शुरू करेंगे। 30 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में भी इसी मुद्दे पर उनकी सभा व संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मार्च महीने तक पूरे देश में वह इस अभियान के तहत घूम-घूम कर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे।

'लोकतांत्रिक देशों की रैंकिंग में नीचे गिरना चिंताजनक'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चिदंबरम ने कहा, सत्ता में काबिज टुकड़े-टुकड़े गैंग लोकतंत्र को कर रहा कमजोर
- भय, प्रतिशोध, असहिष्णुता और एक रंग-विचार में रंगने की कोशिश से लोकतंत्र को पहुंचा गहरा आघात : सिंघवी

मजबूत लोकतंत्र की विश्व रैंकिंग में भारत के दस पायदान नीचे जाने को कांग्रेस ने चिंताजनक करार दिया है। पार्टी के अनुसार भय, असहिष्णुता, बदले की राजनीति और हमारी विविधता को एकरूपता में तब्दील करने के सरकार के प्रयासों ने हमारे लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे साफ है कि सत्ता में काबिज असल 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है और यह भारतीयों के लिए खतरे की घंटी है।

लोकतंत्र सूचकांक से जुड़ी एक वैश्विक रिपोर्ट में भारत के 41वें पायदान से 51वें स्थान पर लुढ़कने की आई ताजा रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर यह प्रहार किया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जहां लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार चार अहम कारण गिनाए वहीं पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने सत्ता में बैठे लोगों को असली 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' बताया। चिदंबरम ने कहा कि पिछले दो साल के घटनाक्रमों का आकलन करने वाले जानते हैं कि लोकतंत्र कमजोर तो हुआ ही है। साथ ही सत्ता में काबिज लोगों ने लोकतांत्रिक

अभिषेक मनु सिंघवी। फाइल

संस्थाओं का कद भी छोटा कर दिया है।

सिंघवी ने कहा कि 2006 में जब से यह सूचकांक शुरू हुआ है तब से भारत कभी इतने नीचे के पायदान पर नहीं गया था। हमारे गौरवशाली लोकतंत्र के लिए यह दुखदाई है क्योंकि विश्व के सबसे जीवंत और खुले लोकतंत्र भारत की तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि चार मानकों पर बीते साढ़े पांच साल में बदले हालात से साफ है कि लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। इसमें भय का माहौल पहला कारण है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के सहारे बाहर ही नहीं, अंदर के लोगों में भी डर पैदा किया गया है ताकि सच्चाई सामने न आए। असहिष्णुता दूसरी कसौटी है जिस पर सरकार और सत्ताधारी पार्टी का सभी को एक ही रंग में रंगने का प्रयास सबके सामने है। छात्रों से लेकर लोगों तक के विरोध की आवाज को दबाने के लिए धारा 144 का कानूनी सीमाओं से परे जाकर इस्तेमाल किया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार और सत्ताधारी पार्टी प्रतिशोध की भावना के नए मानक बना रही है। विपक्ष को प्रतिस्पर्धी नहीं, दुश्मन समझा जा रहा है और विपक्ष मुक्त भारत की बात कही जा रही। भारतीय लोकतंत्र में कभी ऐसी संस्कृति नहीं रही थी जहां सरकार और विपक्ष के नेता आपस में बैठक कर बातचीत न करें। देश की विविधता को एकरूपता में तब्दील करने के सरकार के प्रयासों को सिंघवी ने लोकतंत्र को कमजोर करने की चौथी कसौटी करार दिया। उन्होंने कहा कि खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, विचार-बोली आदि सभी एक ही तरह के हों ऐसे नजरिये एक जीवंत और खुले लोकतंत्र को मजबूत तो नहीं बनाते।

एनएसए लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय राजधानी और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस कानून के तहत पुलिस के पास किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 12 महीने तक हिरासत में रखने का अधिकार है।

अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने और प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए एनएसए लागू किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 10 जनवरी को एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस की हिरासत में लेने के अधिकार 19 जनवरी से तीन महीने के लिए बढ़ा दिए थे। शर्मा ने याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मणिपुर को भी पक्षकार बनाया है। अधिसूचना को असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है और इसे रद करने की मांग की गई है। यह घोषित करने की मांग भी की गई है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया जा सकता। इसके तहत हिरासत में लिए गए हर व्यक्ति के लिए 50-50 लाख रुपये हर्जाने की मांग की गई है।

ट्रंप को भी जवाब, कश्मीर पर तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं

प्रथम पृष्ठ से आगे

कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता करने की पेशकश को ठुकराते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मामले हैं उन्हें शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र के तहत द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है और उसे बातचीत के लिए आतंकवाद रोधी माहौल तैयार करना है। उल्लेखनीय है कि विगत मंगलवार को दावोस में इमरान खान से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि वह कश्मीर पर बहुत नजदीक से नजर रखे हुए हैं। साथ ही वह इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका चाहते हैं।

पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जेपीसी के पास भेजा गया

नई दिल्ली, आइएएनएस

बिल की समीक्षा

- मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति विचार कर देगी सुझाव
- आम लोगों, संगठनों और संस्थाओं से भी तीन हफ्ते में मांगे गए सुझाव

पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस बिल को लोकसभा में शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था। नई दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस बिल की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी।

लोकसभा सचिवालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है कि इस बिल पर व्यक्तियों, संगठनों और संबंधित संस्थाओं के विचार और सुझाव लेने का फैसला किया गया है। इस बिल को लेकर कोई भी अपना विचार और सुझाव तीन हफ्ते के भीतर दे सकता है। इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में लिखित ज्ञापन और सुझाव लोकसभा सचिवालय के निदेशक को भेजा जा सकता है।

बयान में कहा गया है कि संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए ज्ञापन को रिकॉर्ड में और गोपनीय रखा जाएगा। ज्ञापन देने के साथ ही अगर कोई संयुक्त संसदीय समिति के सामने उपस्थिति होकर अपनी बात भी रखना चाहता है तो इसके लिए विशेष अनुरोध करना होगा। हालांकि, इस मामले में समिति जो भी फैसला लेगी उसे अंतिम माना जाएगा।

बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को 11 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। इस बिल के जरिए फेसबुक, गूगल और अन्य कंपनियों के लिए लोगों के निजी और गैर निजी डाटा को गुप्त रखना अनिवार्य बनाया गया है। बिना अनुमति डाटा का इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

पुरस्कार विजेता बच्चों से आज मिलेंगे मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' के विजेता बच्चों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1730 आदिवासी कलाकारों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) के सदस्यों और उन कलाकारों से भी मुलाकात करेंगे जो गणतंत्र दिवस पर 'एटहोम' कार्यक्रम में भाग लेंगे।

आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार 49 पुरस्कार विजेताओं में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग हैं। खासकर जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से एक-एक व्यक्ति को अवार्ड मिला है। यह अवार्ड बच्चों को कला-संस्कृति, शोध, समाजसेवा, खेल और बहादुरी के क्षेत्र में मिला है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विगत बुधवार को इन बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दे चुके हैं। अब इन बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार बच्चों को राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम साझीदार मानती है। उनकी उम्मीदों मान्यता और उपलब्धियों पर पुरस्कार दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री से मिले नड्डा

भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार जेपी नड्डा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नड्डा ने बाद में कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। उनके मार्गदर्शन के साथ वह निरंतर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। एएनआइ

पहली बार दिल्ली में दिखेगी कोलकाता पोर्ट की झांकी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- पीएम ने किया था नाम बदलने का एलान पर झांकी में अब भी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
- गौरवशाली अतीत, उज्ज्वल भविष्य की टैग लाइन, हावड़ा ब्रिज, क्लॉक टावर भी आएगा नजर

गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल बंगाल की झांकी नजर नहीं आएगी, लेकिन परेड के दौरान जहाजरानी मंत्रालय की झांकी में 150 वर्षीय कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) की झलक पहली बार दिखेगी। इससे पहले बंगाल सरकार लड़कियों के लिए चलाई जाने वाली योजना कन्याश्री को गणतंत्र दिवस परेड में दिखाना चाहती थी, लेकिन झांकी के प्रस्ताव को चयन करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने खारिज कर दिया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुनी गई 22 झांकियों में 16 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकी होगी और छह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की होगी।

काम करते नजर आएंगे मजदूर : गणतंत्र दिवस परेड में केपीटी की झांकी में श्रम व इंजीनियरिंग के नायाब नमूने के तौर पर कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले रवींद्र सेतु (हावड़ा ब्रिज) की पृष्ठभूमि में साइट पर काम करते मजदूर नजर आएंगे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का ऐतिहासिक क्लॉक टावर भी नजर आएगा। झांकी के आगे में हिंदी और अंग्रेजी में 'कोलकाता पत्तन न्यास' लिखा होगा। साथ में 150 वर्ष - गौरवशाली अतीत, उज्ज्वल भविष्य' की टैग लाइन भी होगी। जहाजरानी मंत्रालय की झांकी 22 झांकियों में से एक होगी।

पीएम के एलान के बाद भी झांकी में नहीं बदला नाम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नामकरण भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम करने की घोषणा की थी। परंतु, देखा जा रहा है कि झांकी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नाम लिखा ही दिख रहा है। नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट नहीं है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने को लेकर विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार की आलोचना भी की जा रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसके खिलाफ में बीते दिनों विरोध जुलूस निकाला गया। वहीं, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की ट्रेड यूनियनों ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि इस कदम से संगठन के इतिहास को नुकसान पहुंचेगा।

भ्रष्टाचार के मामले में भारत 80वें स्थान पर

दावोस, प्रेट्र : दुनिया के 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का स्थान 80वां है। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआइ) में ये नतीजे सामने आए हैं। विशेषज्ञों और बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में जारी सीपीआइ की रिपोर्ट में 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग उनके यहां सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर तय की गई है। इस सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीष पर बने हुई हैं। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विटजरलैंड का स्थान है। सातवें स्थान पर नॉर्वे, आठवें पर नीदरलैंड और नौवें स्थान पर जर्मनी और लग्जमबर्ग हैं। भारत 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है। भारत के साथ ही इस स्थान पर चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को भी बने हुए हैं। पड़ोसी पाकिस्तान 120वें स्थान पर है। अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति ठीक तो है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले वह दो पायदान नीचे फिसल गया है। पिछले साल भारत 78वें स्थान पर था। ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि जिन देशों में चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसे का इस्तेमाल होता है और जहां सरकारें अमीर व रसूखदार लोगों की ही सुनती है वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है।

उत्तराखंड के डीएमएमसी को आपदा प्रबंधन पुरस्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- डीएमएमसी ने उत्तराखंड त्रासदी के दौरान निभाई थी अहम भूमिका
- मिला 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

उत्तराखंड त्रासदी के समय राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र (डीएमएमसी) को 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) को तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले कुमार मुन्नन सिंह को भी निजी वर्ग में यह पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि मोदी सरकार ने पिछले साल ही आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। उनकी जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2006 में स्थापित डीएमएमसी ने उत्तराखंड में जिला और तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन का तंत्र खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। यह संस्थान आपदा प्रबंधन में अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी जुटा है और बहुत सारे छात्र इसमें आपदा प्रबंधन पर अनुसंधान कर रहे हैं। यही कारण है कि इस संस्थान में हुए अनुसंधान से 50 से अधिक पेपर विभिन्न वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इस संस्थान द्वारा आपदा राहत पर बनाई गई फिल्म 'द साइलेंट हीरो' 200 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और काफी सराही भी गई है।

वही, निजी वर्ग में पुरस्कार पाने वाले कुमार मुन्नन सिंह ने 2004 में सुनामी के दौरान राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्हें 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का संस्थापक सदस्य नियुक्त किया गया था। इस पद रहते हुए उन्होंने एनडीआरएफ की स्थापना और उसे राहत व बचाव कार्यों के लिए एक दक्ष बल के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी।

राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा पर सुनवाई तीन महीने बाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर तीन महीने बाद विचार करेगा।

राम सेतु भारत और श्रीलंका के तटों के बीच चूनापत्थरों से बना एक पुल है। रामायण महाकाव्य के मुताबिक लंकापति रावण जब माता सीता को हरण कर अपने देश ले गया था, तब लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु का निर्माण वानर सेना ने किया था।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने स्वामी की याचिका पर गौर करने के बाद कहा कि आप इसे तीन महीने बाद मेंशन करें तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। स्वामी ने पीठ से मामले पर जल्द सुनवाई की अपील की थी।

स्वामी ने कहा कि वह इस मामले में पहले चरण की लड़ाई जीत चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2017 में केंद्रीय मंत्री ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। लेकिन

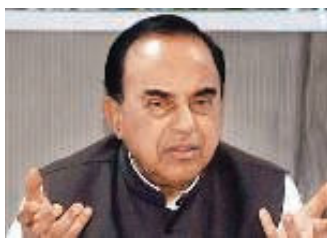

सुब्रमण्यम स्वामी। फाइल

- सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से तीन महीने बाद आने को कहा
- भाजपा नेता ने की है केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग

उसके बाद इस मामले में कुछ नहीं हुआ।

शीर्ष अदालत ने उसके समक्ष लंबित ढेरों मामलों को हवाला देते हुए स्वामी से अपनी याचिका तीन महीने बाद लगाने को कहा। यूपीए-एक की सरकार द्वारा शुरू किए गए सेतुसमुंद्रम जहाज मार्ग प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर अपनी याचिका में भी स्वामी ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की थी। यह मामला 2007 में सुप्रीम कोर्ट में आया था और कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी।

आश्वासन

पहले रेलवे के पास देश भर में कुल 14 प्रिंटिंग प्रेस थीं, जिनमें 9 बंद हो चुकी हैं, पिछले वर्ष जून में रेलवे बोर्ड ने बाकी पांच प्रेसों को भी मार्च 2020 तक बंद करने का निर्णय ले लिया था

नहीं बंद होंगी अब रेलवे की बाकी पांच प्रिंटिंग प्रेस : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने की योजना अब रुक गई है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने यूनियनों को इस बात का भरोसा दिया है। यूनियनों ने बाकी बची पांच प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने के मंत्रालय के प्रस्ताव पर ऐतराज जताते हुए इन्हें रेलवे के लिए अति आवश्यक बताया था।

पहले रेलवे के पास देश भर में कुल 14 प्रिंटिंग प्रेस थीं। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इनमें से नौ प्रिंटिंग प्रेसों को गैर जरूरी मानते हुए बंद करने तथा केवल पांच प्रिंटिंग प्रेसों को बनाए रखने का फैसला किया था। पिछले वर्ष जून में रेलवे बोर्ड ने बाकी पांच प्रेसों को भी मार्च 2020 तक बंद करने का निर्णय ले लिया था। हाल में संपन्न हुई रेलवे की परिवर्तन संगोष्ठी में भी इन प्रेसों को जल्द से जल्द बंद करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन पिछले दिनों यूनियनों ने रेलमंत्री पीयूष गोयल से मिलकर इस पर कड़ा ऐतराज जताया और फैसले के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। रेलवे की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) ने रेलमंत्री से कहा कि यदि इन प्रिंटिंग प्रेसों को भी बंद किया गया तो आपात स्थिति में रेलवे को टिकटों तथा अन्य सामग्री की छपाई के लिए पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे आपात परिस्थितियों में संकट खड़ा हो सकता है। ये प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, चेन्नई तथा सिकंदराबाद में स्थित हैं।

एआइआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार, ये पांचों प्रिंटिंग प्रेस अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनके आधुनिकीकरण पर पिछले वर्षों में काफी पैसा खर्च किया जा चुका है। इनमें रेलवे टिकटों के अलावा मनी वैल्यू बुक्स, रेलवे ऑपरेशन एवं सेफ्टी से जुड़े फॉर्मों, रसीदों और पुस्तिकाओं की छपाई होती है। इनमें रेल टिकटों की छपाई केवल 11 पैसे प्रति टिकट की लागत पर होती है, जबकि निजी क्षेत्र में लागत इससे ज्यादा है। डिजिटाइजेशन, ई-टिकटिंग व मोबाइल टिकटिंग के बावजूद अभी भी हर साल लगभग 20 करोड़ आरक्षित (पीआरएस) तथा 300 करोड़ अनारक्षित टिकटों का उपयोग रेलवे में हो रहा है और अगले कई वर्षों तक इस स्थिति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है।

पूर्व तटीय रेलवे ने स्थापित किया पहला कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व तटीय रेलवे ने सरकार का पहला कचरे से ईंधन बनानेवाला प्लांट स्थापित किया है। यह प्लांट इलेक्ट्रानिक कचरे और प्लास्टिक को 24 घंटे में हल्के डीजल में बदल देगा। गुरुवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पेटेंट कराई गई इस तकनीक को पोलीक्रैक के नाम से जाना जाता है। तकनीक का इस्तेमाल इस कचरे से ऊर्जा प्लांट में किया जाएगा। यह रेलवे में अपनी तरह का पहला और देश में चौथा प्लांट है।

पूर्व तटीय रेलवे के प्रवक्ता जेपी मिश्रा ने कहा, 'यह दुनिया की पहली पेटेंट कराई गई हेटेरोजेनॉस कैटेलाइटिक प्रक्रिया है जो डाले गए विभिन्न प्रकार के कचरे को हाइड्रोकार्बन तरल ईंधनों, गैस, कार्बन और पानी में बदल देती है। इससे पहले डिब्बा मरम्मती कार्यशाला से बड़ी मात्रा में अलौह रद्दी निकलती थी। निस्तारण का कोई प्रभावी उपाय नहीं होने से उन्हें खाली जगह में फेंक दिया जाता था। ऐसा कचरा पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव डालता था।'

मिश्रा ने कहा कि इस प्रक्रिया में मशीन में डालने से पहले कचरे को चुनकर अलग करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा, 'इसमें नमी सोखने की उच्च क्षमता है, इसलिए कचरे को सुखाने की जरूरत नहीं होगी। 24 घंटे में कचरे के प्रसंस्करण का काम पूरा हो जाएगा। चूंकि यह एक बंद इकाई है, इसलिए धूल उड़ने की गुंजाइश नहीं है। कचरा प्राप्त होते ही इस्तेमाल होने से सड़ने का खतरा भी नहीं है।'

कह के रहेंगे

माधव जोशी

13 मई 1952 को आयोजित हुआ था राज्यसभा का पहला सत्र। जुलाई 2018 से नियमों में बदलाव के बाद से राज्यसभा सदस्य सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण दे सकते हैं क्योंकि ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 24 जनवरी 2020

राज्यों में कितनी जरूरी द्विसदनीय व्यवस्था

आंध्रप्रदेश विधानसभा में सत्ताधारी वाइएसआर कांग्रेस ने तीन राजधानियां बनाने के प्रस्ताव को प्रचंड बहुमत (175 में से 151 सीटें) के चलते निम्न सदन से पारित तो करा लिया लेकिन इसे विधान परिषद (विधान मंडल का उच्च सदन) ने अस्थायी रूप से रोक दिया है। विधानसभा में जहां जगनमोहन रेड्डी सरकार बहुमत में हैं। वहीं विधान परिषद में मुख्य विपक्षी पार्टी तेलगुदेशम के पास 58 में से 28 सीटें हैं। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार उच्च सदन को ही खत्म करने पर विचार कर रही है। दूसरी ओर, देश के चार बड़े राज्य ओडिशा, राजस्थान, असम और मध्यप्रदेश उच्च सदन स्थापित करने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्यों के लिए कितने सदन वाली व्यवस्था बेहतर है और इनकी मौजूदा दौर में कितनी प्रासंगिकता है।

यहां हैं उच्च सदन

संसद में लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही संविधान ने राज्यों को द्विसदनीय व्यवस्था का अधिकार दिया है। यद्यपि छह राज्यों में ही उच्च सदन की व्यवस्था है। इनमें आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की एक तिहाई से ज्यादा और चालीस से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की तरह इसके सदस्य सीधे विधायकों या स्थायी निकायों द्वारा चुने जाते हैं अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

पक्ष-विपक्ष के तर्क

उच्च सदन के पक्ष में रहने वालों का तर्क है कि इसके अस्तित्व में आने से बेहतर बहस हो सकेगी और बहुमत की सरकारों के जल्दबाजी में लिए निर्णयों को जांचा जा सकेगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि यह व्यवस्था मनोनीत पेशेवरों को विधान प्रकिया से जुड़ने की आज्ञा देती है। यद्यपि जो लोग दूसरे सदन के विरोध में हैं वो अक्सर तर्क देते हैं कि इससे कानून बनने में देरी होती है। इस सदन को राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है जो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। साथ ही यह सरकारी कोष की बर्बादी है।

संसद के पास अधिकार

संसद के पास राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्त करने का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानसभा दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित कर केंद्र को भेजती है। आंध्रप्रदेश में 1958 से उच्च सदन है, इसे 1985 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसे एक बार फिर 2007 में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान और असम के विधान परिषद गठन के प्रस्ताव संसद में अटके हुए हैं।

स्थायी सदन है विधान परिषद

राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद स्थायी सदन है। इसके सदस्यों में से एक तिहाई हर दो साल की अवधि में कार्यमुक्त हो जाते हैं। यद्यपि विधानसभाओं को इनके सुझावों को न मानने का अधिकार होता है।

करोड़ों का बजट

ओडिशा ने प्रस्तावित उच्च सदन के लिए वार्षिक करीब 35 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने एकमुश्त 100 करोड़ रुपये और असम ने 19 करोड़ रुपये वार्षिक के साथ ही 69 करोड़ का खर्चा बताया है।

आंध्रप्रदेश की तीन राजधानियां

आंध्रप्रदेश विधानसभा ने तीन राजधानियां बनाने का प्रस्ताव किया है। दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर विशाखापत्तनम को कार्यकारी, अमरावती को विधायी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में प्रीटोरिया कार्यकारी, केपटाउन विधायी और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। वाइएसआर कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ एक बड़ी राजधानी बनाने का अर्थ दूसरे हिस्सों को नजरअंदाज करना है।

न्यूज गैलरी

आंध्र सरकार ने दिया विधान परिषद खत्म करने का संकेत

अमरावती : आंध्र प्रदेश के लिए तीन राजधानी बनाने से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विधान परिषद में मात खाने के बाद राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह उच्च सदन को खत्म कर सकती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या ऐसा सदन होना चाहिए, जो केवल राजनीतिक मंशा के साथ काम करता है? उन्होंने कहा कि विधान परिषद होना कोई अनिवार्य नहीं है। यह हमारा ही बनाया हुआ है और केवल हमारी सुविधा के लिए है। इसलिए हमें सोमवार को आगे इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और फैसला लेना चाहिए कि विधान परिषद को जारी रखना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री बुधवार को विधान परिषद में जो कुछ हुआ, उस पर विधान सभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे। (प्रेट्र)

राजद ने फिर लगाए पोस्टर, लिखा, ट्रबल इंजन की सरकार

पटना : बिहार में पोस्टर वार का सिलसिला जारी है। राजद की ओर से राजधानी में भाजपा एवं जदयू पर कटाक्ष करते हुए फिर पोस्टर लगाए गए हैं। राजद कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया गया है। केंद्र और राज्य में भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार को डबल इंजन के बदले ट्रबल इंजन लिखा गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की भी तस्वीर लगाई गई है, जिसपर झूठ एक्सप्रेस और लूट एक्सप्रेस लिखा गया है। इससे पहले भी दोनों दलों की ओर से कई पोस्टर चिपकाए जा चुके हैं। दोनों ओर से एक दूसरे के शासनकाल की पोल खोलने वाले पोस्टरों में कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप हैं। (राब्यू)

राज ठाकरे ने बदला झंडा, बेटे को राजनीति में उतारा

बदले कलेवर ▶ 14 साल पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के गठन के समय बहुरंगी था पार्टी का झंडा

अब भगवा रंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर का चित्र होगा

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के मुखिया राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का झंडा बदलकर हिंदुत्व का रंग गाढ़ा करने का संकेत दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुत्र अमित ठाकरे को भी राजनीति में उतार दिया है।

राज ठाकरे ने 14 साल पहले जब शिवसेना से अलग होकर मनसे का गठन किया तो अपने झंडे को बहुरंगी स्वरूप दिया था। उसमें नीला, हरा एवं भगवा रंग की पट्टियों पर चुनाव चिह्न रेल का इंजन शामिल किया था। लेकिन अब उनकी पार्टी के झंडे में भगवा रंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर का चित्र होगा। साथ ही नीचे कत्थई रंग की पट्टी पर पार्टी का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लिखा होगा। यही नहीं, गुरुवार को पहली बार उनके मंच पर विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा भी नजर आई। इससे पहले उनके मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अर्धप्रतिमा के बगल में डॉ. भीमराव आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनके दादा प्रबोधनकार ठाकरे की तस्वीरें हुआ करती थीं। माना जा रहा है कि राज ठाकरे ने अपनी रणनीति में यह परिवर्तन विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में आए बदलाव को देखते हुए किया है।

पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हिंदुत्व का झंडाबरदार समझी जानेवाली शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार बना ली है। इससे शिवसेना के कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं। जिन दलों के खिलाफ वे पिछले 30 वर्षों से संघर्ष करते आए, आज उन्हीं दलों के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं। राज ठाकरे को लगता है कि इस स्थिति में वह यदि अपनी छवि हिंदुत्ववादी नेता की बनाते हैं, तो शिवसेना से छिटके कार्यकर्ता उनके साथ आ सकते हैं। सावरकर की प्रतिमा को मंच पर पहली बार स्थापित करना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस द्वारा सावरकर की लगातार आलोचना के बावजूद शिवसेना वैसी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पा रही है, जैसी कि लोग उससे अपेक्षा करते हैं। 14 साल पहले मनसे की स्थापना के समय राज ठाकरे ने मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए ही अपने झंडे में हरे रंग की पट्टी को स्थान दिया था।

राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को भी पार्टी में शामिल कर राजनीति में आगे बढ़ाने का संकेत दे दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके चचेरे बड़े भाई उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे चुनाव लड़कर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता में राज अपने पुत्र अमित को पीछे नहीं रहने देना चाहते। कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की राजनीति में किसी न किसी स्तर पर मनसे का तालमेल भाजपा के साथ हो सकता है। इसकी शुरुआत स्थानीय निकाय चुनावों से हो सकती है।

महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना(मनसे) के मुखिया राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे राजनीति के मैदान में कूद पड़े। मुंबई में गुरुवार को आयोजित समारोह के दौरान तलवार उठाए अमित। एएनआइ

महाराष्ट्र नवनिर्वाण सेना(मनसे) के मुखिया राज ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी का नया झंडा लांच किया। एएनआइ

अल्पसंख्यक शिवसेना के खिलाफ नहीं : पवार

मुंबई, प्रेट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने उनसे कहा था कि अगर उनकी पार्टी शिवसेना से हाथ मिला ले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाना चाहिए।

पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव शिवसेना और भाजपा साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पाने पर दोनों पार्टियां अलग हो गई थीं। राकांपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में सरकार गठन को लेकर चले गतिरोध का जिक्र करते हुए पवार ने कहा कि तीन-चार हफ्तों तक (शिवसेना-भाजपा द्वारा) सरकार बनाने की दिशा में कोई कदम ही नहीं उठाया जा रहा था। इसके बाद शिवसेना के साथ संभावित गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों से सुझाव लिए गए। पवार ने कहा, 'अल्पसंख्यकों की ओर से हमें बताया गया कि अगर आप शिवसेना को साथ लेना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन भाजपा को दूर रखो।

शरद पवार। फाइल

अल्पसंख्यकों ने उस कदम (शिवसेना से बातचीत) का स्वागत किया था।' पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटनाक्रम ने देश को रास्ता दिखाया है और उन्होंने इस पहल के लिए समुदाय की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि राज्य विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। जब समुदाय के सदस्य फैसला करते हैं तो किसी पार्टी की हार सुनिश्चित करते हैं। पवार ने कहा कि राकांपा ने जोर देकर राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग मांगा था ताकि समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा सकें। मालूम हो कि राकांपा नेता नवाब मलिक राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं।

मुंबई के 'उत्तर प्रदेश दिवस' में शामिल होंगे उप्र के कई हैवीवेट नेता

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई : मुंबई में शुक्रवार को मनाए जाने वाले 'उत्तर प्रदेश दिवस समारोह' में इस बार यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस एवं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल आदि उपस्थित रहेंगे। पिछली बार इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया था।

उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश दिवस' दो वर्ष पहले मनाना शुरू किया गया, लेकिन मुंबई में उत्तर प्रदेश मूल के लोग पिछले 32 वर्षों से उत्तर प्रदेश दिवस धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान प्रदर्शित करने वाला समारोह बन चुका है, बल्कि चुनावी वर्षों में शक्ति प्रदर्शन का माध्यम भी बन जाता है। इस समारोह के जरिये नेता मुंबई की आबादी में करीब 40 फीसद हिंदी भाषियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का मौका नहीं छोड़ते।

अभियान के संयोजक मुंबई भाजपा के महासचिव अमरजीत मिश्र ने बताया कि आजादी मिलने के बाद तक उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रॉविंस आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। यह नाम लंबा था, इसलिए संक्षेप में इसे यूनाइटेड प्रॉविंस या यूपी ही कहा जाता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके संक्षिप्त नाम 'यूपी' से प्रेम था, इसलिए इसका नाम बदलते समय भी यूपी शब्द को बरकार रखा और इस प्रदेश का नया नामकरण उत्तर प्रदेश (यूपी) हुआ। नए नाम का गजट 24 जनवरी, 1950 को जारी हुआ, इसलिए अभियान संस्था इसी तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है। मुंबई में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की शुरुआत हमेशा महाराष्ट्र गीत 'जय जय महाराष्ट्र माझा' से होती है। उत्तर प्रदेश में 'उत्तर प्रदेश दिवस' के आयोजन का श्रेय वहां के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को जाता है।

जेल से निकलते ही 2017 के मामले में गिरफ्तार हुए हार्दिक पटेल

अहमदाबाद, प्रेट्र : कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को जैसे ही साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर निकले, गांधीनगर जिले की पुलिस ने 2017 के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले कांग्रेस नेता को देशद्रोह के मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी। 2015 के मामले में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने के कारण हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया था।

हार्दिक पटेल। फाइल

अहमदाबाद में एक स्थानीय कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी के चार दिनों बाद जमानत दे दी। गुरुवार को जेल से बाहर आते ही गांधीनगर जिले की मनसा तहसील पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 2017 में दर्ज एक एफआइआर के सिलसिले में की गई है। पुलिस से अनुमति लिए बगैर सभा को संबोधित करने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गई थी। मनसा के इंस्पेक्टर एसएस पवार ने कहा कि एफआइआर तो तब दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी आज की गई है।

आजम के जौहर विवि पर कार्रवाई 26 किसानों को मिला कब्जा

जागरण संवाददाता, रामपुर

सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने गुरुवार को भी बड़ी कार्रवाई की। 26 किसानों को यूनिवर्सिटी में शामिल की गई जमीन पर कब्जा दिला दिया गया।

एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी गुरुवार दोपहर राजस्व टीम के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे और पैमाइश कराकर किसानों को कब्जा दिलाया। पैमाइश की प्रकिया शाम तक चली। इस दौरान लेखपालों के साथ किसान भी मौजूद रहे। इन किसानों ने जमीन पर कब्जा करने के आरोप में आजम पर मुकदमे कराए थे। एसडीएम ने बताया कि इन किसानों की करीब 20 बीघा जमीन है, जो बिना रजिस्ट्री के जबरन यूनिवर्सिटी के अंदर कर ली गई थी। सभी किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा दिला दिया गया है।

तब भूमाफिया घोषित हुए थे आजम : एसडीएम तिवारी ने बताया कि आलियागंज के 26 किसानों ने जुलाई 2019 में जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह को शपथ पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम ने सपा शासनकाल में उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली। विरोध करने पर तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खां ने उन्हें डराया धमकाया और हवालात में बंद किया। इन शपथ पत्रों की जांच कराने के बाद 12 जुलाई 2019 को प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद आलियागंज के उन सभी 26 किसानों ने अजीमनगर थाने में अलग-अलग तहरीर देकर रिपोर्ट कराई। 18 जुलाई को एसडीएम की ओर से आजम का नाम एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया। इस पर उन्हीं लोगों के नाम दर्ज कराए जाते हैं, जो जमीन पर कब्जा करते हैं।

आजम खां। फाइल

सरकार ने भी लिया है 104 बीघा जमीन पर कब्जा : प्रशासन ने बुधवार को भी यूनिवर्सिटी की 104 बीघा जमीन को कब्जे में ले लिया था। जमीन 10 अनुसूचित जातियों से डीएम की अनुमति लिए बिना खरीदी गई थी। नियमानुसार अनुसूचित जातियों की जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी है।

'महाराष्ट्र सरकार के विज्ञापनों में पीएम का फोटो अवश्य लगे'

मुंबई, प्रेट्र : वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार के सभी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

गुरुवार को लिखे इस पत्र में फड़नवीस ने कहा है कि राज्य सरकार के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री के फोटो नहीं लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 मई, 2015 और 18 मार्च, 2016 के आदेश में सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री का फोटो प्रकाशित करने के बारे में उल्लेख किया था। शीर्ष अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने भी 11 अगस्त, 2017 को सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो लगाने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया था।

फड़नवीस का कहना है कि 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना' से जुड़े विज्ञापनों में इस सर्कुलर का उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री का फोटो लगाया गया है जबकि यह योजना पूरी तरह केंद्र पोषित है।

नीतीश कुमार की पवन को दो टूक- जहां जाना हैं जाएं, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं

राज्य ब्यूरो, पटना

जदयू के पूर्व राज्यसभा सदस्य पवन वर्मा को जदयू ने नमस्कार कर लिया है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) पर लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे पवन वर्मा पर नीतीश कुमार ने दो टूक अंदाज में गुरुवार को कहा कि उन्हें जहां जाना हैं जाएं, मेरी शुभकामना है उन्हें। पवन वर्मा लगातार सीएए और एनआरसी के मसले पर जिस तरह से जदयू पर हमलावर थे उससे जदयू के भीतर इस मसले पर द्वंद्व की बात कही जा रही थी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पवन वर्मा को नसीहत देते हुए साफ कर दिया कि जदयू के भीतर सीएए पर किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं। पार्टी के किसी नेता का कोई वक्तव्य दल का आधिकारिक वक्तव्य नहीं हो सकता।

सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गांधी मैदान के समीप सुभाष प्रतिमा स्थल परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री ने काफी तल्ख अंदाज में पवन वर्मा पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर उनके मन में कुछ था तो आकर विमर्श करना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे कि हमसे क्या बात होती थी। अब हम कहेंगे क्या कि हमसे उनकी क्या-क्या बात हो होती थी? यह कोई तरीका है क्या? इसके बाद भी मेरे मन में उनके प्रति इज्जत है।

नीतीश कुमार और पवन वर्मा की फाइल फोटो।

> जदयू में दो तरह के लोग हैं। एक जो मेहनत कर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। दूसरे अनुकंपा वाले हैं। पार्टी में पद पाते हैं, अनाप-शनाप बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों के रहने न रहने से पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता है।
>
> **-आरसीपी सिंह, सांसद और राष्ट्रीय महासचिव, जदयू**

आइएफएस से राजनीति का सफर : जदयू के महासचिव रह चुके पवन वर्मा भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) के पूर्व अधिकारी रहे हैं। 2013 में सेवानिवृत्त हुए। नीतीश कुमार के सलाहकार भी रह चुके वर्मा अब तक कई किताबें लिख चुके हैं, जिनमें से कुछ बेहद चर्चित रही हैं। लंदन में नेहरू सेंटर में प्रतिष्ठित वार्षिक नेहरू मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन किया। वह गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के संयोजक भी हैं। कूटनीति, साहित्य, संस्कृति और सौंदर्यशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए पवन को 2005 में इंडियानापोलिस विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की मानद उपाधि दे चुका है। दिसंबर 2012 में भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, (ड्रक ठुक्से) से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। 2006 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ, कोलकाता) उन्हें सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड से प्रदान कर चुका है।

संभाल चुके हैं कई पद : 2001 से 2004 तक साइप्रस में भारतीय उच्चायुक्त रहे। 2005 से 2009 तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक भी रहे। 2009 से 2013 तक भूटान में भारत के राजदूत रहे। 2014 से 2016 तक बिहार से राज्यसभा सदस्य रहे।

बदला रुख

राहुल की हार के बाद था पहला दौरा, टीस न छिपा सका मां का दिल, न कहीं ठहराव और न अभिवादन, सिर्फ गमगीन परिवारों से मुलाकात कर लौटीं

रूठी अमेठी में सोनिया गांधी भी नजर आई अनमनी सी

जितेंद्र शर्मा, रायबरेली

कारवां गुजर गया और अमेठी के बाशिंदे गुबार देखते रह गए। गुबार दिखा रहा था कि राजनीतिक रिश्तों की डोर कितनी कमजोर होती है। पिछले कई दशकों से नेहरू-गांधी परिवार का जो मजबूत रिश्ता इस धरती से बना, वह राहुल गांधी की एक हार से यूं बिखर गया, जिसे सहेजने की तड़प न बतौर पार्टी अध्यक्ष मां सोनिया गांधी में दिखी और न ही महासचिव बहन प्रियंका वाड्रा में। पिछले दिनों हादसे में मारे गए ग्रामीणों के परिजनों से मुलाकात को छोड़ दें तो रूठी अमेठी में सोनिया अनमनी सी ही नजर आईं।

सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा बुधवार को रायबरेली पहुंचीं और भुएमऊ गेस्ट हाउस में प्रदेशभर से प्रशिक्षण के लिए जुटे जिला और शहर अध्यक्षों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। गुरुवार दोपहर करीब 12.30 बजे दोनों कांग्रेस नेता अमेठी के लिए रवाना हो गईं। सड़क के दोनों किनारों पर क्षेत्रवासी इस उम्मीद में खड़े थे कि शायद सोनिया या प्रियंका हालचाल लें, मगर ऐसा नहीं हुआ। गाड़ियां सीधे भरेथा मौजा में रुकीं, जहां के छह ग्रामीणों की पिछले दिनों सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। दो परिवारों से कुछ मिनटों की मुलाकात कर काफिला फिर उसी रफ्तार से वापस फुरसतगंज हवाई पट्टी के लिए दौड़ पड़ा। अमेठी के बाशिंदों को शायद इसकी उम्मीद न रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी यहां से सांसद रहे, तब सोनिया आती थीं तो भीड़ देखकर गाड़ी रुकवा देती थीं। चलते-चलते हालचाल ले लेती थीं। न रुकीं तो गाड़ी का शीशा नीचे कर हाथ जोड़ लेती थीं। राहुल गांधी की हार के बाद सोनिया का यह पहला अमेठी दौरा था। प्रियंका भी उसके बाद एक ही बार कुछ देर के लिए आई थीं।

अमेठी के भरेथा गांव में सड़क हादसे में मृतक कल्पनाथ कश्यप के आवास पर उनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करतीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा। हृदेश चंदेल

संघर्ष की बेला है, घर और मजबूत करें : सोनिया

जासं रायबरेली : बुधवार की शाम लगभग साढ़े पांच बजे भुएमऊ गेस्टहाउस पहुंची कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा लगभग 19 घंटे तक रायबरेली में रहीं लेकिन प्रशिक्षण के संयुक्त सत्र में बोलने का मोर्चा प्रियंका ने ही संभाला। सोनिया ने सिर्फ तीन से पांच मिनट में ही अपनी बात रखी। उन्होंने लोगों से कहा कि ये हमारा घर है। घर के लोगों को संघर्ष के लिए और मजबूत होना चाहिए। आप लोग अपने को मजबूत करें, क्योंकि 2022 की लड़ाई लड़नी है।

गुजरात भाजपा के दो और विधायक नाराज, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी) लिमिटेड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के दो विधायकों ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखा है। इससे राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है।

सीएम रूपाणी के कार्यकाल के दौरान यह पहला मौका है, जब पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष जाहिर किया है। वडोदरा के सावली से विधायक केतन इनामदार ने गत दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इनामदार के समर्थन में सावली नगरपालिका के 16 पार्षद तथा 300 भाजपा नेता व पदाधिकारी भी इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वघाणी का दावा है कि इनामदार को मना लिया गया है। इस बीच भरूच जिले के दो विधायकों दुष्यंत पटेल व अरुण सिंह राणा ने जीएनएफसी में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम रूपाणी को पत्र लिखा है। उनका पत्र गुरुवार को मीडिया में आया। आरोप है कि वागरा में जीएनएफसी के टीडीआइ प्लांट में 7,700 मीट्रिक टन केमिकल्स जमा किया गया, जिसे खतरनाक गैस फॉस्जीन से बनाया गया है। इसी गैस से भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसा हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि दो और भाजपा विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने इनामदार को पार्टी में शामिल होने के लिए खुला ऑफर देते हुए कहा, 'आधी पिच पर आकर खेलने वाले रूपाणी को उनके विधायक ही स्टंप आउट करेंगे।' सीएम रूपाणी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ज्यादा खुश न हो। कई कांग्रेसी विधायक भाजपा में आने के लिए लाइन में लगे हैं।

1951 के शरणार्थी समझौते (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) का हस्ताक्षरकर्ता देश भारत नहीं है और न ही यहां कोई घरेलू शरणार्थी कानून है। इसलिए बिना किसी वैध कागजात या एक्सपायर्ड हो चुके कागजात के भारत में रहने वाले लोगों को अवैध प्रवासी माना जाता है।

न्यूज गैलरी

महिलाओं की आड़ में बवाल करने वाले कायर : योगी

आगरा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि महिलाओं को आगे कर सीएए का विरोध करने वाले कायर हैं। अब प्रशासन अपनी शैली में इसका हल ढूंढ़ेगा। देश विरोधी नारे लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होगी। आगरा में सीएए के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सिमी और पीएफआइ के बुलावे पर हर जगह आग लगा रहे थे, उन्हें जब पता चला कि उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा, तो सब शांत हो गए। सभी को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में देश विरोधी गतिविधियां करने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। पिछली सरकारें दंगाइयों की मिन्नतें करती थीं, अब कार्रवाई हो रही है। (जासं)

'साधु-संतों की भावना और भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए'

कन्नौज : सीएए का विरोध कर रहीं महिलाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू धर्म में साधु-संतों का सम्मान है। यदि वह साधु-संत और योगी हैं तो कम से कम ऐसी भावना और भाषा नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के छिबरामऊ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह लाखों महिलाएं भारतीय संविधान को बचाने के लिए खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही भारत की आत्मा को समझेगा। सरकार को जवाब देने दीजिए, जनता वोट डालने के बाद इन्हें हटाकर अपना संविधान बदल देगी। (जासं)

'सीएए कायम रहा तो धर्मनिरपेक्षता पर अंतिम कील'

भोपाल : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएए को मोदी सरकार का असंवैधानिक कानून बताया है। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान घबराया, डरा हुआ और निराश है। उसने राजनीतिक दलों, नेताओं, पुलिस से उम्मीद छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद की अंतिम किरण दिखाई दे रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को कायम रखा तो यह देश की धर्मनिरपेक्षता पर अंतिम कील साबित होगा। दिग्विजय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया और कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान भड़काने व उकसाने वाला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वह अब न तो राजनीतिक दलों के हाथ में रहा, न नेताओं के बस में रहा। (राब्यू)

राजस्थान विस सत्र में सीएए के खिलाफ आएगा संकल्प

जयपुर : राजस्थान विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। इस साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ सत्र शुरू होगा। सत्र के पहले दिन ही हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि सरकार सत्र में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ संकल्प पारित कराने का प्रस्ताव लेकर आएगी। संकल्प पारित कराने के साथ ही संसद और विधानसभा में एससी, एसटी का आरक्षण 10 साल बढ़ाने के लिए किए गए 126वें संविधान संशोधन का अनुमोदन भी किया जाएगा। कांग्रेस, भाजपा दोनों ही दलों ने 24 व 25 जनवरी के लिए विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। (राब्यू)

जनमत
मुद्दा

क्या प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार हमारे संविधान की मूल आत्मा से खिलवाड़ करने में सक्षम है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं।

झारखंड में सीएए के समर्थन में निकले जुलूस पर हमले के बाद बवाल, कर्फ्यू

बिगाड़ा माहौल ▶ लोहरदगा के विभिन्न क्षेत्रों में तोड़फोड़, घरों में लगाई गई आग

चार दर्जन लोगों के साथ ही पुलिसकर्मी भी घायल

जागरण संवाददाता, लोहरदगा

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में झारखंड के लोहरदगा में गुरुवार को निकाले गए जुलूस पर अमलाटोली क्षेत्र में हमला हो गया। उपद्रवियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तोड़फोड़ और अगजनी भी शुरू कर दी। मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहनों, निजी एवं सरकारी वाहनों के साथ-साथ कई दुकानों को फूंक दिया गया। कुछ देर के अंतराल पर पूरा लोहरदगा धू-धू कर जलने लगा। इन घटनाओं में चार दर्जन से अधिक महिला-पुरुषों के साथ पुलिस के भी कई जवान घायल हुए हैं। घायलों में सीएए समर्थकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हैं। शहर के कई इलाकों में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिहिंसा का दौर भी शुरू हो गया। हिंसा रोकने में पुलिस पूरी तरह विफल रही, यहां तक कि उपद्रवियों ने एसपी प्रियदर्शी आलोक को लक्ष्य कर जबरदस्त पथराव किया। किसी तरह अंगरक्षक उन्हें सही सलामत निकालने में सफल रहे, लेकिन इस क्रम में एसपी के कई अंगरक्षक घायल हो गए।

लोहरदगा में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद सड़क पर बिखरे ईंट के टुकड़े। जागरण

मांगा गया अतिरिक्त बल

उपायुक्त आकांक्षा रंजन, एसपी प्रियदर्शी आलोक, डीडीसी आर रोनिटा, एसडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह सहित पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी सड़क पर उतरकर शांति व्यवस्था कायम करने में जुटे रहे। इधर इस घटना के बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक एबी होमकर लोहरदगा पहुंचकर स्थित पर नजर रख रहे हैं। लोहरदगा जिले के अलग-अलग स्थानों के अलावा दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगा लिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर दिया गया।

शहर में लगाया गया कर्फ्यू

शहर के माहौल को देखते हुए उपायुक्त आकांक्षा रंजन के निर्देश पर एसडीओ ज्योति कुमारी झा ने शहर में एहतियातन कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ अग्निशमन विभाग सहित तमाम आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को अपने घर से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है।

लोहरदगा में जुलूस पर हमले के दौरान ही उपद्रवियों ने दीपक अग्रवाल की दुकान में आग लगा दी। जागरण

स्कूल में फंसे रहे विद्यार्थी

इस दौरान कई स्कूलों में विद्यार्थी काफी देर तक फंसे रहे। बाद में पुलिस-प्रशासन के निर्देश पर बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक अभिभावकों के माध्यम से पहुंचाया गया।

अशोभनीय टिप्पणी पर पूर्व मंत्री के खिलाफ केस

नईदुनिया, राजगढ़

▶ मप्र में थप्पड़ कांड : सभा में राजगढ़ की कलेक्टर के लिए बोले थे अपशब्द

मध्य प्रदेश के राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने पर पुलिस ने गुरुवार शाम भाजपा नेता व पूर्व राज्यमंत्री बद्रीलाल यादव के खिलाफ ब्यावरा थाने में एफआइआर दर्ज कर ली। वहीं, शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न संघों ने टिप्पणी के विरोध में जिलेभर के कुछ कार्यालयों में काम बंद करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।

गौरतलब है कि 19 जनवरी को सीएए के समर्थन में ब्यावरा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इसी दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी रवि बड़ोने को थप्पड़ मार दिया था। डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने भी एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे थे। इसके विरोध में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह, विस में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ब्यावरा में सभा कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ललकारा था।

इन नेताओं के मंच पर पहुंचने से पहले ही पूर्व मंत्री यादव ने कलेक्टर को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी। भाजपा नेता यादव के खिलाफ ब्यावरा के एसडीएम संदीप अस्थाना की शिकायत पर ब्यावरा सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है।

पुतले फूंके, प्रदर्शन किया : गुरुवार को राजगढ़ जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव पर कार्रवाई की मांग की। अधिकांश कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वहीं कांग्रेस ने जगह-जगह यादव के पुतले जलाए। अधिकारियों-कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। एसडीएम श्रुति अग्रवाल के नेतृत्व में एडीएम नवित धुर्वे को सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

जल संसाधन मंत्री ने की अधिकारियों की तारीफ

इस बीच मप्र के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने राजगढ़ की महिला कलेक्टर और एसडीएम के कार्यों की प्रशंसा की। कराड़ा ने कहा कि इन अधिकारियों ने सख्त कदम उठाकर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा। किसी भी अप्रिय घटना को घटित नहीं होने दिया।

अब गुना कलेक्टर ने नेताओं को बताया 'डकैत-घपलेबाज'

अब प्रदेश के अधिकारी भी मर्यादा तोड़ने लगे हैं। वह मुखर होकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गुना के कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने अपनी फेसबुक वॉल पर वरिष्ठ अफसरों-को टैग करते हुए लिखा कि 'जिनकी डकैती और घपलेबाजियां सारा शहर जानता है, वे सीना ठोककर झूठ बोल रहे हैं।'

मौजूदा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से गहरी होंगी लोकतंत्र की जड़ें : प्रणब

नई दिल्ली, एजेंसियां

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुनना, तर्क करना और असहमति को लोकतंत्र की खुशबू बताया है। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर चल रहे मौजूदा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल चुके हैं। पूरा विश्वास है कि विरोध प्रदर्शन की इन लहरों से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।

चुनाव आयोग की तरफ से गुरुवार को आयोजित प्रथम सुकुमार सेन स्मृति व्याख्यान में बतौर वक्ता पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र हर परीक्षा में खरा उतरा है। सहमति किसी भी लोकतंत्र के लिए जीवनदायी खून की तरह महत्वपूर्ण होती है।

युवाओं की राय भी महत्वपूर्ण : देश भर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों का स्पष्ट हवाला देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, 'पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में लोगों को घरों से निकलकर सड़कों पर आते हुए देखा गया है। खासकर युवाओं को, जिन्होंने मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। मेरी नजर में उनकी राय भी महत्वपूर्ण है। संविधान को लेकर उनकी अभिव्यक्ति और विश्वास मन को प्रसन्न करने वाला है।' उल्लेखनीय है कि इन प्रदर्शनों में कई जगहों पर हिंसा भी हो चुकी है।

कार्यक्रम के बाद उपलब्ध कराई गई पूर्व राष्ट्रपति के भाषण की प्रति के अनुसार, 'मुझे विश्वास है कि व्यापक और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की लहरें पूरे देश में फैल चुकी हैं और इससे लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी।' हालांकि, भाषण के दौरान उन्होंने ये बातें नहीं कही थीं।

चुनाव को बदनाम करने की कोई भी कोशिश से चुनाव प्रक्रिया होगी बदनाम : पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है और उसे बदनाम करने की कोई भी कोशिश पूरी चुनाव प्रक्रिया को बदनाम कर देगी। उन्होंने कहा कि कोई संस्थान कैसा काम करता है, यह वहां काम करने वाले लोगों पर निर्भर करता है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से संस्थागत अखंडता सुनिश्चित की है।

सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाना राजनीतिक कदम : शशि थरूर

जासं, कोलकाता : कांग्रेस सांसद व वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का राज्यों का कदम राजनीति से प्रेरित है क्योंकि नागरिकता देने में उनकी बमुश्किल ही कोई भूमिका नजर आती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण और प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी के क्रियान्वयन में राज्यों की अहम भूमिका होगी क्योंकि केंद्र के पास मानव संसाधन का अभाव है, ऐसे में राज्य के अधिकारी ही इस काम को पूरा करेंगे।

यहां बता दें कि थरूर का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस शासित पंजाब और वाममोर्चा की अगुआई वाली केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ 27 जनवरी को प्रस्ताव लाया जाना है। जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, इससे पहले थरूर के पार्टी सहयोगी कपिल सिब्बल ने भी पिछले सप्ताह यह कहा था कि सीएए के क्रियान्वयन से राज्य इन्कार नहीं कर सकते।

सीएए के खिलाफ बोल कर विपक्ष कर रहा एससी का विरोध : जेपी नड्डा

जागरण संवाददाता, आगरा

भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली सभा में जेपी नड्डा गुरुवार को आक्रामक तेवर में थे। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में हुई सभा में उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी सीएए पर 10 लाइन भी बोल दें तो मान जाऊं। उन्होंने विपक्ष को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वह इसका विरोध कर अनुसूचित जाति (एससी) का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सीएए से लाभांवित होने वाले शरणार्थियों में 70 फीसद एससी हैं। प्रधानमंत्री ने इस कानून को लागू कराया तो गृहमंत्री अमित शाह इसके शिल्पी हैं।

सभा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को हताश और मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया और उसके नेताओं को पाकिस्तानी भाषा बोलने वाला कहा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उप्र में भी देश-विरोधी तत्वों द्वारा कई जगह दंगे भड़काने की कोशिश की गई लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी इसकी निंदा नहीं की क्योंकि वही इसे भड़काने में लगी हुई है। कांग्रेस देश में स्थिरता लाना नहीं चाहती। रामजन्मभूमि मुद्दे पर कहा कि देश में ऐसा भी नेतृत्व था जो जानबूझ कर श्रीराम जन्मभूमि विवाद का हल नहीं चाहता था। बहुत जल्द अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण होगा।

सीएए के समर्थन में काठी मीना बाजार मैदान पर आयोजित जनसभा में लोगों को संबोधित करते भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। जागरण

- जनसभा में भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर बोला हमला
- कहा, राहुल गांधी सीएए पर 10 लाइन बोल दें तो मान जाऊं
- बोले, कांग्रेस हताश और मानसिक दिवालियापन की शिकार

> देश में जो काम 70 वर्षों से लटके हुए थे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने उन्हें आठ महीने में पूरा कर 'लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई' की कहावत को बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति ने सदियों के लिए राहत दे दी है।
> **-जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा।**

मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी बोला-तुम सट्टेबाजी करो, मैं हूं ना

नईदुनिया, होशंगाबाद : मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी का अनूठा मामला सामने आया है। राज्य के सिवनी मालवा के पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) शंकरलाल सोनिया ने एक पूर्व सटोरिए को वरदहस्त देते हुए कहा, 'तुम सट्टेबाजी करो, मैं हूं ना। हर माह 10 हजार रुपये देना।' एसडीओपी द्वारा रिश्वत का दबाव बढ़ाने पर पूर्व सटोरिए ने प्रदेश लोकायुक्त पुलिस संगठन से शिकायत की। लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को योजनापूर्वक एसडीओपी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया।

लोकायुक्त टीम के अनुसार सिवनी मालवा के देवल मोहल्ला डागाजी मार्ग निवासी पूर्व सटोरिए दीपक धन्यासे (34) ने भोपाल कार्यालय में शिकायत की थी कि वह तीन माह पहले सट्टेबाजी बंद कर चुका। इसके बाद भी एसडीओपी शंकरलाल सोनिया उसे सट्टेबाजी जारी रखने और हर माह 10 हजार रुपये रिश्वत देने का दबाव बना रहे हैं। तीन माह से उसने कोई राशि नहीं दी तो पुलिस बार-बार घर आकर परेशान कर रही है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

मसूरी थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर एनसीसी के टू-सीटर ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। प्लेन में बैठे दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची एयरफोर्स की तकनीकी टीम विमान को ट्रक में रखकर साथ ले गई। एनसीसी के इस जेन एयरक्राफ्ट को वायुसेना का पायलट उड़ा रहा था। इसमें अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। घटना में पायलट या किसी अन्य को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विमान को थोड़ी क्षति अवश्य पहुंची है।

एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि विमान सुबह 11.16 मिनट पर बरेली से हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हुआ था। तकनीकी खराबी आने पर 1:45 बजे सदरपुर गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हादसे में एनसीसी के जेन एयरक्राफ्ट के आगे का एक पहिया और बायां विंग क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पायलट ने एयरफोर्स के अधिकारियों को घटना की सूचना दी। अधिकारी तकनीकी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एयरफोर्स के अधिकारियों ने विमान की जांच-पड़ताल की। तकनीकी टीम ने विमान के दोनों को विंग को खोल दिया। इसके बाद शाम करीब चार बजे विमान को एयरफोर्स के ट्रक में रखकर साथ ले गए। विमान पर एनसीसी का लोगो बना हुआ था।

सीमा विवाद में फंसी पुलिस : विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद मुरादनगर और मसूरी पुलिस सीमा विवाद में उलझ गई। समय पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

पायलट की समझदारी से टल गया बड़ा हादसा

तकनीकी खराबी आने से पायलट ने विमान को बीच सड़क पर नहीं उतारा। यदि पायलट विमान को बीच सड़क पर उतार देता तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि उस दौरान एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से वाहन दौड़ रहे थे। हालांकि सड़क के किनारे पर लैंड करने के विमान का विंग रेलिंग की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया।

निर्भया के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने वाले जज का तबादला

जासं, नई दिल्ली : निर्भया के दोषियों को डेथ वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा का तबादला हो गया है। उन्हें पटियाला हाउस अदालत से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग में अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने पटियाला हाउस के सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि सतीश कुमार अरोड़ा को तुरंत उनके मौजूदा पद से मुक्त किया जाए, ताकि वह नया पदभार संभाल सकें। तबादला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दिशा-निर्देश पर किया गया है। पटियाला हाउस अदालत में बतौर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहते हुए सतीश कुमार अरोड़ा ने दोषियों विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह और पवन को एक फरवरी के लिए डेथ वारंट जारी किया था। उनके कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के केस भी सुने जाते थे। अब निर्भया मामले को जल्द अन्य अदालत में भेजा जाएगा और वहीं पर इस केस से संबंधित कोई भी याचिका दायर हो सकेगी।

निर्भया के दोषियों के रिश्तेदारों को बताई फांसी की तारीख

गौतम कुमार मिश्रा, नई दिल्ली

निर्भया के दोषियों के नाम जारी डेथ वारंट के अनुसार एक फरवरी को फांसी दी जानी है। जेल प्रशासन फांसी की प्रक्रिया को पूरा करने में जुट गया है। दोषियों के रिश्तेदारों को पत्र लिखकर बताया दिया है कि एक फरवरी को सुबह छह बजे फंदे पर लटकाया जाएगा। यदि वे चाहें तो अंतिम मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जेल प्रशासन को अभी किसी का कोई जवाब नहीं मिला है।

तिहाड़ जेल अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता दोषियों की सुरक्षा को लेकर है। इसके लिए जेल मैनुअल पर कड़ाई से अमल हो रहा है। उनके सेल को रोजाना बदला जा रहा है। उन्हें ऐसे सेल में रखा जा रहा है, जहां बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मी को हर कोना आसानी से नजर आए। उसकी संरचना में ऐसी कोई कमी न हो जिसकी मदद से दोषी खुदकशी की कोशिश कर सके। सुरक्षाकर्मी को सख्त हिदायत है कि दोषी से कोई बात न करे। यदि दोषी को सेल से बाहर निकालना पड़े तो सुनिश्चित कर लिया जाए कि वहां पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद हों। इस सेल की जांच जेल उपाधीक्षक स्वयं करते हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि चारों दोषियों को एक ही बैरक, लेकिन अलग अलग सेल में रखा गया है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले चारों दोषियों अक्षय, विनय, पवन व मुकेश को जेल संख्या तीन के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। इसी जेल में फांसी घर भी है। रोजाना चिकित्सक उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। सुबह व शाम के समय स्वास्थ्य की जांच होती है। उनका वजन किया जाता है। डाइट चार्ट के हिसाब से भोजन दिया जा रहा है।

इंद्रा जयसिंह को कंगना की फटकार

मुंबई, एएनआइ : बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनोट ने वरिष्ठ वकील इंद्रा जयसिंह को निर्भया की मां से दुष्कर्मियों को माफ करने के लिए कहने पर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि उस महिला (जयसिंह) को उन अपराधियों के साथ चार दिनों के जिए जेल में रखना चाहिए। गुरुवार को एक कार्यक्रम में कंगना ने यह भी कहा कि समाज के सामने उदाहरण स्थापित करने के लिए दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि सबसे पहले तो दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वाले लोग नाबालिग नहीं होते। ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्भया के माता-पिता के साथ सहानुभूति व्यक्त की और मौत की सजा तामील करने में देरी पर नाखुशी जताई।

दो हजार रुपये महीने पर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता था मुस्तफा

रेलवे ई-टिकटिंग रैकेट

दिलीप सिन्हा, गिरिडीह

> सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला उसमें ऐसी युक्ति कर सकता है, जिससे एक महीने बाद वह काम करना बंद कर दे। इसी के दम पर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला रुपये न मिलने पर उसे बंद कर देता होगा।
> **-पंकज कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।**

> रैकेट के बारे में कई जानकारियां मिली हैं। आधा दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। आपत्तिजनक सॉफ्टवेयर भी उनके पास मिला है। जांच चल रही है। पूरे रैकेट को ध्वस्त किया जाएगा।
> **-हेमंत कुमार, सीनियर कमांडेंट, आरपीएफ, धनबाद**

सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े गुलाम मुस्तफा की गिरफ्तारी के बाद अंतरराष्ट्रीय रेलवे ई-टिकटिंग रैकेट के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के दलांगी गांव का गुलाम मुस्तफा इस गिरोह का सह सरगना है। सरगना हामिद अशरफ दुबई में रहता है।

मुस्तफा ने देशभर में रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों को एएनएमएस नाम का सॉफ्टवेयर बेचा। इस सॉफ्टवेयर के लिए हर माह दो हजार रुपये की रकम भी ली जाती थी। भुगतान न करने पर सॉफ्टवेयर का लिंक काट दिया जाता था। रेल पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुस्तफा पहले ओडिशा में हाफिज (जिसे कुरान कंठस्थ हो) के रूप में काम करता था। फिर बेंगलुरु जाकर मदरसे में हाफिज बना। यहीं रेलवे ई-टिकटिंग गिरोह के सरगना हामिद के संपर्क में आया। कुछ ही दिनों में सह सरगना के रूप में उसकी पहचान हो गई। उसे सॉफ्टवेयर बेचने का जिम्मा मिला। देशभर में रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों को यह सॉफ्टवेयर बेचने लगा। अपनी कथित पत्नी सबीना के जरिए वह खरीदार को सॉफ्टवेयर देता था। एक सॉफ्टवेयर के लिए दो हजार रुपये प्रतिमाह लेता था। मुस्तफा अब तक तीन हजार सॉफ्टवेयर देशभर में बेच चुका है। वह इससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा दुबई में हामिद अशरफ को भेजता था। इधर, रेल पुलिस ने गिरिडीह से अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ने गुरुवार को रेल अदालत धनबाद में सरेंडर किया है।

रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आइआरसीटीसी और क्रिस एप जारी किया है। इस गिरोह ने नया सॉफ्टवेयर एएनएमएस तैयार किया। जो रेलवे के सॉफ्टवेयर से अधिक तेज काम करता है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए लिंक खुलने के बाद यात्री का डिटेल भरा जाता है, तब टिकट बुक होता है। एएनएमएस सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले यात्री का डिटेल भर लिया जाता है। जब बुकिंग का लिंक खुलता है, गिरोह अधिकांश टिकटों को रेलवे के सिस्टम में सॉफ्टवेयर के बल पर सेंध लगाकर बुक कर लेता है।

हामिद का नेपाल में ठिकाना, दुबई भी आना-जाना

एसके सिंह, बस्ती

उप्र के बस्ती के रमवापुर कला गांव निवासी हामिद अशरफ का कनेक्शन आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान से होना सामने आया है। भुवनेश्वर में दो दिन पूर्व पकड़े गए गुलाम मुस्तफा ने यह राज खोला तो खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए। पता चला कि अनाधिकृत रेल टिकट का कारोबारी हामिद आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। इसके बाद पुलिस उसे दबोचने के लिए दो दिनों से नेपाल में डेरा डाले है। वह पहली बार 2016 में एएनएमएस नामक साफ्टवेयर से रेल टिकटों का कारोबार पूरे देश में खड़ा करने के बाद पकड़ में आया था। उसके एजेंट कई जगह पकड़े गए। रेल मंत्रालय ने जांच सीबीआइ को सौंपी है। अप्रैल 2016 में बस्ती के पुरानी बस्ती क्षेत्र स्थित दक्षिण दरवाजा से वह पकड़ा गया। कुछ दिन बाद जमानत पर छूटकर आया तो अपना ठिकाना बदलकर नेपाल में जा छिपा। इसका कनेक्शन दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

पिता हुआ भूमिगत : हामिद के पिता जमीरुल हसन गांव छोड़कर कप्तानगंज में बस चुके हैं। वहां चूड़ी बेचने का कारोबार शुरू किया फिर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान खोली। तरक्की का आलम यह रहा कि दो साल पहले एचएमडी मार्ट खोल लिया। यह हामिद अशरफ के नाम ही है। इसके बाद दूसरा व्यावसायिक कांप्लेक्स भी बनवाने लगा। आतंकी संगठन से जुड़ने की बात सामने आने पर भूमिगत हो गया।

बस्ती में पला और बढ़ा हामिद : आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने बताया कि हामिद, जमीरुल हसन का गोद लिया बेटा है। पढ़ाई के दौरान ही वह रेल टिकट के कारोबार से जुड़ गया था।

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चौथा तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
[illegible]
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम [illegible]
[illegible]
To, D-1 [illegible]
D-2 [illegible]
[illegible]
[illegible] 23.03.2020 को प्रातः 10.30 बजे इस अधिकरण के समक्ष [illegible]
[illegible] 9 जनवरी 2020.
अधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

867.9 हजार लोग नवंबर 2019 में भारत के औपचारिक श्रमक्षेत्र से जुड़े हैं। एम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) के हवाले से यह रिपोर्ट पिछले दिनों जारी की गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 24 जनवरी 2020

सागर में जलाए गए युवक की दिल्ली में मौत, मध्य प्रदेश में सियासत गर्म

राज्य ब्यूरो, भोपाल: मध्य प्रदेश के सागर में करीब 10 दिन पहले जलाए गए अनुसूचित जाति के युवक की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते प्रदेश सरकार ने अजा युवक की फरियाद पर समय पर कार्रवाई नहीं की। वहीं, कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।

सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के धनप्रसाद अहिरवार को उसके पड़ोसियों छुट्टू, अच्चू पठान, कल्लू और इरफान ने 14 जनवरी को केरोसिन डालकर जला दिया था। उन्हें इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से दिल्ली भेजा गया था, जहां गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। युवक की मौत पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'धनप्रसाद अहिरवार के परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। परिवार की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं।' दूसरी ओर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कमलनाथ जी, घटना के समय आपकी सरकार और पुलिस कहां थी, बताइए? कुछ दिन पूर्व भी धनप्रसाद के भाई की पत्नी के साथ इन्ही दबंगों ने मारपीट की थी, तब भी यह सरकार मौन थी। उसी समय पुलिस ने जरूरी कदम उठाए होते तो शायद आज प्रदेश को अपने एक नागरिक के जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा नेताओं ने धनप्रसाद के इलाज को लेकर राजनीति की, लेकिन देखभाल नहीं की। घटना को भाजपा ने दलित-मुस्लिम विवाद का रूप देने का प्रयास भी किया।

तमिलनाडु में आइएस के तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

शिकंजा ▸ धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना चाहते थे आरोपित

आतंकी संगठन के लिए करते थे भर्तियां, जुटाते थे धन

रामनाथपुरम, प्रेट्र : तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में आतंकी संगठन आइएस से संबंध रखने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों जिहादी विचारधारा का प्रचार करते थे और इस्लाम का विरोध करने वालों की हत्या की फिराक में थे, ताकि लोगों के बीच भय पैदा हो।

पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आरोपित बी. मुहम्मद अली, पुरा गनी और आमिर को एक सूचना के आधार पर देवीपटनम से बुधवार को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब सभी फरार होने की तैयारी में थे। हालांकि, एक अन्य आरोपित शेख दाऊद फरार होने में कामयाब रहा।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपित रामनाथपुरम में जिहादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। वे लोग देशविरोधी गतिविधियों में भी शामिल थे। आरोपित प्रतिबंधित संगठन आइएस के लिए भर्तियां करने और धन जुटाने का काम भी करते थे।

पुलिस ने बताया कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे एक अन्य आरोपित अब्दुल शमीम को धन हस्तांतरित करने की बात कर रहे थे। शमीम केरल सीमा पर स्थित कन्याकुमारी जिले में हुई विल्सन की हत्या का आरोपित है। पुलिस ने तीनों आरोपितों के पास से किताबें और इस्लामिक प्रचार सामग्री जब्त की हैं। उनके पास से ऑडियो क्लिप के रूप में भी जिहादी प्रचार सामग्री मिली, जिन्हें वे वाट्सएस समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते थे। तीनों आरोपित मुहम्मद रियाज व शेख दाऊद के साथी हैं, जिन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने पहले से मुकदमा दर्ज कर रखा है। पुलिस ने आइपीसी की विभिन्न धाराओं समेत गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

एटीएस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर : मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने वर्ष 2018 के नालासोपारा (मुंबई) हथियार तस्करी के फरार आरोपित प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पुणे में आयोजित सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल-2017 में हमले के लिए षड्यंत्र रचने का भी आरोप है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि प्रताप बंगाल का रहने वाला है। प्रताप को एक स्थानीय कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 30 जनवरी तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया।

पाक में चल रहे वाट्सएप से जुड़े हैं 50 भारतीय नंबर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ एजेंट राशिद अहमद से पूछताछ के दौरान पाकिस्तान में संचालित एक वाट्सएप अकाउंट रिकवर करने में कामयाबी हासिल कर ली है। उस ग्रुप में 50 भारतीय नंबर भी जुड़े हैं। राशिद ने बाबू व अली की आइडी पर दो सिम लिए थे, जिन नंबरों पर पाकिस्तान में वाट्सएप संचालित हो रहे हैं। एटीएस व अन्य खुफिया एजेंसी अब वाट्सएप के जरिए सीधे पाकिस्तान में बैठे आइएसआइ के आकाओं से जुड़े 50 भारतीय नंबरों के बारे में छानबीन करने में जुट गई है। एटीएस के एक अधिकारी के अनुसार राशिद अहमद ने अपने दोस्त बाबू की आइडी पर जो सिम लिया था, उस पर संचालित वाट्सएप रिकवर हुआ है।

26 जनवरी को रिहा किए जाएं सभी राजनीतिक बंदी : मीर

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ एनडीपी और पीडीपी नेता बोले-यह रिहाई की परंपरा है, बंदिशें भी हटें

▸ केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बहुत अच्छे, इनका परिणाम भी जल्द दिखेगा

गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू-कश्मीर में कैदियों की रिहाई की परंपरा रही है। इसलिए हिरासत में रखे गए तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों को 26 जनवरी को रिहा किया जाए। इसके साथ ही जो बंदिशें रही हैं उन्हें हटाया जाए। यह केंद्र की संवेदना का एक बड़ा कदम होगा।

यह बात नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) अध्यक्ष गुलाम हसन मीर और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के पूर्व महासचिव दिलावर मीर ने श्रीनगर में गुरुवार को संयुक्त पत्रकारवार्ता में कही। वहीं, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा है। आना चाहिए, तभी तो वह जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात को समझ सकेंगे। हां, देखना यह है कि वह इन दौरों से क्या सबक लेते हैं। यहां के मसलों को कैसे हल करते हैं। दौरों का परिणाम चार-छह महीने बाद ही दिखेगा। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से केंद्रीय मंत्रियों का कश्मीर दौरा काफी महत्वपूर्ण है।

जम्मू-कश्मीर में तीसरे मोर्चे के गठन की जारी सुगबुगाहट के बीच गुरुवार को संयुक्त पत्रकारवार्ता में दोनों ही नेता विवादास्पद सवालों से बचते नजर आए। लेकिन उन्होंने साफ संकेत दिया कि पांच अगस्त 2019 के बदलाव को लोग स्वीकार रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पांच अगस्त तक किसी को इसका आभास नहीं था, लोगों में नाराजगी भी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। केंद्र सरकार के हालात को काबू रखने के लिए किए गए बंदोबस्त सराहनीय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही हमें कश्मीर में शांति बहाली के लिए आम लोगों को भी श्रेय देना चाहिए क्योंकि उन्होंने तमाम उत्तेजना के बावजूद संयम बरता और हिंसा पर नहीं उतरे।

शायद ही वापस आए अनुच्छेद 370

अनुच्छेद 370 को लेकर पूछे गए सवाल पर हसन और दिलावर ने कहा कि यह शायद ही अब वापस आए। क्योंकि राष्ट्रीय दलों में इसकी बहाली के लिए सहमति नहीं बनेगी। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही इस पर फैसला लेगा, अगर वह कहे तो ही बहाल होगा। कश्मीर पंडितों के पलायन संबंधी सवाल पर गुलाम हसन मीर ने कहा कि यह बहुत दुखद है। यह किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, दुखद है। कोई भी कश्मीरी पंडितों के पलायन से खुश नहीं है। इसके साथ ही डोमिसाइल के मुद्दे पर गुलाम हसन मीर और दिलावर मीर ने कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। विभिन्न राज्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार, जमीन व अन्य मुद्दों पर संरक्षण प्रदान करने के लिए यह सुविधा है।

सीटीईटी के लिए आवेदन आज से, परीक्षा जुलाई में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जुलाई 2020 में आयोजित होने वाली केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के आवेदन और परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। इसके लिए 24 जनवरी से 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जबकि परीक्षा पांच जुलाई को होगी। 27 फरवरी तक आवेदन शुल्क जमा होंगे। बोर्ड के मुताबिक देश के 112 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन सीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही की जा सकेगी। सीबीएसई साल में दो बार जुलाई और दिसंबर में यह परीक्षा आयोजित करता है। पेपर-1 में सफल उम्मीदवार कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि पेपर-2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये, जबकि पेपर 1 और 2 के लिए 1200 रुपये है। एससी-एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 के लिए 500 रुपये और पेपर 1 और 2 के लिए 600 रुपये रखा गया है।

250 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाया

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

उत्तरी कश्मीर में सेना की किलो फोर्स में ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी ने कहा कि हम स्थानीय सिविल सोसाइटी, पंच-सरपंचों, जिला प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवी संगठनों के साथ लगातार संवाद करते हैं। इसी आधार पर हम करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं। यहां रोजगार मेले के जरिए करीब 250 लड़के-लड़कियों ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाया है।

नौजवानों को गुमराह होने से बचाना है मकसद : चिनार कोर मुख्यालय के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने कहा कि हमारा मकसद कश्मीर में शांति, खुशहाली, सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाते हुए स्थानीय युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगाना है। इसी के तहत गुडविल स्कूल भी स्थापित किए हैं ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जरूरी है कि जिहादी तत्वों को यहां नौजवानों को गुमराह करने का कोई मौका न मिले।

केंद्र की आउटरीच मुहिम ने कश्मीर में पकड़ा जोर

राज्य ब्यूरो, जम्मू

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। अब जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद-370 की उस दीवार को लांघ चुका है, जो विकास में बाधा थी। ऐसे में अब प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहुंच रहे केंद्रीय मंत्री अब विकास की ऐसी प्राचीर बनाने में जुटे हैं जो लोगों में विश्वास पैदा करता हो... लोगों को अलगाववाद और आतंकवाद से दूर रखता हो। मोदी सरकार का आउटरीच कार्यक्रम इस उद्देश्य को पूरा करता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की आगवानी करते लोग साफ संकेत दे रहे हैं कि यह नया जम्मू कश्मीर है, जो बड़ी उम्मीद से शांति और समृद्धि की नई सुबह का स्वागत कर रहा है।

जम्मू संभाग के बाद कश्मीर संभाग में भी अब मोदी के मंत्री विकास का मंत्र दे रहे हैं। गुरुवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों ने घाटी में दस से अधिक कार्यक्रम कर लोगों को विश्वास दिला दिया कि विकास की रफ्तार अब रुकेगी नहीं। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 11 मंत्रियों के कार्यक्रम हुए, जिनमें से आठ मंत्रियों के कार्यक्रम सिर्फ जम्मू संभाग में हुए। वहीं, तीन मंत्री कश्मीर पहुंचे। इनमें जी किशन रेड्डी गांदरबल, श्रीपद नायक श्रीनगर और केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद बारामूला में थे। इस दौरा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उद्घाटन किए। उन्होंने पंच-सरपंचों व आम लोगों से मुलाकात कर उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी मुश्किलों को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। शुक्रवार को रवि शंकर प्रसाद सिंह के अलावा रमेश पोखरियाल निशंक के भी कश्मीर में होंगे।

उधर, जम्मू संभाग में केंद्रीय मंत्री पुरषोत्तम रुपाला ने मीरां साहिब, सुरेश अंगड़ी ने बिश्नाह, साध्वी निरंजन ज्योति ने सुजनधार, सोम प्रकाश ने रियासी, रेणुका सिंह ने मानसर व रमेश्वर तेली ने रामबन में लोगों से मुलाकात कर उनका दर्द जानने सहित विकास गतिविधियों से अवगत करवाया। पुंछ जिले गुलपुर सेक्टर के गांव अजोट में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आम लोगों से रूबरू हुए।

कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बारामुला में इनडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद स्थानीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, यह नया जम्मू-कश्मीर है, जो बड़ी उम्मीदों के साथ शांति-समृद्धि की नई सुबह का स्वागत कर रहा है। ट्विटर से

रविशंकर बोले, अब सुध लेने वाली सरकार है

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कानून एवं न्याय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था व शांति किसी भी क्षेत्र समाज के विकास के लिए जरूरी है। जम्मू कश्मीर दोनों से वंचित था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहां लोगों की सुध लेने वाली सरकार है। बुधवार को बारामुला में विभिन्न जनप्रतिनिधिमंडलों से रवि शंकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करते हुए जन सभाओं को संबोधित किया। कानून एवं न्यायमंत्री रविशंकर ने आतंकियों का गढ़ कहे जाने वाले बारामुला के बाजार में भी पैदल सैर की।

केंद्रीय मंत्रियों के दौरे मात्र वोट बैंक की राजनीति : इल्तिजा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे सिर्फ भाजपा की वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य कश्मीर में मात्र अपना आधार मजबूत करना है। यह आरोप जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को अंधेरे में धकेल दिया है।

गुरुवार को एक समाचार एजेंसी से विशेष बातचीत करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू के लोग भाजपा से असंतुष्ट थे। भाजपा को डर है कि वह जम्मू में सीटें न हार जाएं। इसलिए यह सब शुरू किया गया है। पूछा कि कश्मीर में सबकुछ सामान्य है तो इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था का क्या औचित्य है? सरकार भी कह चुकी है कि अब घुसपैठ में कमी आई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई व्यापक नीति नहीं है। उनके पास सिर्फ पूर्ण बहुमत है, जिसमें मदमस्त होकर वह बिना नीति के फैसले ले रही है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने एनआरसी, सीएए और अयोध्या मामलों को प्राथमिकता दी। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है।

इल्तिजा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सीमित तौर पर जो इंटरनेट सेवाएं बहाल की हैं वे अंतरराष्ट्रीय दबाव में किया है। आरोप लगाया कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर आ रहे हैं, इसीलिए इंटरनेट सेवाएं आंशिक तौर पर बहाल की गई है।

सुरक्षाकर्मियों पर परेशान करने का आरोप

इल्तिजा मुफ्ती ने सुरक्षा कर्मियों पर कथित तौर पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। उसने ट्विट्र पर लिखा कि एसएसजी, आइबी और सीआइडी कश्मीर में लगातार उसकी निगरानी करती हैं। मुझे एसएसजी परेशान कर रही है। सुरक्षा की आड़ में मेरी निजता और आजादी को कुचला नहीं जा सकता।

डॉक्टर बम बोला- मुझे जानना हो तो 'डेंजरस माइंड' पढ़ो, पता चल जाएगा

गौरव दीक्षित, कानपुर

▸ इतिहास खंगालने की एसटीएफ की कोशिश पर दिया जवाब

▸ लेखक हुसैन जैदी और आइपीएस बृजेश सिंह ने लिखी शांत चित्त डॉक्टर के मौत का सौदागर बनने पर किताब

डॉक्टर बम नाम से कुख्यात आतंकी डॉ. जलीस अंसारी का पुराना इतिहास खंगालने में जुटी एसटीएफ के सामने एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद भी दुर्दांत आतंकी बेखौफ और बेफिक्र है। एसटीएफ ने पूछताछ के दौरान जलीस का इतिहास जानना चाहा तो उसने अधिकारियों को दो टूक कह दिया, 'मुझे जानना चाहते हो तो डेंजरस माइंड पढ़ो, मैं क्या हूं पता चल जाएगा।' यह किताब मुंबई के अपराध लेखक हुसैन जैदी और अंडरवर्ल्ड को काफी नजदीक से देखने वाले आइपीएस अफसर बृजेश सिंह ने लिखी है। किताब में कई कुख्यात अपराधियों की कहानी है।

आइपीएस अफसर बृजेश और हुसैन, दोनों ने आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड पर बड़ा शोध किया है। मुंबई के अपराधियों पर दर्जनभर से अधिक किताबें लिखी हैं। डेंजरस माइंड किताब तीन जुलाई 2017 को बाजार में आई थी। इस किताब में लेखकों ने लिखा कि एक शांत चित्त डॉक्टर मौत का सौदागर बन गया। लोगों का इलाज करते-करते बम बनाने लगा। कुछ लोगों के संपर्क में आया और आतंकी बन गया।

इस किताब में डॉ. जलीस के अलावा उत्तर-पश्चिम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की झुग्गी में रहने वाली दो बच्चों की मां और गृहिणी फहमीदा अंसारी के आतंकी बनने की कहानी भी है। इस किताब में लिखा है, एक सामान्य महिला टैक्सी और बस में बम लगाकर ऐसे घर लौट आती थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या कोई इतना हृदयहीन हो सकता है। किताब में शामिल कुख्यात अपराधियों के बारे में लिखा है कि कुछ मजबूरी में आतंकी बने तो कुछ का माइंड वॉश किया गया।

फिल्म 'द वेडनेसडे' में भी 'डॉक्टर बम' का साया : फिल्म अभिनेता नसीरूद्दीन शाह की 2008 में आई फिल्म 'द वेडनेसडे' में बम रखने और सूचना देने का तरीका डॉ. जलीस से प्रेरित है। हालांकि, निर्माता-निर्देशक नीरज पांडेय ने फिल्म के अनुसार समस्या से जूझ रहे आम आदमी के किरदार को रखा है। नीरज पांडेय ने कहानी की क्रेडिट जलीस के मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने वाले आइपीएस अफसर राकेश मारिया को दिया था। जलीस जनता को खौफजदा करने के लिए ऐसा करता था।

सूत्रों के अनुसार, जलीस ने मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर को फोन कर थाने में बम रखा होने की सूचना दी थी। तलाशी में बम मिलने के बाद डिफ्यूज करते समय वह फट गया और कई लोग घायल हो गए थे। एसबी-वन यानी स्पेशल ब्रांच (खुफिया एजेंसी) के सीनियर इंस्पेक्टर को भी फोन कर कार्यालय में बम रखा होने की सूचना दी, वहां भी बम मिला था।

मंगलुरु हवाई अड्डे पर बम रखने वाले को पुलिस हिरासत में भेजा

मंगलुरु, प्रेट्र : मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम रखने वाले आदित्य राव को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने बम रखने के संदिग्ध को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। एक दिन पहले राव ने बेंगलुरु में पुलिस के सामने समर्पण किया था। उसे मंगलुरु में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी किशोर कुमार की अदालत में पेश किया गया। दंडाधिकारी ने पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली। पुलिस ने आगे की जांच के लिए राव की हिरासत की मांग की थी। उसे पेश किए जाने के समय अदालत परिसर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। राज्य की राजधानी में स्वास्थ्य जांच कराने के बाद पुलिस टीम बुधवार रात राव को लेकर मंगलुरु पहुंची।

इससे पहले मंगलुरु के पुलिस आयुक्त पीएस हर्ष ने कहा था कि हवाई अड्डा परिसर में बम रखने से पहले राव ने योजना बनाई थी। संदिग्ध ने बताया है कि उसने बम बनाने के लिए ऑनलाइन सामग्री का आर्डर दिया था।

कड़ी सतर्कता से दुश्मन के मंसूबों को बनाएं पूरी तरह नाकाम : सेना अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, जम्मू

थलसेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने सेना की उत्तरी कमान के अधिकारियों व जवानों को दुश्मन के मंसूबे नाकाम बनाने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी व जवान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें।

उत्तरी कमान मुख्यालय ऊधमपुर में गुरुवार को सुरक्षा हालात पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सेना अध्यक्ष दोपहर को पहले राजौरी के भिंबर गली फिर कृष्णा घाटी सेक्टरों में पहुंचे। उन्होंने वहां पर फील्ड कमांडरों व जवानों से नियंत्रण रेखा के हालात के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सेना अध्यक्ष 16 कोर मुख्यालय नगरोटा पहुंचे। वहां बैठक कर जम्मू की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आतंकवाद के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए स्थायी शांति कायम करने के लिए कहा। दूरदराज क्षेत्रों में बर्फबारी से मुश्किलों का सामना करने वालों को सेना की ओर से दिए जा रहे सहयोग के बारे में भी जानकारी ली।

उप राज्यपाल से सुरक्षा परिदृश्य पर किया विचार विमर्श : जनरल नरवाने जम्मू में उप राज्यपाल जीसी मुर्मू से भी मिले। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य और देश के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाने की कार्रवाई और बेहतर समन्वय से गणतंत्र दिवस को सुरक्षित बनाने की मुहिम पर विचार-विमर्श किया गया।

थलसेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने (बाएं) जम्मू संभाग के दौरे के दौरान सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह के साथ। फोटो : पीआरओ डिफेंस

जागरण विशेष

मुश्किल हालात में हासिल की मंजिल, जीत रहीं हर मुकाबला, दोहरी जिम्मेदारियों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए मिलती है सराहना

एक और सुपर मॉम! चंडीगढ़ की मुक्केबाज हेड कांस्टेबल रीना

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़

बॉक्सिंग में जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने रीना को हाल ही में प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल बनाया है। दो बच्चों की मां रीना मुक्केबाजी में अब तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के 25 पदक जीत चुकी हैं। इससे पहले भारत की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरीकॉम, जिन्हें 'सुपर मॉम' का तमगा मिला, दोहरी जिम्मेदारियों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए सराही जाती रही हैं।

अपने दमदार मुक्कों से विरोधी खिलाड़ियों को पस्त कर ढेरों मेडल जीतने वाली 29 साल की रीना शर्मा का आज हर कोई मुरीद है। कहती हैं, जिंदगी में लक्ष्य को पाने की हसरतें बुलंद हों तो मुश्किल हालात भी कोई मायने नहीं रखते। बेटियां अब आसमां छू रही हैं। मैंने भी दो बेटियां होने के बाद कई मेडल जीते हैं। छह बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम हमारे सामने जीता जागता उदाहरण हैं...।

पति मोहन शर्मा, बड़ी बेटी तनवी और छोटी बेटी यशवी के साथ अपने मेडल दिखातीं रीना। संजय घिल्डियाल

हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मी रीना की जिंदगी का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मंजिल की ओर बढ़ती जा रही हैं। दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में रीना ने संघर्ष के दिनों से अब तक बॉक्सिंग से जुड़े अनुभवों को साझा किया।

झज्जर जिले के बापड़ौदा गांव में जन्मी रीना बताती हैं, हम चार बहनें और एक भाई है। परिवार के आर्थिक हालात भी अच्छे नहीं रहे। पिता जयकवार शर्मा ने डीटीसी में ड्राइवर की नौकरी करते हुए मुझे बॉक्सर बनाने के सपने को पूरा किया। उन दिनों में लड़कियां बॉक्सिंग में न के बराबर होती थीं, खासकर हरियाणा में, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ब्रह्मप्रकाश ने मेरी प्रतिभा को परखते हुए जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा। पहले ही टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा...। रीना ने अभी तक विभिन्न टूर्नामेंट में 25 से अधिक मेडल जीते हैं जिनमें 15 गोल्ड मेडल हैं। अगला टारगेट साउथ एशियन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर वर्ल्ड पुलिस गेम्स का टिकट पक्का करना है। पति मोहन शर्मा भी पुलिस विभाग में पदस्थ हैं। बकौल रीना, पति ने हर मुश्किल में साथ दिया और हौसला बढ़ाया। रीना 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई और इतने साल में खेल कोटे से बॉक्सिंग में प्रमोशन पाने वाली पहली महिला हैं। शाकाहारी भोजन करती हैं।

25 पदक जीत चुकीं दो बच्चों की मां रीना, मुक्के का दम देख चंडीगढ़ पुलिस ने प्रमोशन देकर बनाया है हेड कांस्टेबल

दोनों बेटियों को मानती हैं अपनी ताकत

रीना की दो बेटियां, छह साल की तनवी और आठ महीने की यशवी हैं। रीना कहती हैं कि जब मैरीकॉम मां बनने के बाद भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं तो कोई भी ऐसा कर सकती है। दरअसल, मेरी दोनों बेटियां ही मेरी ताकत हैं, जो मुझे लड़ने और जीतने की प्रेरणा देती हैं। पति भी प्रोत्साहित करते हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

दिल्ली की रेडिकल फूड के खिलाफ 819 करोड़ की जालसाजी का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने दिल्ली की रेडिकल फूड लिमिटेड के खिलाफ 819 करोड़ रुपये की जालसाजी का मामला दर्ज किया है। बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से सीबीआइ को मिली शिकायत पर जांच एजेंसी ने तलाशी भी ली है। रेडिकल फूड लिमिटेड का नई दिल्ली के साकेत में कार्यालय है।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके निदेशक सिद्धार्थ चौधरी एवं अंजू चौधरी ने 732 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इन लोगों ने जाली दस्तावेज को असली की तरह पेश कर एसबीआइ एवं अन्य बैंकों के साथ जालसाजी की। बैंक के कंसोर्टियम में एसबीआइ, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, एक्जिम बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीएसबी बैंक, विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) और यूको बैंक शामिल हैं।

563 निजी आइडी का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपर की ओर से इस्तेमाल किया गया गलत तरीके से ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए। हालिया खबरों के अनुसार, रेलवे टिकटों के काला कारोबार का टेरर फंडिंग से नाता होने की बात कही गई है।

मन के साथ काम की बात भी जरूरी : गहलोत

- राजस्थान के सीएम ने किया समारोह का उद्घाटन
- पांच दिवसीय आयोजन में 500 वक्ता रखेंगे बात

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल

मनीष गोधा, जयपुर

साहित्य का कुंभ कहे जाने वाले 'जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल' की गुरुवार को जयपुर के डिग्गी पैलेस में शुरुआत हुई। राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली कला के प्रदर्शन और महात्मा गांधी के प्रिय भजन 'वैष्णव जन...' के साथ फेस्टिवल शुरू हुआ। उद्घाटन करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह ऐसा आयोजन है, जिसका हम सालभर इंतजार करते हैं, ताकि मन की बात कह सकें, लेकिन मन की बात के साथ काम की बात भी होनी चाहिए। यह फेस्टिवल राजस्थान की पहचान बन चुका है।

इस मौके पर गहलोत ने राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक विजयदान देथा की किताब 'बातां री फुलवारी' के अंग्रेजी अनुवाद 'टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़' का लोकार्पण भी किया। यह अनुवाद विशेष कोठारी ने किया है। गहलोत ने देथा को भी याद किया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का यह 13वां संस्करण है। इस बार दुनियाभर के करीब 500 वक्ता यहां पांच दिन में होने वाले 200 से ज्यादा सत्रों में अपनी बात रखेंगे। फेस्टवल के निदेशक संजोय के. राय ने कहा कि गांधी के देश में नफरत बढ़ना चिंताजनक है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि चुप न रहें। हमें एक-दूसरे की आवाज बनकर बोलना है और प्यार की भाषा बोलनी है। फेस्टिवल सह निदेशक नमिता गोखले और विलियम डेरम्पिरल ने कहा कि भारत में साहित्य की मौखिक परंपरा बहुत गहरे उतरी हुई है और यही कारण है कि यह फेस्टिवल सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। प्रेट्र

जब तक कला समृद्ध है, भविष्य बेहतर है : उद्घाटन सत्र की मुख्य वक्ता शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल ने कला के विभिन्न स्वरूपों के आपसी संबंध के बारे में कहा कि हर कला आपस में जुड़ी हुई हैं। शिल्प, चित्रकला, नृत्य और संगीत सभी आपस में जुड़े हैं और कोई ऊपर नहीं है। हालांकि, गायन को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन मैं कला जगत में किसी पदानुक्रम की पक्षधर नहीं हूं और मानती हूं कि हर कला आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। सत्र के दूसरे प्रमुख वक्ता गणितज्ञ मार्कोस डू सोएटे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में 'गणित में कविता' और 'कविता में गणित' है। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एस. रामानुजन कहा करते थे कि गणित में हर अंक की अपनी कहानी होती है।

स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ाई : फेस्टिवल में इस बार सामान्य पास के लिए फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। ऐसे में 23, 24 और 27 जनवरी के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फीस इस बार 500 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी गई है, जो पिछले साल 300 रुपये थी। फेस्टिवल के शुरुआती वर्षों में यह मुफ्त हुआ करता था। वहीं 25 और 26 यानी साप्ताहांत पर प्रति व्यक्ति टिकट की दर 300 रुपये बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है।

सावरकर को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा : परांजपे

जागरण संवाददाता, जयपुर : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर पर एक सत्र हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मकरंद आर. परांजपे ने कहा कि सावरकर को राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार निशाना बनाया जाता है, जबकि भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया उनका योगदान किसी से कम नहीं। यह बात 'विवेकानंद, सावरकर एंड पटेल : एकोज फ्रॉम द पास्ट' में परांजपे ने विक्रम संपत और हिंदोल सेनगुप्ता से बातचीत में कही। स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीर सावरकर पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने इन्हें भारत की मूल आत्मा को बचाए रखने वाले नेतृत्वकर्ता बताया। यदि अपने-अपने समय में ये न होते तो भारत का मूल विचार बहुत हद तक प्रभावित हो जाता। परांजपे ने कहा- 'सावरकर ने ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल ने भी दया याचिका दायर की थी, किंतु सावरकर की दया याचिका को इसलिए बार-बार चर्चा में लाया जाता है ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। यह सब एक तरह की नादानी, चालाकी और षड्यंत्र है।'

खोल के मुट्ठी नारों वाली, बैठो ना कुछ बात करें : प्रसून जोशी

जागरण संवाददाता, जयपुर

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन गुरुवार को तमाम सत्रों के बीच प्रसिद्ध गीतकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी का सत्र सबसे आकर्षक रहा। जोशी ने देश के वर्तमान हालात पर दिलचस्प टिप्पणी की। वे देश में नाराज होकर नारे लगाने वाले लोगों की ओर इशारा करते हुए कविताई अंदाज में बोले, 'बैठो ना कुछ बात करें, अंधियारे को मात करें, खोल के मुट्ठी नारों वाली, हाथों में अब हाथ धरें। बैठो ना कुछ बात करें'।

जोशी ने इशारों-इशारों में देश में प्रदर्शन कर रहे लोगों को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा- यह देश कभी टोलरेंस यानी किसी को बर्दाश्त न करने वाली संस्कृति वाला रहा ही नहीं। हम तो हमेशा से अंगीकार करने वाले रहे हैं। इसलिए इस देश को वैसा मत बनाइए, जैसा ये कभी नहीं था और जैसी इसकी संस्कृति कभी नहीं थी। प्रसून से वाणी त्रिपाठी टिक्कू ने बात की।

सिर्फ देश के लिए जीते हैं प्रधानमंत्री मोदी : एक श्रोता ने प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेते समय क्या आप पर दबाव था? इस पर प्रसून ने कहा- 'भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हों या विरोधी, लेकिन कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीते हैं। उनका निजी कुछ भी नहीं। उनमें लेशमात्र स्वार्थ नहीं।' प्रसून ने विपक्ष व 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' की ओर इशारा किए बिना कहा- 'असहमति में भी गरिमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में कुछ भी कह दिया जाए।' उन्होंने देश में बेजा विरोध कर रहे लोगों की ओर संकेत किया कि देश में सबको साफ मन से रहना होगा। मन में बैर रखेंगे तो दूसरों के मन में संदेह पैदा होगा।

एक सत्र के दौरान प्रसून जोशी। एएनआइ

न्यूज गैलरी

रवीना टंडन और फराह खान को हाई कोर्ट से राहत

चंडीगढ़ : अभिनेत्री रवीना टंडन और कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक फराह खान को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार वर्मा ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की है। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में 25 दिसंबर को दर्ज एफआइआर रद कराने के लिए रवीना टंडन व फराह खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा है कि आरोप आधारहीन हैं। टीवी शो में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से कुछ नहीं किया। दोनों वेब शो 'बैक बैंचर्स' में गेस्ट और एंकर हैं। (राब्यू)

किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी : हेमंत

प. सिंहभूम : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में हुए नरसंहार के दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी राज्य में काननू व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हेमंत गुरुवार को नरसंहार पीड़ितों से मिलने पश्चिमी सिंहभूम जिले के बुरुगुलीकेरा गांव पहुंचे थे। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के जान माल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री गांव पहुंचकर सीधे मृतकों के स्वजन के पास पहुंचे। उनके पास जमीन पर बैठकर इस निर्मम घटना की जानकारी ली। मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री ने पत्थलगड़ी के विरोध के कारण हत्या किए जाने की बात से इन्कार किया। जांच टीम पता करेगी कि सही कारण क्या है। (जासं)

स्वामी चिन्मयानंद ने दाखिल की पैरोल अर्जी

प्रयागराज : दुष्कर्म मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने हाई कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दाखिल की है। उनकी ओर से नियमित जमानत अर्जी देने की याचिका पर हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। फैसला आने में हो रहे विलंब के चलते उन्होंने पैरोल अर्जी दाखिल कर कुछ समय के लिए जेल से रिहा करने की मांग की है। अर्जी में उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि उनको इलाज के लिए कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए। अर्जी पर 27 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित स्वामी चिन्मयानंद लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनकी जमानत सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। हाई कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। (जासं)

छत्तीसगढ़ में अब मीसा बंदियों को नहीं मिल पाएगी पेंशन

फैसला ▸ कांग्रेस सरकार ने रद किया पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का अध्यादेश

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्य में मीसा बंदियों की पेंशन योजना को पूरी तरह बंद कर दिया है। सरकार ने गुरुवार को एक अध्यादेश जारी कर उस नियम को ही खत्म कर दिया है, जिसके तहत पेंशन दी जा रही थी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2008 में मीसा बंदियों को पेंशन देने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्य के करीब सवा तीन सौ लोगों को 15 से 25 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही थी। हालांकि, राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद एक जनवरी 2019 से सरकार ने इस पेंशन पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं।

सत्ता परिवर्तन के साथ ही बंद हुई पेंशन : छत्तीसगढ़ ही नहीं मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन के साथ ही मीसा बंदियों को दी जा रही पेंशन सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार के इस फैसले को मीसा बंदियों ने वहां हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मीसा बंदियों की पेंशन रोके जाने के खिलाफ इस वक्त छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में 40 याचिकाएं दायर की गई हैं। यह याचिकाएं मीसा बंदी और उनकी विधवा पत्नियों ने दायर की हैं। नियमानुसार मीसा बंदी की विधवाओं को आधी पेंशन पाने का अधिकार है।

> मीसा बंदियों को पेंशन देने के संबंध में कोई काननू नहीं बना था। अध्यादेश के जरिये नियम बनाया गया था। इस सरकार ने उस अध्यादेश को रद कर दिया है। यह सरकार का अधिकार है। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
> -सच्चिदानंद उपासने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लोकतंत्र सेनानी संघ

325 के करीब हैं राज्य में मीसा बंदी, 15 हजार रुपये पेंशन मिलती थी छह माह से कम जेल काटने वालों को

25 हजार रुपये मिलती थी छह माह से अधिक जेल में समय बिताने वालों को

01 जनवरी 2019 से ही नहीं दी जा रही थी पेंशन

कोर्ट ने दिया है बकाया देने का निर्देश : हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 में राज्य सरकार को भौतिक सत्यापन कर पेंशन और एरियर्स देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश सरगुजा के मीसाबंदी असित भट्टाचार्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था।

बकाया पेंशन की मांग करेंगे : पेंशन देने के संबंध में जारी अध्यादेश को रद किए जाने के बाद अब मीसा बंदी करीब एक वर्ष से रोकी गई पेंशन राशि देने की मांग करने की तैयारी में हैं। मीसा बंदियों के संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने अध्यादेश को 23 जनवरी 2020 को रद किया है, जबकि हाई कोर्ट ने पहले ही पेंशन और एरियर्स देने का आदेश दिया था। हम उस आदेश का सरकार से पालन कराने की कोशिश करेंगे।

कौन हैं मीसा बंदी : मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने बनाया था। इससे सरकार को असीमित अधिकार मिल गए। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया। इसका विरोध करने वालों को जेल में बंद कर दिया गया था, जिन्हें मीसा बंदी कहा गया।

अजहर ने धोखाधड़ी का आरोप नकारा, मानहानि केस की धमकी

- औरंगाबाद की ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने बुधवार को दर्ज कराई थी एफआइआर
- पूर्व सांसद ने कहा, सुर्खियों में बने रहने के लिए कराई गई एफआइआर

हैदराबाद, आइएएनएस : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व सांसद मुहम्मद अजहरुद्दीन ने महाराष्ट्र की एक ट्रैवल एजेंसी की ओर से लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप से इन्कार किया है। साथ ही उन्होंने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दायर करने की धमकी भी दी है।

ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर अजहरुद्दीन ने गुरुवार को कहा, 'जिन्होंने भी एफआइआर दर्ज कराई है, उन्होंने ऐसा सुर्खियों में बने रहने के लिए किया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरोप बेबुनियाद हैं।' वर्तमान में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजहरुद्दीन ने कहा कि वह अपने वकील से सलाह लेंगे और उन लोगों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दायर करेंगे जिन्होंने एफआइआर दर्ज कराई है।

मालूम हो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बुधवार को अजहरुद्दीन और दो अन्य के खिलाफ एक स्थानीय ट्रैवल एजेंट से करीब 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। यह शिकायत दानिश टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक शहाब वाई. मुहम्मद (49) ने दर्ज कराई है। वह बंद हो चुकी जेट एयरवेज के पूर्व एक्जीक्यूटिव भी हैं। औरंगाबाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एडी नागरे ने बताया, 'हमने मुजीब खान (औरंगाबाद), सुधीश अविक्कल (केरल) और मुहम्मद अजहरुद्दीन (हैदराबाद) के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और जांच जारी है।' शिकायत के मुताबिक, नौ नवंबर से 12 नवंबर, 2019 के बीच अविक्कल ने अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के कई टिकट बुक कराए थे और अजहरुद्दीन के निजी सचिव मुजीब खान ने टिकटों का शुल्क अदा करने का वादा किया था। शहाब ने बताया कि तब से अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है लिहाजा वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर था।

मुहम्मद अजहरुद्दीन। फाइल

देविंदर सहित पांच लोग 15 दिन की रिमांड पर

राज्य ब्यूरो, जम्मू : आतंकियों का साथ देते हुए पकड़े गए दागी डीएसपी देविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीद बाबू समेत पांच लोगों को गुरुवार को एनआइए की विशेष अदालत ने 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। देविंदर सिंह व उनके आतंकी साथियों को गत बुधवार को ही एनआइए श्रीनगर से जम्मू लाई थी।

निलंबित देविंदर सिंह के अलावा हिजबुल कमांडर नवीद मुश्ताक शाह उर्फ नवीद बाबा उर्फ नवीद बाबू, हिजबुल आतंकी रफी अहमद राथर, लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर इरफान शफी मीर और नवीद के भाई सईद इरफान अहमद उर्फ इरफान को पहले सुबह जानीपुर कोर्ट परिसर में एनआइए अदालत में पेश किया जाना था। किन्हीं कारणों से पांचों की पेशी शाम सवार चार बजे हुई।

अधिकारियों ने बताया कि एनआइए की अदालत में पेश किए गए पांच आरोपितों में सईद इरफान अहमद उर्फ इरफान को बड़ी आतंकी साजिश में शामिल होने व आतंकियों को शरण देने के मामले में गिरफ्तार किया है। इरफान हिजबुल कमांडर नवीद मुश्ताक बाबा का छोटा भाई है। वह नवीद और देविंदर के बीच संपर्क का जरिया था। किसी मिशन विशेष के लिए उनकी यात्रा का बंदोबस्त करता था। विशेष जज एनआइए अदालत सुभाष चंद ने कहा कि एनआइए द्वारा रिमांड का आग्रह न्यायोचित है। ऐसे में सभी आरोपितों को 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है।

चंडीगढ़ में कारोबारी की पत्नी, बेटा व बेटी की गला रेतकर हत्या

- कारोबारी ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, देर रात पीजीआइ में तोड़ा दम
- हरियाणा के कैथल की थी कारोबारी संजय की पत्नी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

शहर के मनीमाजरा स्थित मॉडर्न कांप्लेक्स के फ्लैट नंबर-5012 में बुधवार देर रात कारोबारी की पत्नी, बेटी और बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस को वारदात की सूचना तब मिली जब पता चला कि कारोबारी सुरेंदर उर्फ संजय अरोड़ा पीजीआइ में उपचाराधीन है। उसने बुधवार रात को ही ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी। गुरुवार रात पीजीआइ में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। फ्लैट से मिले सुसाइड नोट में ऑर्थिक तंगी से परेशान होने की बात लिखी गई है।

संजय अरोड़ा की पंचकूला सेक्टर-9 में कृष्णा बेकरी के नाम से शॉप है। इस बेकरी को सात साल की लीज पर चला रहे कर्मवीर के पास पीजीआइ से कॉल आई कि संजय अरोड़ा को ट्रेन की चपेट में आने के कारण गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। वह तुरंत पीजीआइ के लिए निकल गया। इस बीच उसने संजय के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल पर जवाब न मिलने पर वह तुरंत मनीमाजरा स्थित फ्लैट पर जा पहुंचा। उसने देखा कि मुख्य गेट का ताला बाहर से बंद है और अंदर लाइटें ऑन थीं। दरवाजे के बाहर फर्श पर खून पड़ा था। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट का ताला तोड़ा तो देखा कि संजय की 22 वर्षीय बेटी रतना उर्फ सांची का शव मुख्य गेट के पास पड़ा था। कमरे में 45 वर्षीय पत्नी सुनीता व 16 वर्षीय बेटे अर्जुन के शव पड़े मिले। अर्जुन स्कूल ड्रेस में था। तीनों का गला रेता गया था।

हत्यारे के साथ रतना की हुई थी हाथापाई

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सबसे पहले संजय की पत्नी, उसके बाद बेटे और फिर बेटी की हत्या की गई है। हत्यारे ने बेटी पर रॉड से भी हमला किया। इस दौरान दोनों की हाथापाई भी हुई थी।

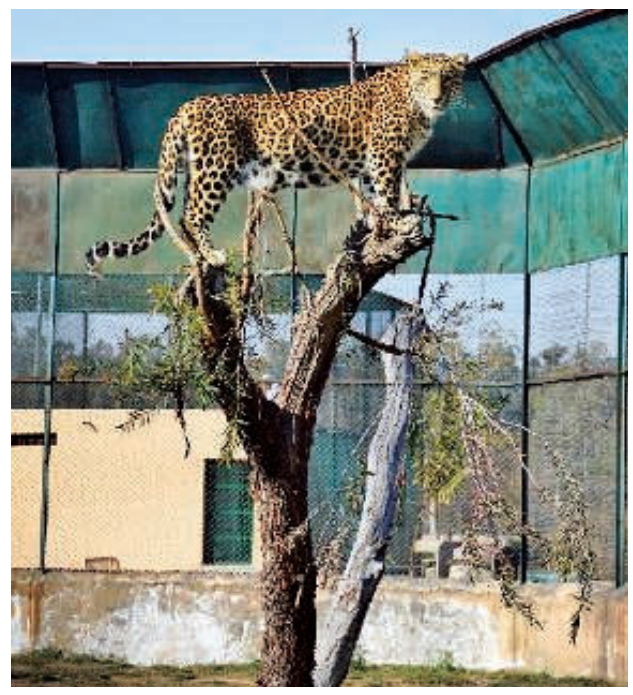

धूप सेंकने पेड़ पर चढ़ी मादा तेंदुआ

हरियाणा में कई दिन बाद गुरुवार को आसमान साफ हुआ तो हर किसी ने गुनगुनी धूप का आनंद उठाया। ऐसे में रोहतक के चिड़ियाघर में यह मादा तेंदुआ कैसे पीछे रहती। बाड़े के चारों ओर लगी ऊंची रेलिंग जब धूप में बाधा बनी तो वह पेड़ पर ही चढ़ गई। संजय शर्मा

साईबाबा जन्मस्थान विवाद हाई कोर्ट जाएंगे पाथरीवासी

- सीएम उद्धव ठाकरे के मिलने से इन्कार के बाद लिया फैसला
- कहा, विकास राशि मिले या नहीं, पर जन्मस्थान का दावा नहीं छोड़ेंगे

औरंगाबाद, प्रेट्र : साईबाबा के जन्मस्थान को लेकर जारी विवाद में नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव के लोगों ने इस विवाद का समाधान तलाशने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।

साई जन्मभूमि पाथरी संस्थान के सदस्यों ने बताया कि वे बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के समक्ष साक्ष्यों के साथ याचिका दाखिल करेंगे और प्रमाणित करेंगे कि साईबाबा का जन्म पाथरी में ही हुआ था। पाथरी निवासी कुछ लोगों का कहना है कि शिरडी मंदिर ट्रस्ट के दबाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बयान से पीछे हटे हैं।

विधानपरिषद सदस्य और कार्यसमिति के अध्यक्ष बाबाजानी दुर्रानी ने भी कहा कि पाथरी के लोग जन्मस्थान के मुद्दे पर कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा, 'शिवसेना सासंद संजय जाधव ने एक मुलाकात के दौरान सीएम ठाकरे से कहा था कि पाथरीवासी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ठाकरे ने मुलाकात से इन्कार करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विवाद न पैदा किया जाए।'

दुर्रानी ने कहा, 'ठाकरे ने जब मुलाकात से मना कर दिया तो हमने इस मुद्दे का कानूनी तौर पर समाधान निकालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'अगर सरकार धन जारी न भी करे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हम यह दावा कभी नहीं छोड़ेंगे कि पाथरी ही साईबाबा का जन्मस्थान है।'

बांबे हाई कोर्ट। फाइल

उल्लेखनीय है कि नौ जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ठाकरे ने कहा था कि पाथरी को साईबाबा का जन्मस्थान माना जाता है और उसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया कि शिरडी साईबाबा संस्थान के पास 2,600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिससे सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। शिरडी साईबाबा के कारण धनी बनी और जिस जगह पर संत ने अंतिम सांस ली उससे संपन्नता कोई नहीं छीन सकता।

राम मंदिर

कई संतों ने जताई भव्य और गगनचुंबी मंदिर की इच्छा, विहिप का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल पुराने मॉडल के पक्ष में

पुराने मॉडल छोड़, आकांक्षा भव्य मंदिर की

रघुवरशरण, अयोध्या

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने रामजन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर के पुराने मॉडल के प्रति मोह जरूर जताया है लेकिन कई संत चाहते हैं कि वहां गगनचुंबी भव्य मंदिर बनाया जाए। इन्हीं जनआकांक्षों को देखते हुए पुराना मॉडल अब उन्हें छोटा प्रतीत होता है जिसके अनुरूप रामघाट स्थित रामजन्मभूमि न्यास कार्यशाला में शिलाओं को गढ़ने का काम 1991 से शुरू हुआ।

रामजन्मभूमि न्यास के ही सदस्य पूर्व सांसद डॉ. रामविलासदास वेदांती ने तो उसकी माप भी निर्धारित की। उनके मुताबिक राममंदिर के शिखर की ऊंचाई 1011 फीट तथा उसका विस्तार दो सौ एकड़ में होना चाहिए। रामालय न्यास के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी पीछे नहीं रहे।

उन्होंने मंदिर को 1008 फीट ऊंचा बनाए जाने की वकालत करने के साथ कहा कि यह इतना विशाल हो कि इसमें एक साथ एक लाख आठ हजार श्रद्धालु रुक सकें। इतने ही लोगों के भोजन के लिए विशाल आगार और विशाल सीता रसोई भी संयोजित हो। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बार-बार रामलला के गगनचुंबी मंदिर की संभावना जताते रहे हैं। अब संत भी पुराने मॉडल का मोह छोड़कर भव्य राम मंदिर निर्माण की आकांक्षा जता रहे हैं।

प्रतीकात्मक।

लेकिन, गत सोमवार को प्रयाग में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में विहिप समर्थक संतों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें उसी मॉडल के अनुरूप मंदिर मंजूर होगा, जिसके आधार पर दशकों तक मंदिर आंदोलन चला। ऐसे में यह तय है कि मंदिर निर्माण के लिए संभावित शासकीय ट्रस्ट को दोनों ओर से दबाव का सामना करना पड़ेगा।

भव्यतम मंदिरों के आगे नहीं ठहरता न्यास का मंदिर

रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित मंदिर 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा एवं 128 फीट ऊंचा है। प्रस्तावित मंदिर का यह आकार भव्यता की श्रेणी में तो रखा जा सकता है, पर जब दुनिया के भव्यतम मंदिरों से तुलना का सवाल हो तो यह मंदिर कहीं नहीं ठहरता। न्यास का प्रस्तावित मंदिर सवा एकड़ क्षेत्र में है। दुनिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर पांच सौ एकड़ में है।

दोनों युवक भी संदेह के घेर में

प्रथम पृष्ठ से आगे

आयकर विभाग ने दोनों युवकों को भी संदेह के दायरे में रखा गया है। टैक्स वसूली के लिए उन्हें क्रमश: 3.5 करोड़ एवं 1.06 करोड़ रुपये जमा कराने के नोटिस दिए गए हैं। विभाग ने उन पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर ली है। इन युवकों का दावा है कि मुंबई एक्सिस बैंक के जिस खाते में यह भारी भरकम राशि जमा हुई, वह उनके नाम पर खोले गए फर्जी खाते थे।

सीबीआइ को दिया आवेदन : मामला 2011-12 का है, जब दोनों युवकों के खाते में यह राशि जमा हुई। तब दोनों युवक इंदौर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी टेली परफार्मेंस कंपनी में काम करते थे। एक युवक रवि गुप्ता ने पुलिस और सीबीआइ को आवेदन देकर कहा है कि इस मामले में वह बेकसूर है, उसके नाम पर फर्जी खाते किसने और क्यों खोले? और इतनी बड़ी राशि कहां से आई और कहां गई? इसकी जांच कराई जाए। इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा तथा बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मैदानी भागों में ठंडी तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। खिली धूप के साथ दिन का मौसम सुहावना बना रहेगा। कोहरे का असर नहीं रहेगा।

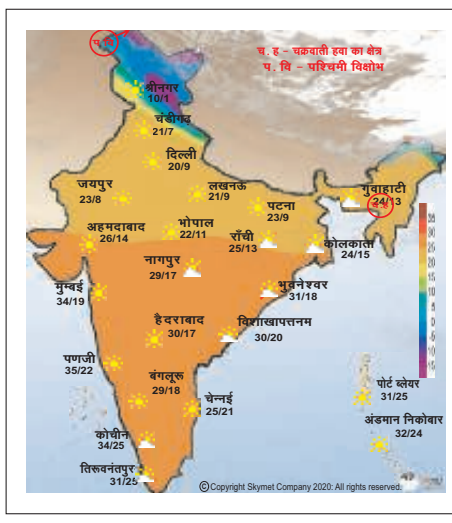

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/20/आंबा	अहमदाबाद	24/12/आंबा
कोलकाता	25/16/सा	बड़ौदा	24/11/आंबा
चेन्नई	31/23/आंबा	नागपुर	30/18/आंबा
हैदराबाद	31/18/सा	इन्दौर	26/11/व
बंगलूरू	30/17/सा	राँची	28/15/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	25/13/व
गुवाहाटी	24/14/आंबा	जमशेदपुर	30/15/आंबा
गंगटोक	05/-6/सा	पुणे	28/17/आंबा

दैनिक जागरण
समरसता ही समाज को समृद्धि की राह पर अग्रसर कर सकती है

कश्मीर में नई पहल

दावोस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के समक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कश्मीर को लेकर दिया गया बयान कितना निरर्थक है, इसका प्रमाण खुद अमेरिकी संसद को विदेश मामलों में सलाह देने वाली एजेंसी का यह आकलन है कि पाकिस्तान के विकल्प सीमित हैं। इस अमेरिकी एजेंसी का यह भी मानना है कि कश्मीर पर बेलगाम हो रहे पाकिस्तान को इसलिए कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि उसके साथ-साथ चीन का दामन भी दागदार है। इसका आभास चीन को भी हो जाना चाहिए, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मसले पर चर्चा कराने की नाकाम कोशिश के बाद। ऐसी ही नाकामी का सामना मलेशिया और तुर्की भी कर चुके हैं जो इस्लामी जगत में अपनी अहमियत दर्शाने के लिए पाकिस्तान की हां में हां मिला रहे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफल रहने के बावजूद भारत को कूटनीति मोर्चे पर उसी तरह सक्रियता दिखानी होगी जैसी उसने गत दिवस अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को महत्वहीन करार देकर दिखाई। कश्मीर पर अनावश्यक टीका-टिप्पणी कर रहे देश जितनी जल्दी यह समझें तो बेहतर कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर अपने उन्हीं अधिकारों का ही इस्तेमाल किया है जो एक संप्रभु देश के रूप में उसे हासिल हैं। यह बुनियादी बात अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भी समझनी होगी, जो समस्या के मूल कारणों पर गौर किए बगैर यह दिखाने की कोशिश कर रहा जैसे भारत की केंद्रीय सत्ता ने कश्मीर के अधिकारों में बेजा कटौती कर दी है।

यह साफ है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का एक हिस्सा जानबूझकर यह समझने को तैयार नहीं कि कश्मीर समस्या वास्तव में जम्मू और लद्दाख की भी समस्या थी। वह अपने एजेंडे के तहत इस तथ्य से भी मुंह मोड़ रहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था। अज्ञानता, अहंकार और ईर्ष्या से उपजे इस एजेंडे को नाकाम करने के लिए यह भी आवश्यक है कि कश्मीर के हालात सामान्य बनाने के लिए और अधिक तत्परता का परिचय दिया जाए। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्रियों को जम्मू-कश्मीर भेजने की पहल उल्लेखनीय है। इससे एक ओर जहां राज्य के लोगों में यह भरोसा बढ़ेगा कि केंद्रीय सत्ता उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री भी इससे अवगत होंगे कि उनके विभागों से संबंधित योजनाएं जमीन पर कितना असर कर रही हैं? अच्छा होगा कि केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू-कश्मीर जाने का सिलसिला कायम रहे। अब जब घाटी में आतंकी तत्व पस्त पड़ रहे हैं तब वहां के लोगों को केवल यह प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए कि उनकी समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, बल्कि उन्हें अपनी समस्याएं हल होती भी दिखनी चाहिए।

पर्यटन उद्योग को उम्मीद

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी यहां के सुधर रहे हालात और लोगों के बीच पहुंच रहे सकारात्मक संदेश का परिणाम है। विगत दो महीने में ही यहां पर देसी-विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। पिछले वर्ष अगस्त में जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या न के बराबर रह गई थी। केंद्र सरकार ने स्वयं ही पर्यटकों को यहां पर न आने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। कई देशों ने भी हालात को देखकर अपने नागरिकों को कश्मीर में जाने से मना कर दिया था। अच्छी बात यह है कि केंद्र एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाद अब पूरे जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है। पहले कश्मीर में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल करना, फिर राजनीतिक कैदियों की धीरे-धीरे रिहाई शुरू करना और अब 12 जिलों में 2जी मोबाइल इंटरनेट की सुविधा शुरू करना इसी का परिणाम है। इससे देश-विदेश में यह संदेश जा रहा है कि अब कश्मीर के हालात में सुधार हो गया है। यही नहीं इस बार समय पर हुई बर्फबारी ने सोने पर सुहागे जैसा काम किया है। कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को भी उम्मीद बंध गई है। यह सर्वविदित है कि पर्यटन पर यहां के लाखों लोग निर्भर है और पर्यटन उद्योग जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में रीढ़ का काम करता है। उपराज्यपाल प्रशासन भी इससे भलीभांति परिचित है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में रोड़ शो भी कर रहा है। इससे यह उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर में अब पहले से भी अधिक पर्यटक आकर यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेंगे। कुछ महीने में ही वैश्विक निवेशक सम्मेलन भी आयोजित होने जा रहा है। अगर इस क्षेत्र में निवेश के लिए औद्योगिक घराने आगे आते हैं तो आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है।

केंद्र एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाद अब पूरे जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है। इससे देश-विदेश में यह संदेश जा रहा है कि अब कश्मीर के हालात में अपेक्षित सुधार हो गया है

दूर होती नहीं दिखती कांग्रेस की दुविधा

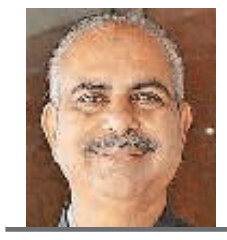

रशीद किदवई

कांग्रेस को यह सोचना होगा कि क्या कारण है कि देश का जो युवा भाजपा से नाराज नजर आता है वह उसे एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहा?

कांग्रेस के वैचारिक और व्यावहारिक चुनौतियों से जूझने का सिलसिला कायम है। जहां एक तरफ भाजपा में नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया और जेपी नड्डा ने पार्टी की कमान भी संभाल ली वहीं कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठे सवालों का समाधान होता नहीं दिखता। नड्डा के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी अपने संसदीय बोर्ड में रिक्त पदों को भरने वाली है, लेकिन कांग्रेस 1991 के बाद से ही अपने संसदीय बोर्ड का चयन करने में असमर्थ है। बात केवल इतने तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को यह समझ नहीं आ रहा है कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों को पराजित करे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ कोई ऐसा तालमेल करे जिससे भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने से वंचित किया जा सके।

महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के गठबंधन वाली साझा सरकार को लगातार झटके लग रहे हैं। कांग्रेस शिवसेना नेता संजय राउत के तीखे बयानों का सही तरह जवाब नहीं दे पा रही है। इंदिरा गांधी की विरासत के दावेदार राहुल गांधी से आदित्य ठाकरे दो बार मिल चुके हैं, लेकिन गठबंधन में परस्पर विश्वास और टीम भावना का अभाव साफ दिख रहा है।

दिल्ली में शाहीन बाग और अन्य स्थानों पर नागरिकता संशोधन कानून का जो विरोध हो रहा है और जिनमें कांग्रेसी नेता शिरकत कर रहे हैं उसे लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं दिख रही कि इससे उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा ही। शाहीन बाग धरने में मणिशंकर अय्यर का जाना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। दरअसल मणिशंकर अय्यर की कांग्रेस में कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन टीवी चैनलों की बहस में वह कांग्रेस के एक मुख्य पात्र बन जाते हैं। खुद मणिशंकर अय्यर को भी इस बात का अंदाजा है कि कांग्रेस में उन्हें अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता। एक बार उनसे पूछा गया था कि वह राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समय की तुलना कैसे करते हैं तो उनका जवाब था कि राजीव गांधी के समय मैं अर्श पर था और अब मैं फर्श पर हूं।

वास्तव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस में उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन कांग्रेस उनसे अपना दामन छुड़ाना भी नहीं चाहती। मणिशंकर अय्यर रह-रहकर पाकिस्तान जाते रहते हैं। वह वहां के नेताओं और बुद्धिजीवियों से मिलते हैं। वह वहां पर और साथ ही वहां से लौटकर ऐसे बयान देते हैं जो अक्सर सुर्खियां बन जाते हैं। हाल में वह पाकिस्तान से लौटकर शाहीन बाग धरने में गए और वहां उन्होंने भाषण भी दिया। कांग्रेस को समझ नहीं आया कि वह उनके इस भाषण का स्वागत करे या विरोध? संकट केवल इतना ही नहीं है। दिल्ली में शाहीन बाग और देश के अन्य स्थानों पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में जो धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं उन्हें लेकर भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वह उनका विरोध करे या समर्थन?

अवधेश राजपूत

आस्था एक बड़ा निजी और महत्वपूर्ण मामला होता है। यदि धर्म से जुड़ी हुई मान्यताओं को हम राष्ट्रवाद के विरुद्ध मानेंगे तो उससे तरह-तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। भारत जैसे देश जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हों वहां धार्मिक और क्षेत्रीय भावनाएं होना कोई अचरज की बात नहीं है। किसी खास परिस्थिति में धर्म से जुड़े नारे, जैसे 'जो बोले से निहाल', 'हर-हर महादेव' या 'अल्लाह ओ अकबर' लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी फौज में विभिन्न रेजीमेंट्स जो है भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्घोष करती हैं, खास तौर पर दुश्मन को मजा चखाने के समय। इन नारों को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। इस संबंध में जो उदारवादी लिबरल सोच है वह मूल रुप से धर्म और आस्था के विरुद्ध जाती है और यहां पर कांग्रेस दो पाटों के बीच में पिसती नजर आती है। उसे लगता है कि किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ कोई नारा अल्पसंख्यकों अथवा बहुसंख्यकों द्वारा गलत समझा जा सकता है और वह रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस उनसे कन्नी काट रही है। शशि थरूर ऐसे नारों का विरोध कर रहे हैं। वह एक विद्वान नेता की छवि रखते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के लिहाज से वह नौसिखिये प्रतीत हो रहे हैं।

कांग्रेस की एक समस्या यह है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों और विशेष रूप से युवाओं में पार्टी को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि क्या कारण है कि देश का जो युवा भाजपा से नाराज नजर आता है वह कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में क्यों नहीं देख रहा है और वह भी तब जब कांग्रेस में राहुल गांधी जैसा एक युवा नेता है?

कांग्रेस को इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या कारण है कि जहां एक तरफ भाजपा को नड्डा को अपना नया अध्यक्ष चुनने में कोई परेशानी नहीं हुई वहीं कांग्रेस राहुल गांधी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने में हिचक रही है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस अपने संगठन के चुनाव से पीछे हट रही है? क्या वजह है कि राहुल गांधी के 2003 से ही राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद आज तक कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बन पाए हैं?

दरअसल सोनिया गांधी जोखिम उठाने की राजनीति से बचती नजर आ रही हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की मानें तो कांग्रेस गर्म खिचड़ी को किनारे-किनारे से खा करके ही संतुष्ट होना चाहती है। महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में सत्ता में भागीदारी के बाद कांग्रेस दिल्ली में उस मॉडल को दोहराना चाह रही है जो उसने 2013 में अपनाया था और जिसके तहत केजरीवाल सरकार को समर्थन दिया था। कांग्रेस को लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने बलबूते बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे और ऐसे में उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बन पाएगी। बिहार के मामले में भी कांग्रेस का ऐसा ही कुछ आकलन है। उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा में कुछ खटपट जरूर होगी और उसे वहां की सत्ता में शामिल होने का कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन क्या दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी का रास्ता कांग्रेस को कभी भाजपा के विकल्प के रूप में पेश कर पाएगा? यह वह सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी दे सकते हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विजिटिंग फेलो हैं)

response@jagran.com

एक और पुरानी समस्या का समाधान

श्रीप्रकाश शर्मा

ब्रू जनजाति को राहत देकर केंद्र ने यही दर्शाया कि वह पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है

करीब 23 वर्षों से निर्वासित जीवन गुजार रहे मिजोरम के 35000 ब्रू जनजाति के परिवारों की समस्या का समाधान हाल में तब हुआ जब केंद्र सरकार की पहल पर त्रिपुरा और मिजोरम के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ब्रू लोगों को स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाया जाएगा। ब्रू त्रिपुरा की 21 जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है। इसे रियांग भी कहा जाता है। इसका मूल निवास स्थान म्यांमार और बांग्लादेश का चटगांव माना जाता है। ब्रू जनजाति असम को छूते हुए मिजोरम के दो जिलों मामित और कोलासिब में भी निवास करती है। यह जनजाति मिजोरम के एक अन्य जिले लूंगलई में भी प्रवास करती है। मिजोरम में ब्रू जनजाति के लोगों की जनसंख्या 40,000 है। वहीं त्रिपुरा में इनकी आबादी 1.30 लाख है। त्रिपुरा और असम में रहने वाले अधिकांश ब्रू हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। 88 प्रतिशत ईसाई आबादी वाले मिजोरम में इनका रहना मुश्किल हो रहा था। ब्रू और मिजो समुदाय के बीच संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब 1990 में ब्रू लोगों को निर्वाचक सूची से हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी। मिजो समुदाय का मानना था कि ब्रू लोग मिजोरम के स्थायी निवासी नहीं हैं। इस प्रकार की मांग की प्रतिक्रिया में ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट और एक राजनीतिक इकाई ब्रू नेशनल यूनियन का निर्माण हुआ। इन दोनों संगठनों ने संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत मिजोरम के ब्रू लोगों के लिए अधिक स्वायत्तता और ब्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग रखी। मामित के ब्रू बहुल क्षेत्र में 21 अक्टूबर, 1996 को एक मिजो ऑफिसर की हत्या की पृष्ठभूमि में हिंसक घटनाओं की जो शुरुआत हुई, उसकी लौ तेजी से फैलती गई। इसके फलस्वरूप मिजोरम से ब्रू लोगों के त्रिपुरा की ओर पलायन की शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं है कि त्रिपुरा के अस्थायी शरणार्थी में दो दशकों से भी अधिक अवधि से रहने वाले ब्रू लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूर्व में प्रयास नहीं किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। हाल के बहुप्रतीक्षित समझौते का सफर भी आसान नहीं रहा।

इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो ब्रू लोगों की घर वापसी के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश 2010 से ही की जा रही थी। इस दिशा में पहला प्रयास नवंबर 2010 में किया गया, जिसके फलस्वरूप 1622 ब्रू परिवारों के 8573 सदस्य पहली बार मिजोरम वापस आए। 2011,

2012 और 2015 में भी इस दिशा में प्रयास किए गए, किंतु बड़ी सफलता हाथ नहीं लग पाई। अंतिम चरण के रूप में 30 नवंबर, 2018 तक इन ब्रू शरणार्थियों को मिजोरम लौट जाना था। सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 328 परिवारों से अधिक अपने घर वापस नहीं हो पाए। इसकी एक बड़ी वजह यही थी कि मिजो लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। माना जाना चाहिए कि हाल के समझौते से इस विवादस्पद मुद्दे का अंतिम रूप से समाधान हो जाएगा। इस समझौते के अनुसार केंद्र सरकार ने राहत कार्यक्रमों के लिए 600 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। त्रिपुरा ने इन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए 35 एकड़ भूमि देने का भी एलान किया है। त्रिपुरा में इन परिवारों को जनजातीय दर्जा के अतिरिक्त उन्हें मताधिकार भी प्राप्त होगा। त्रिपुरा में विकास और जनकल्याण के लिए चलाए जा रही विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं में भी उन्हें समान रूप से अवसर मिलेगा। सरकार द्वारा इन ब्रू परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समुदाय के सदस्यों को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में चार लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को त्रिपुरा सरकार द्वारा 1200 वर्गफीट भूमि भी दी जाएगी और आने वाले दो वर्षों तक 5000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुफ्त राशन के साथ घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि वर्षों से विकास की रोशनी से दूर रहे इन विस्थापित परिवारों के लिए एक नया जीवन शुरू करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस समझौते का महत्व इसलिए है, क्योंकि इसके पहले तक आम तौर पर शेष देश को यह पता ही नहीं था कि ब्रू लोग कौन हैं और उनकी समस्या क्या है? यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने ब्रू लोगों को राहत देने की ठोस पहल की। इससे यह दावा सही साबित होता है कि वह पूर्वोत्तर के साथ देश की पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम इस सत्य से कदाचित ही इन्कार कर पाएं कि विस्थापित के रूप में किसी नए राज्य में घर बसाने और एक नया जीवन शुरू करना आसान नहीं होता है। भावनात्मक रूप से अपनी ही जमीन और पूर्वजों की विरासत से कटकर किसी समुदाय के सामने केवल खुद की पहचान का प्रश्न ही सिर नहीं उठाता, बल्कि रोजगार, शिक्षा और फिर नए सिरे से खुद के वजूद को एक मजबूत आधार प्रदान करने का मुद्दा भी आत्मपरीक्षण के कई प्रश्न छोड़ जाता है। नए समझौते के तहत ब्रू परिवारों का त्रिपुरा में जो पुनर्वास होने जा रहा है उससे मिजोरम की सरकार के साथ-साथ वहां की अवाम ने भी राहत की सांस ली है।

आज जबकि ब्रू परिवारों के लिए त्रासदी और अनिश्चितता के दिन समाप्त हो चुके हैं और समग्र विकास की एक नई रोशनी उनके जीवन में दस्तक दे रही है तो इस बात की ताकीद करना अनिवार्य हो जाता है कि सरकार द्वारा किए गए वायदे बिना किसी विलंब के अब तक दुख और लाचारी का जीवन गुजार रहे हजारों ब्रू परिवारों को उपलब्ध हो पाएं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दिशा में मिजोरम से पलायन के भुक्तभोगी इन परिवारों को भी अपनी सोच और दर्शन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की सख्त दरकार है, ताकि लंबे अर्से से मिजोरम और त्रिपुरा के विभिन्न समुदायों के मध्य शांति और सौहार्द का माहौल स्थापित हो सके।

(लेखक मिजोरम के एक विद्यालय में प्राचार्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सद्-संकल्प

जिस प्रकार अभिमान करना पाप है, उसी प्रकार स्वयं को दीन-हीन समझना भी पाप है। कतिपय अभिभावक बच्चों के लिए अपमानजनक और हीनतासूचक भाषा का उपयोग करते हैं, यह उचित नहीं है। इससे उनके मस्तिष्क में हीनता के संस्कार अंकित हो जाते हैं। जिनका उनके भविष्य पर घातक प्रभाव होता है। बच्चों के लिए मार्गदर्शन जरूरी है, पर उसके साथ हीनता की भावना को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रारंभ में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में मंदबुद्धि समझे जाते थे। वे शिक्षकों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते थे। उनके सहपाठी उनकी पीठ पर 'मूर्ख', 'बुद्धू' जैसे उपहासास्पद शब्द लिख देते थे, पर आइंस्टीन हीन भावना के शिकार नहीं हुए। शताब्दी के महान वैज्ञानिक के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हुए।

व्यक्ति और परिस्थिति का गहरा संबंध है। जिसे अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं वह सहजता से विकास कर सकता है। प्रतिकूल परिवेश में सफलता की ओर बढ़ना कठिन होता है। परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। आज के जनमानस पर परिस्थितिवाद का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। इससे मानसिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हर व्यक्ति का जीवन परिवर्तनशील है। समय-समय पर कठिनाइयों की दुर्गम घाटियां भी पार करनी होती हैं। जिनका मानस परिस्थितिवादी हो जाता है, वे उस स्थिति में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। विश्व के सभी महापुरुष अपने मनोबल के आधार पर सफलता के शिखर पर आरूढ़ हुए हैं। हमारे आत्मबल और पुरुषार्थ में ही सफलता का निवास होता है, बाहर के साधनों में नहीं।

जीवन के हर क्षण से पूरा रस निचोड़ लेना, हर क्षण को पूरी जिजीविषा से जी लेना, हर क्षण में अपने प्राण उड़ेल देना-यही है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यही है जीवन का सद्-संकल्प। यही है समस्याओं से मुक्ति का मार्ग।

ललित गर्ग

गुणवत्ता का सवाल

कपिल अग्रवाल

आज देश भर में योग एवं जिम केंद्रों की बाढ़ सी आई हुई है, पर मुख्य समस्या उनकी गुणवत्ता को लेकर है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश भर के सभी खेल स्टेडियमों एवं सरकारी जमीनों में सार्वजनिक जिम एवं योग केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिसमें आम जनता प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की मदद से बगैर शुल्क अपनी सेहत दुरुस्त कर सकेगी। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए नियम कानून बनाने एवं नियामक के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दरअसल देश भर में योग एवं जिम केंद्रों की बाढ़ सी आई हुई है, पर मुख्य समस्या उनकी गुणवत्ता को लेकर है, क्योंकि इनके अधिकांश संचालक-प्रशिक्षक स्वयं अप्रशिक्षित हैं। इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। कोई कानूनी बंदिश न होने के चलते देश के कोने-कोने में ऐसे अनाधिकृत संस्थानों की बाढ़ आ रही है जो सही ढंग से सिखाने एवं व्यायाम कराने के बजाय उपभोक्ताओं की जेब पर ज्यादा नजर रखते हैं। खासकर जिम में मशीनी व्यायाम के साथ-साथ अनाप-शनाप दामों पर शक्ति वर्धक दवाएं, सप्लीमेंट, जानवरों को दिए जाने वाले विशेष उत्प्रेरकयुक्त इंजेक्शन तक बेचे जा रहे हैं। तमाम शहरों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें विभिन्न दवाएं एवं खतरनाक इंजेक्शन लेकर जिंदगी चैपट कर ली गई। योग केंद्रों का हाल तो इससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अधिकांश प्रशिक्षकों को योग की बुनियादी जानकारी भी नहीं होती और वे कुछ सामान्य आसन बताकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर लेते हैं।

इन संस्थानों में जाकर रोजाना घंटे दो घंटे कसरत करना गलत नहीं है, पर इसके लिए प्रशिक्षित कोच का दिशा निर्देशन खास तौर से जरूरी है। बगैर किसी मानक व खराब गुणवत्ता वाले सस्ते उपकरणों के गलत ढंग से इस्तेमाल करने की वजह से मांसपेशियों व नसों में खिंचाव, रीढ़ की हड्डी अथवा कमर में तकलीफ, जोड़ों में दर्द जैसे मामलों की तादाद इसीलिए दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार बॉडी बिल्डिंग के नाम पर बतौर उत्प्रेरकों के रूप में ली जाने वाली खतरनाक रासायनिक दवाएं व इंजेक्शन आदि न केवल नुकसानप्रद हैं, बल्कि जानलेवा भी हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में कोई खास व प्रभावी नियम कानून न होने के चलते सब कुछ बेलगाम रहा है।

जिस प्रकार योग एवं जिम की शुरुआत करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी होती हैं उसी प्रकार इन्हें त्यागते वक्त भी सावधानियों का पालन करना होता है। और यह सब प्रशिक्षक एवं चिकित्सक ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। अच्छा है कि विकसित देशों की तरह अब भारत सरकार ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इस व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए न केवल मानक निर्धारित किए जा रहे हैं, बल्कि एक नियामकीय संस्था बनाकर रजिस्ट्रेशन, मान्यता एवं रेटिंग लेना अनिवार्य किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को इनकी प्रामाणिकता, गुणवत्ता एवं सुविधाओं के साथ-साथ संचालकों एवं प्रशिक्षकों की योग्यता के बारे में भी जानकारी मिलेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

चेहरा बदलना काफी नहीं

अमित शाह की बड़ी लकीर शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने उम्मीद जताई है कि भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के विजय रथ की गति को बरकरार रखेंगे। जिस तरह घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी सूझबूझ से अपने घर के सभी सदस्यों को एकता की डोर में बांधकर रखेगा, उसी तरह हर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह न होने दे। खैर नड्डा भाजपा को क्या नयापन दे पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल मात्र अध्यक्ष का चेहरा बदलने से ही भाजपा अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाएगी। इसके लिए उसे अपने सभी कार्यकर्ताओं की सोच बदलनी होगी। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों की जनसमस्याओं की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि देश का मतदाता चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के चेहरे को देखकर नहीं करता, बल्कि अपने स्थानीय नेताओं की नीयत को देखकर करता है। जेपी नड्डा से गुजारिश है कि वह अपनी पार्टी के सरकारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दें कि वे सभी अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर जोर दें।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

दहेज प्रथा से तड़पती बेटियां

दहेज क्या है? यह उस पिता से पूछना, जिसकी जमीन भी चली गई और उसकी बेटी भी। सदियों से चली आ रही दहेज जैसी कुप्रथा अक्सर बेटियों के लिए काल बन जाती है। आए दिन दहेज उत्पीड़न की खबरें अखबारों में छपती हैं, लेकिन हमारे समाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते हैं बेटी से बड़ा कोई धन नहीं, परंतु कहने भर से परिवर्तन नहीं होने वाला, इस बात पर अमल करने के बाद ही समाज में परिवर्तन संभव है। बेटी पक्ष से बड़े दहेज की मांग करने पर लोग एक भी बार नहीं सोचते कि बेटी पक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा। संसार के सभी पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा वर और घर चाहते हैं, जिससे बेटी को कोई दिक्कत न हो। इसलिए लड़के पक्ष के द्वारा मांगे गए दहेज को देने के लिए राजी हो जाते हैं। भले ही वो उतना दहेज देने की स्थिति में न हों। बेटियों की शादी में पूर्ण दहेज न दे पाने पर ससुराल वाले बेटी को परेशान करते हैं। दहेज प्रथा के बुरे परिणाम के बारे में सोच कर हर किसी की रूह कांप उठती है। क्योंकि इतिहास ने दहेज प्रथा से तड़पती बेटियों की एक बड़ी लिस्ट बना रखी है। आखिर हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जो जुल्म दूसरों की बेटियों पर कर रहे हैं। आखिर हमारे घर में भी तो बेटी है। एक दिन वो भी जाएगी किसी दूसरे के घर तब उसके साथ भी अगर ऐसा ही सलूक हुआ तो हमें कैसा लगेगा? इसलिए किसी की बेटी और अपनी बहू को प्रताड़ित करना बंद करें तभी आपकी भी बेटी कहीं खुश रह पाएगी। दहेज पर कानूनी रोक के बावजूद समाज में इसे प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। इस बुराई से निजात के लिए जरूरी है कि बड़े लोग दहेज रहित शादियां शुरू करें। तभी समाज में एक संदेश जा सकेगा और लोग बिना दहेज शादियां कर गौरवान्वित महसूस करेंगे।

प्रशांत यादव, दिल्ली

बेटी बचाओ अभियान

राष्ट्रीय बालिका दिवस (24 जनवरी) पर देश के कई जिलों में बाल लिंगानुपात में वृद्धि के लिए बेटी बचाओ अभियान को श्रेय देना चाहिए। यह अत्यंत दुखद बात है कि समाज लड़कों की तुलना में कम लड़कियों का जन्म चाहता है। इन्हें माता-पिता और समाज द्वारा लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता। दहेज एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा है जिसकी वजह से घर में लड़की के जन्मोपरांत उसके परिवार को सबसे बड़ी चिंता उसका विवाह करना लगता है। दहेज की उत्पत्ति शतकों पुराने स्त्रीधन की संकल्पना से हुई है जो उस समय मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाली नवविवाहिता को संबल प्रदान करने के लिए दिया जाता था। यह सच है कि आज के बदलते समय में जहां एक ओर पुरुष-प्रधान मानसिकता ऐसी बुराई को जीवित रखे हुए है, वहीं दूसरी ओर कानून समाज में रचे-बसे इस अपराध को रोकने के लिए सख्त नहीं हैं। हम ऐसी अपमानजनक प्रथा को नकारें और देश को बालिकाओं के विकास के लिए बेहतर स्थान बनाएं

डिंपी भाटिया, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHI

3.6 प्रतिशत योगदान है देश की जीडीपी में पर्यटन सेक्टर का। वर्ष 2014 के बाद भारत की पर्यटन में वैश्विक स्तर की रैंकिंग 52 से 34 पर आ गई है जिसे और बेहतर बनाया जा सकता है।

आजकल

आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम पर्यटन

ऋषि राज
स्वतंत्र टिप्पणीकार

पर्यटन और अर्थव्यवस्था का चोली दामन का साथ है। कई देशों की तो रोजी-रोटी ही इससे चल रही है। भारत में भी पर्यटन को पूरे समर्पण भाव से पोषित करने की जरूरत है। पर्यटन हमें पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसे गति देने के लिए पर्यटन मंत्रालय में ऐसे अधिकारी चाहिए जो देश के सभी पर्यटन स्थलों पर घूम चुके हों और वहां की जमीनी हकीकत से भली-भांति परिचित हों। रेलवे और पर्यटन विभाग अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा

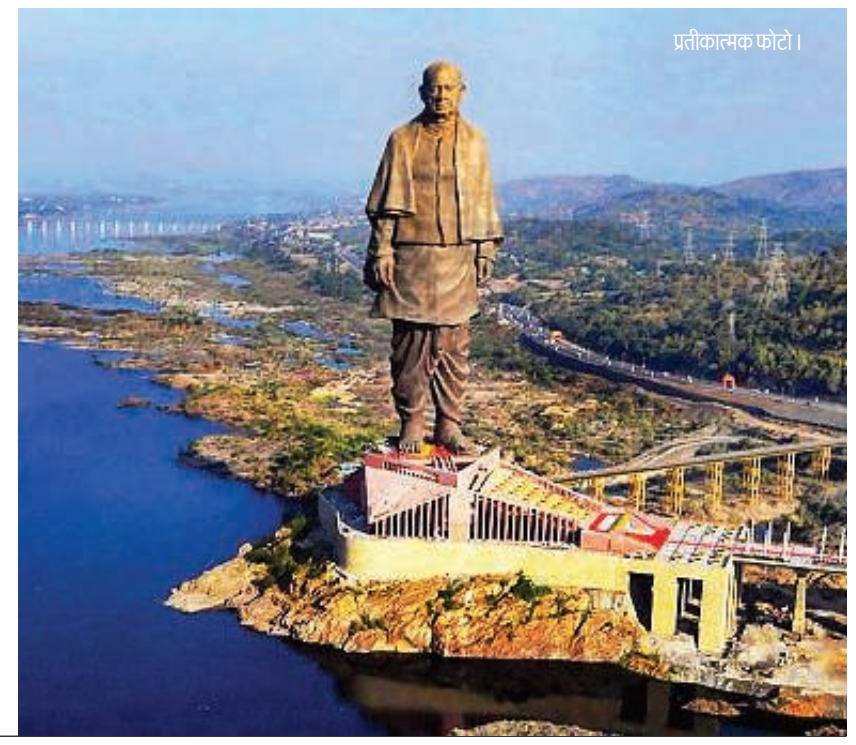
प्रतीकात्मक फोटो।

पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आह्वान किया था कि वे देश के पर्यटन स्थलों पर घूम कर आएं। उसके बाद 'मन की बात' कार्यक्रम के माध्यम से भी उन्होंने पुनः देशवासियों से कम से कम 15 पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित किया है। उनका मकसद एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ना केवल पर्यटन स्थलों का विकास चाहते हैं, बल्कि पर्यटन के माध्यम से होने वाली आमदनी को भी कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि मौजूदा अर्थव्यवस्था को 'फाइव ट्रिलियन डॉलर' यानी पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने में पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हां, यह अवश्य है कि इसके लिए हमें इस क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशना होगा, अपनी रणनीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे और सबसे अधिक जरूरी है, मौजूदा आधारिक ढांचे का रखरखाव सही तरीके से हो, ताकि पर्यटक वहां आसानी से और बड़ी संख्या में आ सकें।

अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों पर देना होगा ध्यान : 'फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी' के स्वप्न को साकार करने के लिए पर्यटन को केंद्र में रख कर नीतियों में बुनियादी और क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे, लीक से हटकर काम करना होगा, 'आउट ऑफ बॉक्स' सोच को अपना कर ही हम अपने देश को पर्यटन प्रधान बना सकते हैं। भारत में इसकी क्षमता भी है। हमारे देश की गिनती भी फ्रांस, स्पेन, अमेरिका और चीन सरीखे देशों में हो सकती है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं।

यह बात काफी सकारात्मक है कि वर्ष 2014 के बाद हमारे देश की पर्यटन में वैश्विक स्तर की रैंकिंग 52 से 34 पर आ गई है। आज पर्यटन सेक्टर की देश की जीडीपी में 3.6 प्रतिशत की भागीदारी है, परंतु यदि हम संभावनाओं की बात करें, तो यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां मात्र छोटे-छोटे बदलाव करके ही हम करोड़ों-अरबों रुपये कमा सकते हैं। ऐसा करने से ना केवल कमाई बढ़ेगी, बल्कि रोजगार में भी असीम वृद्धि होगी जो आज हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती या फिर कहें कि समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है।

आसान बने लक्षद्वीप की यात्रा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के पिछले 27 अक्टूबर के कार्यक्रम में लक्षद्वीप का भी जिक्र किया था। अब जब उन्होंने देशवासियों से वहां जाने का आह्वान किया है, तो जाहिर तौर पर अभी तक लाखों लोगों ने वहां जाने का मन भी बना लिया होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि वहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि लक्षद्वीप का भी अंडमान निकोबार की तरह विकास किया जा सकता है। पर्यटन विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है यहां की हवाई पट्टी, जो इतनी छोटी है कि यहां केवल छोटा हवाई जहाज ही उतारा जा सकता है। इसको बड़ा करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के पास मामला वर्षों से विचाराधीन है। अगर यहां हवाई पट्टी वाली समस्या का समाधान कर दिया जाए तो यह भी अंडमान निकोबार की तरह एक पूर्ण विकसित पर्यटन स्थल बन जाएगा। आशा है, सरकार जल्द इस पर कार्रवाई करेगी।

मुंबई से शिरडी यात्रा : मुंबई से शिरडी के लिए रोजाना बड़ी संख्या में बसें चलती हैं। अगर मुंबई से शिरडी के लिए दिन में प्रत्येक चार घंटे में एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की तरह ट्रेन चला दी जाए जिसमें दर्शनों के 'पेड पास' की व्यवस्था भी साथ ही हो तो अनेक कामगार श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुंबई से पंढरपुर के लिए भी कोई अच्छी ओवर नाइट ट्रेन उपलब्ध करवाई जा सकती है। महाराष्ट्र में पंढरपुर महाराज को मानने वाले भक्तों की संख्या करोड़ों में है। इस संपूर्ण विषय पर रेल विभाग एक अध्यन करे और पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए रूप-रेखा तैयार कर गाड़ियों का संचालन करे।

दिल्ली से वैष्णो देवी यात्रा : दिल्ली से श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए हाल ही में रेलवे ने 'वंदे भारत' ट्रेन सेवा शुरू की है जो एक अच्छा कदम है। लेकिन रेलवे को यह समझना होगा कि सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास हमेशा अपने दिन का समय बचाना चाहता है। इसके लिए प्रीमियम ओवर नाइट 'हमसफर एक्सप्रेस' जैसी ट्रेन शुरू की जा सकती है। यदि इस रूट पर हमसफर एक्सप्रेस शुरू की जाए तो मौजूदा संचालित ओवर नाइट ट्रेन श्रीशक्ति एक्सप्रेस से बढ़िया सुविधा दे सकती है और इस प्रकार लोग प्रीमियम ट्रेन का अधिक किराया देने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। इस गाड़ी के माध्यम से 'एक दिन में वैष्णो माता की यात्रा' कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी सुविधा शुरू करने से ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सकता है जो पर्यटन में मील का पत्थर साबित होगा। कम से कम नई दिल्ली से जम्मूतवी तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को ही यदि तत्काल प्रभाव से जम्मूतवी से श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा तक बढ़ा दिया जाए तो श्रीमाता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले पर्यटकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। रेलवे के लिए ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कटड़ा तक इसे विस्तार देने के बावजूद इस ट्रेन के रखरखाव के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कहने का तात्पर्य कि इसे बिना किसी समस्या के कटड़ा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कई अन्य गाड़ियां हैं जिन्हें मौजूदा गंतव्य से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

शहीद स्मारकों का भ्रमण हो आसान : इसी प्रकार से आज की युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद के बीजारोपण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें शहीदों से जुड़े स्थलों पर ले जाया जाए और रेल मंत्रालय ऐसे स्थानों के लिए विशेष तौर पर रेलगाड़ियों का परिचालन करे। दिल्ली से फिरोजपुर (हुसैनीवाला) के लिए ओवर नाइट ट्रेन हो जिसका नाम 'शहीद ए आजम एक्सप्रेस' रखा जाए। फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर बस उपलब्ध हो जो बच्चों को हुसैनीवाला ले जाए और शाम को वापस फिरोजपुर ले आए और अगली सुबह वे लोग दिल्ली पहुंच जाएं।

बढ़ाई जाए रेलवे की सहभागिता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी चार वर्षों में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे की सहभागिता बढ़ानी होगी। रेलवे की सहभागिता को बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि पर्यटन स्थलों और उससे जुड़ी जरूरतों के मुताबिक योजनाओं का खाका तैयार करते हुए उसे पूरा करना होगा। अगर हम देश के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर जाने वाली रेलगाड़ियों का परिचालन 'टेलर मेड' यानी पर्यटकों की जरूरत के हिसाब से कर दें तो पर्यटन को बढ़ाने में रेलवे का एक महत्वपूर्ण योगदान सामने आ सकता है। किसी भी स्थान पर जाने के लिए अधिकांश लोगों की पहली पसंद 'ओवर नाइट ट्रेन' होती है यानी ऐसी ट्रेन जो रात भर में गंतव्य तक पहुंचा दे ताकि रात में सोते-सोते सुबह तक वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। इसीलिए ऐसी गाड़ियों की मांग सदैव बनी रहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश में सैकड़ों ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनका महज अच्छी रेल कनेक्टिविटी के अभाव में अभी तक हम संपूर्ण दोहन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में हमें अभी तक जारी इस तरह की व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव करना होगा। इस मामले में कैसे हम बेहतरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं इसे हम अनेक उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं।

आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए कोई अच्छी 'ओवर नाइट ट्रेन' नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छी सुविधा मिले। इसके लिए रेलवे 'हमसफर एक्सप्रेस' टाइप की प्रीमियम ट्रेन चला कर कमाई कर सकता है और यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को एक बेहतरीन सेवा भी प्रदान कर सकता है। अमृतसर ना केवल देसी, बल्कि लाखों विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ऐसे में अच्छी सुविधा की एवज में पर्यटकों की जेब से पैसे निकलवाना मुश्किल काम नहीं होगा। हम सिख समुदाय के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब और पटना साहिब के लिए विशेष ओवर नाइट गाड़ियां चला कर 'खालसा सर्किट' बना सकते हैं।

गुजरात के नर्मदा जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई प्रतिमा लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहां देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। अभी यहां तक ट्रेन से आने वाले यात्रियों को वडोदरा स्टेशन पर उतरना होता है और वहां से लगभग सौ किलोमीटर की यात्रा उन्हें सड़क मार्ग के जरिये संपन्न करनी होती है। हालांकि इस संदर्भ में संतोष की बात यह है कि रेल मंत्रालय ने इस पर पहल करते हुए इस पर्यटक स्थल से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित केवडिया कस्बे तक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है और इसे तेजी से पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता भी जताई है। यह आवश्यक है कि आज की युवा पीढ़ी सरदार पटेल पर अध्यन करे, उनसे प्रेरणा ले और इसके लिए नितांत आवश्यक है कि यहां ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाया जाए। इसलिए कॉलेज एवं स्कूलों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से वडोदरा तक के लिए ओवर नाइट ट्रेन का परिचालन होना चाहिए, जिसका नाम 'सरदार एक्सप्रेस' रखा जाना चाहिए। इसके अलावा वडोदरा स्टेशन पर बस उपलब्ध हो जो बच्चों को प्रतिमा स्थल 'केवडिया' तक ले जाए, वडोदरा के कुछ पर्यटक स्थलों को घुमा-फिरा कर देर रात उसी गाड़ी से अगली सुबह वापस दिल्ली पहुंचा दे। इस कार्य से एक तीर से कई निशाने लगाए जा सकते हैं। जहां एक ओर बच्चों को सरदार के जीवन को करीब से जानने का अवसर मिलेगा, वहीं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा देखने के लिए ज्यादा पर्यटक मिलेंगे और रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी।

देश में ऐसे अनेक पर्यटन स्थल हैं जहां तक के लिए रेल संपर्क को बेहतर बनाते हुए पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जा सकती है।

खरी-खरी

पुस्तक मेले का कल्पना-लोक

संतोष उत्सुक

हर वर्ष की तरह इस बार भी लेखकों, किताबों और प्रकाशकों का मेला पिछले दिनों संपन्न हो गया। हालांकि मैं कभी पुस्तक मेले में नहीं जा पाया। कई वरिष्ठ लेखकों ने कई बार मुझसे कहा भी, लेकिन दिल्ली हमेशा दूर रही। वैसे वहां के मंजर बड़े ही रोचक, आकर्षक होते हैं। कई सालों से देख रहा हूं, किसी की भी पहली पुस्तक ही वहां मशहूर हाथों से रिलीज हो रही है। अनुभवी लेखक की छब्बीसवीं पुस्तक तो वहीं होनी ही है। कहीं हमने पढ़ा था, विचारोत्तेजक, प्रखर लेखन से समाज में परिवर्तन आता है। इससे तो लगता है कि दर्जनों के हिसाब से पुस्तकें लिखने वालों ने काफी ज्यादा बदलाव ला दिया होगा। ऐसे में क्रांति की चाहत रखने वाले आम व्यक्ति के मन में भी लेखन का कीड़ा घुस जाता होगा।

कई लोग चुटकी ले रहे होंगे कि फलां ने अमुक यशस्वी लेखक के साथ या प्रसिद्ध प्रकाशक के स्टॉल पर फोटो खिंचवाकर अपना लेखक होना जताया। लेकिन वहां कोई लेखक होने, बनने या दिखने के लिए ही तो नहीं जाता। किताबी मेले में दूसरों के लड्डू खाने के बहाने फेसबुकिया मित्र लेखक भी मिलते होंगे। उन्हें ताजा सुंदर किताबों, स्थापित चेहरों और पेशेवर लेखकों के साथ फोटो व सेल्फी खिंचवाकर हाथ में कलम होना या टाइप करना महसूस होता होगा।

कुछ लेखक वहां पहुंचकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक विमोचक या मुख्यमंत्री या राज्यपाल के हाथों से पुस्तक का विमोचित पैकट खुलवाने की तुलना करते होंगे। वैसे मुख्यमंत्री या राज्यपाल के हाथों विमोचित होने से किताब भी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि लेखक या विमोचक उपलब्ध होना आसान है। एक और बात! पुस्तक लिखना, छपवाना और विमोचन करवाना आसान है, लेकिन पाठक, मित्रों या सरकार को बेचना मुश्किल है। मेले में फेसबुक और अपनी बुक के लिए काफी सामान मिल जाता है। मुझे लगता है, वहां सभी एक-दूसरे से असली प्यार से, असली गले मिलकर, असली खुश होते हैं। छोटे शहर की साहित्यिक दुनिया की तरह लेखक वहां बड़े खेमों में बंटे नहीं होते। उनमें ईर्ष्या, एक-दूसरे को खारिज करने जैसी (कु)भावनाएं नहीं होंगी। किताबें तो जड़ होती हैं, मुझे विश्वास है, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं पनपता होगा।

ट्वीट-ट्वीट

स्पीकर को मिले सांसद-विधायक की सदस्यता छीनने के अधिकार की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का संसद को कहना सही है। लाखों लोगों के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया जटिल है। चुटकी बजाते सदस्यता नहीं छीनी जा सकती। वह भी तब जब स्पीकर पार्टी लाइन पर चलते हों।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

नीतीश कुमार सीएए पर पार्टी विरोधी रुख वाले नेताओं को आईना दिखा रहे हैं। उनके कथन ने दिनकर की याद दिला दी कि 'क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो।' सर, आपका तो इतिहास ही लोगों को माफ करने का रहा है चाहे मांझी हों या कुशवाहा।
डॉ. अजय आलोक@alok_ajay

अपने देश में 5जी तकनीक के लिए वियतनाम हुआवे, एरिक्सन, जेडटीई, सैमसंग और नोकिया जैसी कंपनियों के बजाय देसी कंपनी विट्टेल की तकनीक पर दांव लगाएगा। कंपनी ने भी एलान किया है वह छह महीनों में 5जी सेवाएं शुरू कर देगी।
ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

आइएमएफ का 4.8 फीसद वृद्धि का अनुमान है। महंगाई बढ़ रही है। यह खतरनाक रुझान है। यह वक्त तरलता, विनिर्माण और रोजगार-अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने पर ध्यान देने का है।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के अधिकार की समीक्षा की जानी चाहिए?

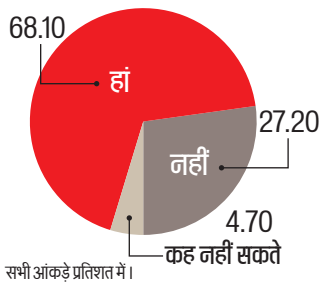

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या मुंबई की तर्ज पर अन्य बड़े शहरों में भी 24 घंटे मॉल-दुकानें खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'शासक' भारतवर्ष के रहे अकबरुद्दीन,
बता रहे हैं आज वह बजा-बजाकर बीन।
बजा-बजाकर बीन चीखकर वे धमकाएं,
फिर भी चाहें आप कि हम उनको अपनाएं!
हमने बांटा प्रेम आप थे सत्यानाशक,
ले करके तलवार बने भारत के 'शासक'।
- ओमप्रकाश तिवारी

हिमाचल प्रदेश डायरी

भाजपा के जगत का प्रकाश, बिंदल से आस

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

बेशक भूमिका पहले से बन रही थी, लेकिन वे 2011 के कुछ निर्णायक पल थे जब जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल को छोड़ते हुए संगठन को चुना था, संगठन के राष्ट्रीय फलक को चुना था। उसके बाद परिस्थितियों को अपने श्रम से अनुकूल बनाते हुए संगठन की आंच में और निखरे। बेशक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से नियमित अध्यक्ष बनना तय ही था, निस्संदेह हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए यह बड़ी बात है। इस एक सर्वसम्मत नियुक्ति के कई संदेश हैं। राज्य छोटा हो, उससे अंतर नहीं पड़ता, काम बड़ा होना चाहिए। इस नाते यह प्रतिभा का सम्मान है, प्रदेश का सम्मान है। भाजपा के जगत में नड्डा का प्रकाश होने के पीछे मूलतः उनका श्रम है। बेशक वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी विश्वस्त हैं। और विश्वास कमाना सबसे कठिन काम होता है। उसे प्रमाणित करना पड़ता है, उसे होना ही नहीं, दिखना भी पड़ता है। उसके बाद से नड्डा ने पीछे लौट कर इसलिए नहीं देखा, क्योंकि एक चुनौती के बाद दूसरी, एक राज्य के बाद दूसरा और एक कठिन कार्य के बाद दूसरा कठिन कार्य संभालते गए और इस मुकाम पर पहुंचे।

पटना से लेकर शिमला और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में संगठन क्षमता प्रमाणित कर चुके नड्डा के दिल्ली तक पहुंचने के बीच कई उपलब्धियां दर्ज हैं। जेपी आंदोलन ने उनकी राजनीतिक और नेतृत्व चेतना को सींचा जिसके बाद वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहे। उसके बाद जब शांता कुमार 1993 में हार गए थे, जेपी नड्डा विधानसभा में पार्टी के नेता थे। तब भारतीय जनता पार्टी के आठ ही विधायक थे। पिता नारायण लाल नड्डा यूं ही नहीं कहते कि नड्डा में नेतृत्व के गुण बचपन से ही थे। बिलासपुर का कंदरौर आंदोलन भी उन्हें सामने लाया था। उनके दादा शिव राम नड्डा उन्हें नेताजी कह कर ही बुलाते थे। वजह यह थी कि जब-जब नड्डा घर आते, हमउम्र बच्चों को इकट्ठा कर लेते। बाकी सब भी उनकी बात मानते थे। उनके संगठक की झलक के लिए यह पर्याप्त है। इससे पूर्व भी हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय फलक पर लोग ढाए रहे हैं, लेकिन पहाड़ का इतना बड़ा सम्मान पहली बार हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के चयन में भी जगत प्रकाश नड्डा की छाप दिखी है। दो ऐसे नाम चल रहे थे जिनका ताल्लुक बिलासपुर से था, लेकिन वे नाम वापस हुए और प्रश्न पूछा गया कि ऐसे नेता का नाम बताएं जो अपने दम पर भाजपा को चुनाव तक ले जा सके। इसलिए, क्योंकि आखिर लक्ष्य, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, निष्ठावाद नहीं, संगठन होना चाहिए। फिर डॉ. राजीव बिंदल का नाम उभरा और तय हो गया। डॉ. राजीव बिंदल के बारे में उनके विरोधी भी मानते हैं कि वह काम करने वाले राजनेता हैं। पहले सोलन और सिरमौर में भाजपा को मजबूत करने में उनका योगदान सर्वविदित है। कभी राजनीतिक मौसम ऐसा हो जाता है कि वात, पित्त और कफ हर पार्टी में असंतुलित हो जाते हैं। आयुर्वेदज्ञ डॉ. बिंदल त्रिदोष का नाश करेंगे, ऐसी ही अपेक्षा से उनका चयन किया गया है। अब संतुलन सधेगा और सरकार और संगठन के बीच तारतम्य और बढ़ेगा, संगठन का चेहरा और दमक के साथ दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद करना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तो पहले ही कह चुके हैं कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अनुराग ठाकुर ने भी 'बड़े भाई' जगत प्रकाश नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई है, उसी प्रकार डॉ. बिंदल का प्रदेशाध्यक्ष बनना भी शिमला से हमीरपुर और मंडी से पालमपुर तक सबको स्वीकार हो गया है। डॉ. बिंदल के यहां अनुभव सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते, उन पर काम हो, इसीलिए होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने नए विधायकों की मजबूरी को समझा और संदर्भ अनुभाग की स्थापना की। विधायक को जिस विषय पर बोलना है, उस से संबद्ध सामग्री उन्हें मिल जाएगी। यह विधानसभा के अकादमिक स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतर कदम था। 'ई कमेटी' और 'ई कांस्टीचुएंसी' तो एक बेहतर सोच थी ही।

यह ज्ञात नहीं कि कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हों या प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, इन दोनों की नियुक्ति के साथ हिंदी भाषा भी सम्मानित हुई है, क्योंकि दोनों शब्द के मर्म को समझते हैं। भाजपा को प्रदेश में आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करने का बड़ा दायित्व डॉ. बिंदल के सामने है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश आदर्श होना ही चाहिए। उम्मीद है कि डॉ. बिंदल हर कोने की बात सुनेंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश देश की 71 लाख की आबादी वाला वह राज्य है जहां बजट के लिए सुझाव मांगने पर केवल 2,393 सुझाव ही आए हैं। इनमें से भी 80 फीसद शिकायतें और मांगें हैं। जहां सुझाव से अधिक शिकायतें हों, वहां संगठन को भी जनता और सरकार के बीच पुल बनना होगा।

भाजपा अध्यक्ष नियुक्त होने पर जेपी नड्डा को बधाई देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो।

बदलाव

दलबदल तय करे स्वतंत्र निकाय

अरविंद कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

देश में दलबदल के मामलों पर अक्सर खींचतान मची रहती है। समय-समय पर इसमें कई खामियां सामने आती रही हैं, जिन्हें दूर करके ही इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है

प्रतीकात्मक फोटो।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुझाव दिया है कि विधायकों को अयोग्य करार देने का अधिकार एक स्वतंत्र निकाय के पास हो। संसद यह तय करे कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास हो या नहीं। यह सुझाव मणिपुर से संबंधित एक याचिका पर दिया गया है जिसमें दलबदल कानून के तहत विधायक टी श्यामकुमार सिंह को मणिपुर विधानसभा से अयोग्य ठहराने की याचना की गई थी। वर्ष 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीते श्यामकुमार बाद में भाजपा में चले गए और मंत्री बने। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर दायर याचिका पर लटकाने वाला रवैया अपनाया। इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने उनको चार सप्ताह में फैसला देने के साथ यह भी कहा कि अगर इस समय सीमा में फैसला नहीं होता तो याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं।

अध्यक्ष सभा के नियमों, शक्तियों और विशेषाधिकारों के संरक्षक हैं। संसदीय परंपराओं का संरक्षण उनका कर्तव्य है। दलबदल कानून यानी संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत उनकी भूमिका न्यायाधीशों जैसी होती है, लेकिन यह भी सच है कि किसी भी फैसले को लेने के पहले उन पर अपने दल और खास तौर पर सत्ता दल का दबाव रहता है। इसी नाते देहरादून में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस पर हुई व्यापक चर्चा के बाद एक समिति गठित की गई है जो व्यापक विचार के साथ संविधान संशोधन के साथ कई अहम सुझाव देगी। हाल में लखनऊ में संपन्न राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत परिक्षेत्र के सम्मेलन में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दलबदल कानून पर पीठासीन अधिकारियों के असीमित अधिकार सीमित होंगे।

मणिपुर के जिस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आई है, उसमें टी श्यामकुमार समेत आठ कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए तो राजनीति गरमा गई। वर्ष 2017 में मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों पर हुए चुनावों में भाजपा को 21 और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थीं। लेकिन दलबदल के बाद राजनीतिक तस्वीर बदल गई और भाजपा ने सरकार बना ली। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी। बाद में कांग्रेस ने राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर भाजपा में शामिल होने वाले इन आठ विधायकों के साथ एक दर्जन संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। उसी दौरान कहा गया था कि सुनवाई न हुई तो कानूनी कार्रवाई का विकल्प खुला है। संसदीय सचिवों को हटाने के बाद वह मुद्दा तो समाप्त हो गया, लेकिन दलबदल का मुद्दा लटका रहा।

दलबदल के मामले से जुड़ा कानून संविधान की दसवीं अनुसूची से जुड़ा है जिसमें अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। आम बोलचाल में इसे दलबदल विरोधी कानून भी कहते हैं। यह विधेयक जनवरी 1985 में संसद से पारित हुआ। इसमें अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया और संविधान की दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें दलबदल करने वाले सांसदों और विधायकों की अर्हता निरस्त करने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद फैसलों में देरी पर सवाल खड़े होते रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पीठासीन अधिकारियों के सामने तमाम चुनौतियां हैं। कई पीठासीन अधिकारियों का मानना है कि उनका दायित्व सदन चलाना है। अगर ब्रिटिश संसद बिना 10वीं अनुसूची के चल रही है तो यह काम भारत में क्यों हो। क्या अध्यक्षों का काम मुख्यमंत्रियों के हितों की रक्षा करना है या सदन की। अध्यक्ष दलीय झगड़ों में भागीदार क्यों बने। दलबदल बेहद घिनौना अपराध है, लेकिन सत्ता और धन की लालच में यह बढ़ता जा रहा है। तमाम पीठासीन अधिकारी मानते हैं कि महज सदस्यता ही नहीं, इसमें पांच साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होने का प्राविधान भी जोड़ा जाना चाहिए।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने 2017 में जदयू सांसद शरद यादव और अली अनवर अंसारी की सदस्यता समाप्त करने का फैसला तीन महीने में सुनाया। इस पर देश भर में काफी चर्चा हुई। सभापति ने अपने फैसले में लिखा कि ऐसे मामलों में देरी से दलबदल विरोधी कानून की मूल भावना आहत होती है। इस नाते विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों को ऐसी याचिकाओं का समयबद्ध और तीन माह के भीतर निपटारा कर देना चाहिए।

लेकिन दलबदल के मामले में अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं के निपटारे में अप्रत्याशित देरी से कई पीठासीन अधिकारियों की बेहद आलोचनाएं हुई हैं। कुछ माह पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दलबदल कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची की समीक्षा की अपील की थी। विधानमंडल के अध्यक्षों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि दलबदल विरोधी कानून सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। सभापति या अध्यक्ष की निष्क्रियता के कारण विधायक न केवल नई पार्टी में बने रहते हैं, बल्कि कुछ मामलों में मंत्री भी बन जाते हैं। न्याय के इस तरह के उपहास को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसद हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की धुरी है और पीठासीन अधिकारी संसदीय तंत्र की धुरी। अध्यक्ष के कार्यालय की अपनी गरिमा और महत्व है। उसके पास बहुत से अहम दायित्व और जिम्मेदारियां हैं। उसके अधीन विधानमंडलों की अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता है। लेकिन दलबदल कानून को लेकर उसके कई फैसलों पर सवाल उठे हैं। विधायिका और न्यायपालिका में तनाव भी पैदा हुआ। यह ताजा मसला भी काफी गंभीर है।

102 लोगों को मौत की सजा सुनाई है ट्रायल कोर्ट ने 2019 में देश में। यह 2018 की तुलना में सुनाई गई सजाओं की तुलना में 60 प्रतिशत कम है। 2018 में 162 लोगों को ट्रायल कोर्ट से मौत की सजा सुनाई गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 24 जनवरी 2020

झारखंड

वित्तीय निगरानी जरूरी

सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा अभियान) के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों को दी गई राशि में लगातार अनियमितता होती रही। उम्मीद की जा रही था कि इस पैसे से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी और उससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, लेकिन व्यवस्थापकों ने अपने भ्रष्ट रवैये से इस पर पानी फेर दिया। वास्तव में जो राशि विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च हुई, उनमें से बड़ी राशि का हिसाब-किताब नहीं दिया गया। वह राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहां तक कि कई जिलों में पदाधिकारियों, कर्मियों, शिक्षकों आदि को रेवड़ी की तरह एडवांस राशि बांटी गई, जिनका समायोजन भी नहीं हुआ। ऐसा पिछले कई वर्षों से होता रहा। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वह यह है कि दैनिक वेतन पर काम कर रहे कर्मियों को भी एडवांस में राशि दी गई। योजना सह वित्त विभाग द्वारा कराई गई ऑडिट में सामने आई इन गड़बड़ियों पर ध्यान आकृष्ट कराए जाने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एक्शन में आया है। अब ऐसे सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से राशि वसूलने के साथ-साथ इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। विभाग से इस आशय का आदेश मिलने के बाद कुछ जिले राशि वसूलने को लेकर रेस भी हुए हैं।

हालांकि यह कदम पहले ही उठाया जाना था। फिर भी, देर से ही उठाया गया यह कदम सराहनीय कहा जा सकता है। इसमें वे कितना सफल हो पाते हैं यह तो समय ही बताएगा।

सर्व शिक्षा अभियान की राशि में लगातार अनियमितता होती रही। कार्यक्रमों में हुए खर्च का हिसाब-किताब नहीं दिया गया है।

ऐसा मामला केवल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में नहीं है। कमोबेश सभी विभागों की यह स्थिति है। महालेखाकार की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। संबंधित विभाग ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों पर संबंधित पदाधिकारियों या कार्यालयों से जवाब मांगकर खानापूर्ति कर देते हैं। पत्राचार का सिलसिला चलता रहता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में ही कई तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक कार्रवाई की जद में आए हैं, लेकिन अंततः उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे कुछ पदाधिकारी अभी विभाग में भी जमे हुए हैं। अन्य विभागों में भी बहुत कम ही ऐसे मामले हैं जिनमें ऐसी रिपोर्ट पर जिम्मेदार पदाधिकारियों या कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हुई हो। सभी विभागों में करोड़ों रुपये की खर्च हुई राशि का समायोजन भी लंबित रहता है। योजना सह वित्त विभाग समय-समय पर इसपर आपत्ति करता है तो विभाग रेस होते हैं। फिर मामला वैसे ही चलता रहता है।

जरूरत ऐसा ठोस तंत्र विकसित करने की है जो सभी विभागों व अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च होनेवाली राशि की वित्तीय निगरानी हो सके। ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों का भी समय पर निपटारा तथा जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। दरअसल ऐसी समस्याओं के मूल में भ्रष्टाचार है। इस पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ों पर प्रहार करना होगा। इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। उम्मीद है नई सरकार इस दिशा में ठोस पहल करेगी।

बंगाल

ईवीएम के बजाय बैलेट पर भरोसा

चंद महीने में राज्य में विभिन्न 110 नगर निकायों के चुनाव होने हैं जिसमें बैलेट के इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। सचिवालय नवान्न सूत्रों के अनुसार इस बाबत राज्य चुनाव आयोग को सरकार की ओर से इत्तला किया जा चुका है। माना जा रहा है कि 10 फरवरी के बाद नगर विकास मंत्रालय की ओर से चुनाव तारीखों की जानकारी साझा की जाएगी। चुनाव दो से तीन चरण में कराया जाएगा। जिन 110 नगर निकायों के लिए चुनाव होना है उसके तहत मतदान केंद्रों की संख्या 18 हजार है। इनमें से अकेले कोलकाता नगर निगम में मतदान केंद्रों की संख्या 4700 है, जबकि हावड़ा नगर निगम में मतदान केंद्रों की संख्या 1200 है।

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में ईवीएम को लेकर काफी हंगामा बरपा हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। भाजपा के चुनाव जीतने को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल खड़े किए थे, परंतु जब कुछ दिन पहले हुए उपचुनाव में ईवीएम के जरिये ही बंगाल की तीनों विधानसभा सीटों पर तृणमूल को जीत मिल गई तो ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। अब एक बार फिर बंगाल में ईवीएम एवं बैलेट को लेकर सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि ममता ने तो पिछले वर्ष अपनी 21 जुलाई की रैली से ईवीएम नहीं बैलेट चाहिए का नारा देकर अभियान छेड़ा था। अब नगर निकाय चुनाव में ममता सरकार बैलेट से ही चुनाव करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा दिया है। 2018 में बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर के माध्यम से ही हुआ था, परंतु मतदान के दिन बैलेट बॉक्स लूट से लेकर मतपत्र फाड़ने और जलाने की घटना आज भी लोगों के मन में ताजी है। बावजूद इसके ममता सरकार बैलेट से ही मतदान कराने के पक्ष में है। बीते साल 21 जुलाई रैली में बनर्जी ने घोषणा की थी कि बंगाल में नगर निकाय और पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से होंगे।

ममता बनर्जी ने तो पिछले वर्ष अपनी 21 जुलाई की रैली से ईवीएम नहीं बैलेट चाहिए का नारा देकर अभियान छेड़ा था।

प्रतीकात्मक फोटो

तकरीबन डेढ़ दशक से नगरपालिका चुनाव ईवीएम से होता रहा है, परंतु अब बैलेट से होगा। वैसे भी बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर काफी कुख्यात रहा है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती है। ऐसे में नगर निगम एवं पालिका चुनाव में क्या होगा इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार के समक्ष ईवीएम से ही मतदान करने की बात कही जा रही है, क्योंकि बैलेट से मतदान कराने में काफी दिक्कत सामने आएगी। अधिक मतदानकर्मियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक की आवश्यकता पड़ेगी, समय और धन अधिक खर्च होगा, लेकिन सरकार अपने रुख पर अडिग है। बात ईवीएम मशीनों की करें तो चुनाव आयोग के पास 21000 ईवीएम हैं। आखिर ईवीएम से मतदान कराने में क्या परेशानी है? यह प्रमाणित हो चुका है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वीवीपैट का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है और उसका मिलान भी हो रहा है। ऐसे में निष्पक्ष मतदान के लिए ईवीएम से बेहतर विकल्प कुछ नहीं है।

बिहार

किसान हित में करार

किसानों के हित के लिए चिंतित राज्य सरकार ने अमेरिकी संस्था पर्यावरण रक्षा कोष के साथ समझौता कर एक अच्छी पहल की है। दरअसल सरकार की चाहत है कि किसान जलवायु के अनुकूल खेती करें ताकि उन्नत फसल से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इस करार से किसानों को प्रत्येक स्तर पर जलवायु के अनुकूल फसलों एवं बीज के चयन, सिंचाई, फसल सुरक्षा और कटाई के बाद के प्रबंधन के संदर्भ में प्रशिक्षण मिल सकेगा। समय-समय पर प्रकृति की मार और आर्थिक वजह से लोग खेती से दूर होते जा रहे हैं। किसानों के हित में तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद उन्हें उसका यथोचित लाभ नहीं मिल पाता है। उम्मीद है कि इस समझौते से किसानों की परेशानी काफी हद तक दूर होगी। सरकार जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों के प्रति लगातार आगाह करती रही है।

जाहिर है किसानों की स्थिति से चिंतित राज्य सरकार इसी वजह से जल-जीवन, हरियाली अभियान पर मिशन मोड में काम कर रही है और इसके लिए 24,524 करोड़ रुपये से योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में क्लाइमेट स्मार्ट कृषि की बात कही जा रही है। सरकार की सोच है कि नई विधियों से ही उपज बढ़ाने की चुनौती और खेती के अवसरों की पहचान करते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती किसानों के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। इसी कारण उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। इस स्थिति में सुधार तभी आएगा जब किसानों को सही समय पर सही सलाह मिले और वे फसल संरक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए पैदावार बढ़ा सकें। राज्य सरकार फसल सहायता योजना के लिए भी सभी जिलों में अलग प्रकोष्ठ बना रही है। वैसे किसान जिन्हें चालू वर्ष में फसलों के नुकसान के बावजूद फसल सहायता योजना का लाभ नहीं मिल सका, वे अपने जिले के प्रकोष्ठ में जाकर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और यदि किसी तरह की त्रुटि रह गई हो तो उसे दूर सकेंगे। उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना भी इस करार का एक हिस्सा है।

खेती में हो रहे बदलावों की जानकारी देना व नवीनतम तकनीक से ही किसानों को अपेक्षित लाभ मिल सकता है। सरकारी मशीनरी को भी उनका साथ देना होगा।

अब सरकार और विभागीय अधिकारियों को समझौते के कार्यान्वयन पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि इस करार का अधिकतम फायदा कृषि और किसानों को मिल सके। आज देश में कृषि की दशा किसी से छुपी नहीं है। एक समय देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में इसका योगदान पचास फीसद से अधिक होता था, लेकिन आज यह गिरकर 14 फीसद पर सिमट गया है। चिंता की बात यह है कि इस पर निर्भर आबादी में कमी नहीं आ रही है। अभी भी देश की करीब 60 फीसद जनसंख्या इस पर निर्भर है। जाहिर है जब खेती आय का बड़ा साधन नहीं रहा गया है तब इसमें लगे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं हो सकेगी। सच्चाई तो यह है कि अधिकांश किसान खेती से अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। देश में किसानों की बढ़ती आत्महत्या के पीछे यह एक मुख्य कारण है। उम्मीद है कि बिहार सरकार द्वारा अमेरिकी संस्था पर्यावरण रक्षा कोष के साथ किए गए समझौता से प्रदेश में कृषि संकट दूर होगा और किसानों की स्थिति सुधरेगी।

हिमाचल प्रदेश

परंपरा के नाम पर अत्याचार अनुचित

जनहित में किसी परंपरा को निभाया जाना सराहनीय है, लेकिन इसके नाम पर किसी पर अत्याचार किया जाना सही नहीं है। समय के साथ कई परंपराओं में बदलाव भी आया है, लेकिन अब भी कई परंपराएं निभाई जा रही हैं। यदि परंपरा के लिए किसी बेजुबान पर अत्याचार किया जाता है तो यह दुखद ही नहीं, गंभीर मामला है। कई लोग शौक के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के कई मामले सामने आते रहे हैं। कई लोग तेंदुए की खाल व नाखून आदि के लिए शिकार करते हैं तो कई जानवरों का शिकार मांस के लिए भी किया जाता है। कई लोग घरों में मोर पंख भी रखते हैं। राज्य में भी इस तरह की कई परंपराएं हैं। कुछ क्षेत्रों में टोपी पर मोनाल की कलगी लगाई जाती रही है। यह देखने में सुंदर लगती है। फैशन के लिए किसी पशु या पक्षी को मारा जाना कतई सही नहीं है। एक पशु प्रेमी ने इस संबंध सरकार को शिकायत भेजी थी। सरकार ने इस पीड़ा को समझा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जो व्यक्ति मोनाल का शिकार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लुप्त प्राय मोनाल आठ से 15 हजार फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। हालांकि अब इनकी संख्या में काफी कमी हो गई है। इनके सिर पर चटक हरे बैंगनी रंग की कलगी होती है। इस कलगी को हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के लोग टोपी पर लगाते रहे हैं। अब सरकार ने मोनाल की कलगी टोपी पर लगाने के मामले में सख्त रुख अपना लिया है। अब किसी ने टोपी पर कलगी लगाई है तो उसे बताना होगा कि वह उसे कहां से लाया है। शिकायतकर्ता ने टोपी पर कलगी लगाने वालों से भी आग्रह किया है कि वे भी इसका प्रयोग न करें। सरकार का इस शिकायत पर संज्ञान लेना और निर्देश जारी किया जाना निःसंदेह सराहनीय कदम है। इससे निरीह प्राणी का शिकार रुकेगा व लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके इन पक्षियों को भी बचाया जा सकेगा। लोगों को भी चाहिए कि वे पहल करें कि किसी प्राणी को मार कर किसी परंपरा या फैशन को पूरा न करें। पशु-पक्षी भी धरती के शृंगार में अहम हैं। इनका संरक्षण किया जाना हर व्यक्ति का दायित्व है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की परंपराएं रुकेंगी।

प्रतीकात्मक फोटो

पशु-पक्षी भी धरती के शृंगार में अहम भूमिका निभाते हैं। लोगों को चाहिए कि वे किसी प्राणी को मार कर परंपरा या फैशन को पूरा न करें।

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट में संशोधन की मांग करेगा पंजाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

गहराते जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक केवल नदी जल विवाद पर सीमित होकर रह गई। सर्वसम्मति से केंद्र से अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट में संशोधन की मांग करने का फैसला हुआ। गिरते भूजल स्तर, प्रदूषित होते नदियों के पानी आदि पर कोई फोकस दिखाई नहीं दिया। भूजल बचाने के लिए वैकल्पिक फसलों की कोई कार्ययोजना भी बैठक से नहीं निकल सकी। बैठक में नदियों के पानी की उपलब्धता का पुनः मुल्यांकन करने की मांग उठी। कहा गया कि भारत सरकार को यह यकीनी बनाना चाहिए कि पंजाब की तीन नदियों का पानी किसी भी हालत में बेसिन से नॉन-बेसिन इलाकों में स्थानांतरित न किया जाए।

सर्वसम्मति से नए ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए प्रस्तावित अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट में जरूरी संशोधन करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि पंजाब की कुल मांग और भावी पीढ़ियों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त पानी मुहैया करवाना जरूरी है। सीएम ने कहा कि इराडी कमीशन के अनुसार पंजाब के नदियों में पानी 17 एमएएफ (मिलियन एकड़ फीट) से घटकर अब 13 एमएएफ रह गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री के समक्ष मांग रखी है कि पंजाब की तीन नदियों में पानी का मौजूदा स्तर पता करने के लिए नया कमीशन स्थापित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वह फिर इसके लिए अपील करेंगे। उनकी सरकार संबंधित महत्वपूर्ण मसलों पर विचार करने के लिए हर छह महीनों बाद सर्वदलीय बैठक बुलाएगी।

यह है प्रस्ताव: 'पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है और भूजल का स्तर तेजी से घटने और दरियायी पानी की कमी के कारण पंजाब के मरुस्थल बनने की आशंका है। पंजाब में 73 प्रतिशत सिंचाई जरूरतों को पूरा करने वाला भूजल अब बहुत नीचे जा चुका है। इस वजह से किसानों और गरीब लोगों की रोजी-रोटी का बड़ा खतरा बना हुआ है। यह सर्वसम्मति से संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पंजाब के दरियायी पानी को तीन दरियाओं (रावी, सतलुज व ब्यास) के बेसिन से नॉन-बेसिन इलाकों में दुनिया भर में अपनाए गए तटीय सिद्धांत (रिपेरियन प्रिंसिपल) के मुताबिक किसी भी सूरत में स्थानांतरित न किया जाए। पानी की उपलब्धता का पुनः मुल्यांकन करने के लिए प्रस्तावित अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट के अधीन नया ट्रिब्यूनल स्थापित करने संबंधी संशोधन करना भी शामिल है।

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आल पार्टी बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए। साथ में हैं उनके (बाएं) भाजपा नेता मदनमोहन मित्तल, अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंदड़, आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा। जागरण

नेताओं ने ये उठाए मुद्दे

दरियाई पानी के साथ-साथ हमें गिरते जल स्तर के बारे में भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। एक रुपये लीटर पानी का मूल्य लगा लिया जाए तो एक किलो चावल के लिए 33 रुपये का पानी खर्च कर रहे हैं।
-सुनील जाखड़, प्रदेश प्रधान, कांग्रेस

पंजाब को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पानी की मौजूदा स्थितियों का ताजा मूल्यांकन करने की मांग करनी चाहिए और रिपेरियन कानून के अनुसार पानी का पुन: विभाजन करना चाहिए। प्रदूषित पानी से कैंसर के मामलों की संख्या बढ़ रही है।
-हरपाल चीमा, आप विधायक

आरोप-प्रत्यारोप के बजाय पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा के लिए एकता दिखानी चाहिए। सतलुज यमुना लिंक नहर को बड़ा मुद्दा बताते हुए कानूनी हल के साथ-साथ इस मुद्दे की सियासी तौर पर भी पैरवी की जानी चाहिए। **-बलविंदर सिंह भूंदड़, राज्यसभा सदस्य**

गेहूं/धान के फसलीय चक्र को तोड़ने और फसलीय विभिन्नता को बढ़ावा देना चाहिए। **-मदन मोहन मित्तल, भाजपा**

दूसरी बार सर्वदलीय बैठक

पानी को लेकर पंजाब सरकार की ओर से दूसरी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इससे पहले 2004 में बुलाई गई थी। तब भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे।

पंजाब में रिटायर्ड अफसरों की पौ बारह, कलसी भी बने चेयरमैन

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पंजाब सरकार में रिटायर्ड अफसरों की पौ बारह है। सरकार ने एक और रिटायर्ड आइएएस अफसर को एक नई अथॉरिटी बनाकर चेयरमैन लगा दिया है। गृह विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एनएस कलसी को पंजाब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को कैप्टन सरकार में चेयरमैन बनाने की संख्या एक दर्जन हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन सरकार को बने तीन साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड और कॉर्पोरेशन व मार्केट कमेटियों में पॉलिटिकल लोगों को चेयरमैन नहीं बनायाया गया है। इस वजह से पार्टी के नेताओं में खासी नाराजगी है।

कलसी को चेयरमैन बनाने संबंधी विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्रा ने इसकी पुष्टि की है। दस दिन पहले मुख्य सचिव करण अवतार सिंह की अगुआई में बनी सर्च कमेटी ने एनएस कलसी और पूर्व आइएएस अधिकारी डॉक्टर जी वज्रालिंगम के नाम को शॉर्टलिस्ट करके मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने कलसी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। अथॉरिटी के दो अन्य मेंबर भी लगाए जाने हैं, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। इसी तरह मंडल स्तर पर भी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनेगी जिसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का चेयरमैन बनाया जा सकता है। इसको भी फिलहाल टाल दिया गया है।

दी गई है चुनौती: पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का चेयरमैन ब्यूरोक्रेट के बजाय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाने की मांग करते हुए एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने चुनौती दी हुई है जिसकी सुनवाई अप्रैल में होगी।

इन अथॉरिटीज का काम

एसपी रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच राज्य स्तर की कंप्लेंट अथॉरिटी करेगी। इससे नीचे रैंक के अधिकारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर सुनवाई मंडल स्तर की अथॉरिटी करेगी।

उत्तराखंड में जल्द अस्तित्व में आएगा प्लास्टिक पार्क

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में जल्द ही अब प्लास्टिक पार्क अस्तित्व में आएगा। इसके लिए ऊधमसिंह नगर के सितारंगज में 30 एकड़ जमीन तलाश ली गई है। इस पार्क में प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। सिडकुल इस पार्क की अवस्थापना का कार्य करेगा। इसकी लागत तकरीबन 92 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से 40 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी।

उत्तराखंड में प्लास्टिक पार्क बनाने की योजना वर्ष 2016 में बनी थी। इसके लिए तब 50 एकड़ जमीन भी तलाशी गई थी। हालांकि, निवेशक न मिलने के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। प्रदेश में वर्ष 2018 में हुए निवेशक सम्मेलन के बाद कई प्लास्टिक उद्योगों ने प्रदेश में अपने उद्योग लगाने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही इस पर अब तेजी से कार्य शुरू किया जा रहा है। दरअसल, प्लास्टिक पार्कों का निर्माण केंद्र की योजना का हिस्सा है। इसके तहत राज्यों में निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसी कड़ी में जुलाई 2018 में देहरादून में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान भी खोला गया है। इसका मकसद यह कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को प्रदेश में ही रोजगार मिल सके और कंपनियों को कुशल मानव संसाधन ढूंढने के लिए बाहर भी न जाना पड़े।

अब इस प्लास्टिक पार्क के निर्माण की कवायद तेजी हो गई है। इस पर अभी शासन स्तर पर काम चल रहा है। दरअसल, पार्क निर्माण के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाना है। इसकी अनुमति कैबिनेट से ली जानी है। इसे देखते हुए अब संबंधित पत्रावली तैयार की जा रही है ताकि इस प्लास्टिक पार्क का निर्माण जल्द से जल्द किया जा सके।

भूपेश ने केंद्र से मांगा कोयला रॉयल्टी के 4140 करोड़ रुपये

नई दुनिया, रायपुर

- संविधान और कानून के हवाले से कहा, रॉयल्टी पर है राज्य का है अधिकार
- राज्य की आठ कंपनियों ने एडिशनल लेवी के रूप में जमा की यह राशि
- 295 रुपये प्रति टन के हिसाब से लेवी जमा करती हैं कोयला उत्खनन करने वाली कंपनियां

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला पर वसूले गए 4140.21 करोड़ रुपये राज्य को देने की मांग की है। यह राशि राज्य के कोयला खदानों से उत्खनन करने वाली कंपनियों से एडिशनल लेवी के रूप में वसूला गया है। फिलहाल यह रकम केंद्रीय कोयला मंत्रालय के खाते में है। नियमों का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि रॉयल्टी पर राज्य सरकार का हक है। सीएम के इस पत्र को लेकर फिर सियासत गरमाने की संभावना जताई जा रही है।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस संबंध में केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। सीएम ने अपने पत्र में संविधान में उल्लेखित प्रावधानों, खनिज अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है। इसके अनुसार खनिज पर राज्य का अधिकार होता है। ऐसे में खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी, लेवी और अन्य कर वसूलने का अधिकार संबंधित राज्य का है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला : मुख्यमंत्री ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि छत्तीसगढ़ में संचालित कोल ब्लॉक से निकाले गए और निकाले जाने वाले कोयले की एडिशनल रॉयल्टी की राशि राज्य सरकार को देय होनी चाहिए। साथ ही सीएम ने छत्तीसगढ़ सरकार को रॉयल्टी देने के संबंध में कोयला मंत्रालय को पिछले पांच सालों में भेजे गए पत्रों का भी उल्लेख किया है।

इन कंपनियों ने किया है एडिशनल लेवी जमा

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ से आठ कोल आवंटियों ने 295 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एडिशनल लेवी कोल मंत्रालय के पास जमा की है। इनमें जायसवाल निको लिमिटेड ने 112.35 करोड़, जिंदल पावर लिमिटेड ने 1185.20 करोड़, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 2082.23 करोड़, मोनेट इस्पात लिमिटेड ने 238.09 करोड़, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड 234.22 करोड़, आरएपीएल (सारडा एनर्जी लिमिटेड) 142.63 करोड़ और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 145.49 करोड़ रुपये शामिल है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी पर विशेष

पहले बेटी तो बचाओ फिर आगे बढ़ाओ

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक तरफ बेटियों को आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं से जुड़े अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी। लिंगानुपात अभी भी साम्य को तरस रहा है। प्रतिकूल हालात में भी हमारी बालिकाएं हर क्षेत्र में नाम कमाने को आतुर हैं। हाल ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार में अगर 12 लड़के शामिल रहे तो दस लड़कियों ने भी खुद को शामिल कराया।

इसलिए मनाया जाता है

बच्चियों के गिरते लिंगानुपात के प्रति सजगता के चलते आज के दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके प्रति समाज में जागरूकता और उनकी शक्तियों के प्रति उन्हीं की सजगता के लिए साल 2008 से इस दिन को अब सरकार की ओर राष्ट्रीय कन्या विकास मिशन के रूप में मनाया जाता है।

प्रचलित है यह प्रसंग: इसी से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थीं। इसलिए आज के दिन उन्हें भी याद किया जाता है।

मनाने का तरीका: देशभर इस दिन को अलग-अलग तरह से मनाता है। सरकारी आयोजन होते हैं और सामाजिक संगठन अपने कार्यक्रम करते हैं। इस दिन सेव गर्ल चाइल्ड के नाम से जगह-जगह अभियान चलाए जाते हैं।

हर साल की अलग थीम: राष्ट्रीय बालिका दिवस को प्रदेश अलग-अलग थीम पर मनाते हैं। प्रदेश की स्थिति और जरूरत के मुताबिक सरकार विषय तय करती है और उसे लेकर आयोजन करती है।

इन बिंदुओं पर फोकस

देश में बेटियों के प्रति अलग तरह की मानसिकता ने समाज के साथ-साथ खुद बच्चियों के आत्मविश्वास को चुनौती दी है। उनके मन में असुरक्षा और असुविधा की भावना घर कर गई है। इसी के चलते इस दिन उनके अस्तित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सुरक्षा जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

वर्तमान स्थिति

149 वां स्थान
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में लिंगानुपात मामले में 153 देशों में भारत का स्थान। पिछले साल बेहतर स्थिति के साथ 108वें स्थान पर था। नेपाल 101वें और बांग्लादेश 50वें स्थान पर है।
- देश में 100 लड़के पर महज 91 लड़कियां
- पाकिस्तान में यह अनुपात 100 और 92 है

257 साल
रिसर्च के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व के मामले में भारत में बराबरी लाने में लगेंगे 257 साल। पिछले साल ये आंकड़ा 202 का साल था।

देशभर में लड़कियों के लिए चल रहीं योजनाएं

- धन लक्ष्मी योजना, भारत सरकार (महिला और बाल विकास मंत्रालय)
- भाग्यलक्ष्मी योजना, कर्नाटक
- लाडली लक्ष्मी योजना, मप्र
- बालिका संरक्षण योजना, आंध्र प्रदेश
- लाडली योजना, दिल्ली और हरियाणा
- राजलक्ष्मी योजना, राजस्थान (बंद कर दी गई है)
- रक्षक योजना, पंजाब
- बालिका समृद्धि योजना (बीएसवाई), गुजरात
- बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल प्रदेश
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बिहार
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बिहार
- कुंअरबाइनू ममेरू योजना, गुजरात
- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, हिमाचल प्रदेश
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मध्य प्रदेश

सशक्तिकरण के अन्य प्रयास

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- महिला हेल्पलाइन
- उज्ज्वला
- कार्यरत महिला आवास योजना
- स्वाधार गृह योजना
- नारी शक्ति पुरस्कार
- राज्य महिला सम्मान, जिला महिला सम्मान
- स्त्री शक्ति पुरस्कार
- महिला इ-हाट
- निर्भया
- महिला शक्ति केंद्र
- महिला पुलिस वालेंटियर

तंत्र के गण

उत्सव गणतंत्र का...

कब बदलेंगे हालात...

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अब भी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाएं एसिड अटैक का शिकार हो रही हैं। दुकानों पर एसिड की खुली बिक्री पर प्रतिबंध के लिए नियम बना, लेकिन क्या हुआ? आज भी आसानी से सभी जगह मामूली सी कीमत पर एसिड मिल जाता है।
लक्ष्मी अग्रवाल, एसिड अटैक सर्वाइवर

नई दिल्ली में एसिड बिक्री के खिलाफ जागरूक करतीं लक्ष्मी। ● फोटो सौ. लक्ष्मी

शोषण के विरुद्ध अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में महिलाओं, बच्चों, कमजोर तबकों को शोषण से बचाने के उपाय किए गए हैं।

जीना इसी का नाम है : एसिड अटैक पीड़िताएं, जिन्होंने झेला भीषण त्रासदी का दर्द

इनके हौसले को सलाम...

कल की खातिर बोलता बचपन

बैठक करते मुन्ना मुन्नी मंच के सदस्य। ● जागरण

प्रशांत ● मुंगेर

बच्चों का एक ऐसा मंच, जिसके माध्यम से न सिर्फ वे अपनी बात रखते हैं, बल्कि समाज को भी जागरूक करते हैं। इसका नाम है मुन्ना-मुन्नी मंच। बिहार के मुंगेर जिले में दिशा विहार संस्था ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में यह अनूठी पहल की है।

यौन शोषण के विरुद्ध मुहिम: मुन्ना-मुन्नी मंच बच्चों को यौन शोषण से बचाने से लेकर शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित कराने आदि को लेकर सतत मुहिम चला रहा है। मुंगेर के 55 गांवों में मुन्ना-मुन्नी मंच गठित किया गया है। इनमें प्राथमिक ओर उच्च विद्यालयों के छात्र-छात्राएं हैं। अभी मंच से 3600 बच्चे जुड़े हुए हैं।

हर माह होती है बैठक: मंच से जुड़े बच्चे माह में एक बार बैठक करते हैं, जिसमें उनके अधिकारों और समस्याओं से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा होती है। इसमें आम तौर पर हमारा विद्यालय कैसा हो, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, बच्चों के यौन शोषण, बाल विवाह आदि मुद्दे होते हैं। चर्चा में जो भी मुद्दे निकलकर आते हैं, उस अनुरूप इसे अंजाम भी दिया जाता है। इस मंच ने बीते पांच सालों में 82 बच्चियों का विवाह रोकने में कामयाबी हासिल की। दिशा विहार के सचिव अभय कुमार अकेला ने बताया कि गांवों में किशोरी मंच का गठन भी किया है।

कश्मीर की हमराही बनी कुर्रत

बच्चों को पढ़ातीं कुर्रत-उल-ऐन। ● जागरण

नवीन नवाज ● श्रीनगर

जीवन का अधिकार

उम्मीद की किरण और कुर्रत। दोनों आज कश्मीर में एक-दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। अगर किसी को कहीं कोई बेसहारा बच्चा नजर आता है तो वह आश को याद करता है। अगर किसी गरीब की बेटी की शादी है या शादी नहीं हो रही है तो वह किसी के आगे मदद के लिए हाथ फैलाने के बजाय आश का सहारा लेता है। पढ़ाई के लिए पैसा आड़े आ रहा है तो भी आस नाम की संस्था हम राही बन जाती है।

वर्ष 2011 में कुर्रत-उल-ऐन ने अकेले जो सफर शुरू किया था, वह अब कारवां बनता जा रहा है। घाटी में कुकरमुत्तों की तरह अनाथाश्रम आश के कारण बंद हो चुके हैं। अगर कहीं कोई है तो वह वहां बच्चों को मुफ्त का खाना देकर अपनी जिम्मेदारी की इत्तिश्री नहीं समझ सकता, उसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी साफ-सफाई, स्वास्थ्य और उनके मानसिक विकास की जिम्मेदारी को भी निभा रहा है। आठ साल के दौरान घाटी में एक हजार से ज्यादा बच्चों की मदद आश ने की है। वह अकेली महिलाओं को आर्थिक व मानसिक रूप से मजबूत बना उन्हें बच्चों को अनाथाश्रम में भेजने के बजाय साथ रख उन्हें जिदगी में कुछ करने का हौसला देती हैं। 100 से ज्यादा लड़कियों की शादी जो दहेज व अन्य कारणों से नहीं हो रही थी, सामूहिक निकाह के जरिए दो वर्षों में कुर्रत के प्रयासों से हुई है।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी: अपने सफर के बारे में जागरण के साथ बातचीत में कुर्रत हंसते हुए कहती हैं कि मेरी मां और परिवार के अन्य लोग मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। घर का माहौल कुछ रूढ़िवादी था। इसलिए जब मैंने इंजीनियर की पढ़ाई छोड़ समाजसेवा के क्षेत्र में बढ़ने का फैसला किया तो विरोध भी हुआ। समाज सेवा में पहले स्नातक, फिर मास्टर्स किया।

तंत्र पर उठा रहीं सवाल : समझे समाज, सुधरे सिस्टम, मिले उपचार और न्याय

जमाना लाख निगाहें फेर ले हमसे... हम उसके लिए नहीं खुद के लिए जीते हैं... तू मुंह चुरा ले ऐ जिंदगी हमसे...मेरे हौसलों के आगे तो तुझे झुकना ही है... हर एसिड सर्वाइवर अपने पीछे की जिंदगी को भूल आज सुखन भरी दुनिया में जीने की जुगत में जुटी हैं। यह काम कितना कठिन है, इसे केवल वही महसूस कर सकती हैं। लेकिन हर पल हर कठिनाई को हराते हुए वे जी रही हैं या यू कहें कि हल पल लड़ रही हैं। इनके इस हौसले को हम सलाम करते हैं! नई दिल्ली से मनु त्यागी की रिपोर्ट :

क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा, हौसले जो बुलंद है मेरे...: रूपा, ऋतु, शबनम, मधु (बाएं से) मुस्कान से यही संदेश दे रही हैं। ● सौ. छांव फाउंडेशन

लक्ष्मी अग्रवाल, ऋतु, रूपा, बाला, शबनम मधु... हर पीड़िता अपने पीछे दिल दहला देने वाली एक हकीकत लिए आगे बढ़ रही है। समाज से इनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है बल्कि हर पल-हर दिन-हर जगह यह संघर्ष आज भी जारी है। ये आज भी उस समाज से लड़ रही हैं, जिसने इनके दुख के समय साथ नहीं दिया। आज भी इन्हें समाज से अपने हिस्से की हमदर्दी की आस है। एसिड अटैक जैसी भीषण त्रासदी झेल चुकीं इन पीड़िताओं का इनके परिवार के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। न किसी ने उफ किया, न विरोध कि ऐसा फिर किसी और के साथ न हो। एक के बाद एक घटनाएं होती रही हैं, हो रही हैं।

पीड़ा को बढ़ा देता है परिवार पर पड़ा आर्थिक बोझ : ऋतु कहती हैं, आस पड़ोस हो या शहर, सभी ने अपनी नजरों और बातों से हमारी पीड़ा को और बढ़ाया। आज आपको भले ही मेरे चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, लेकिन आपको पता है कि चेहरे को बचाए रखने के लिए एक सर्वाइवर को कितनी सर्जरी झेलनी पड़ती हैं। ऑपरेशन होगा, यह सुनते ही परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ दुख को और बढ़ा देता है। सोचिए, जब 10-15 सर्जरी होनी हों तो क्या हाल होगा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि परिवारों ने क्या-क्या झेला होगा। अब हम सब मिलकर इस प्रयास में जुटी हैं कि आगे औरों को आर्थिक, सामाजिक व मानसिक कष्ट न सहना पड़े।

आरक्षण ही नहीं, प्रशिक्षण भी जरूरी... : सर्वाइवर बाला कहती हैं कि हमे दिव्यांग की श्रेणी में रखकर सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण तो दे दिया, लेकिन क्या कभी किसी सरकार ने हम पीड़िताओं से पूछा है कि कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आप को जानकर हैरानी होगी कि अधिकतम पीड़िताएं बहुत कम पढ़ी-लिखी होती हैं। चाहे आप किसी भी शहर में देख लीजिए। मैं, बिजनौर, उप्र से हूं, पांचवी पास हूं। बगैर आगे की पढ़ाई किए यहां शीरोज रेस्त्रां में कंप्यूटर पर भी काम कर लेती हूं। जरूरत आरक्षण की नहीं बल्कि एक उचित दिशा में प्रशिक्षण की है। किसी भी रोजगार के काबिल बनाने के लिए प्रशिक्षण देना ज्यादा उचित रहता है। एक सर्वाइवर जिसने 12-13 सर्जरी झेली हों, वो स्वस्थ नहीं रह पाती। पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी तलाशो, तब जाकर आरक्षण मिलेगा। यह कष्टप्रद है। उप्र सरकार ने हमें दिव्यांग कार्ड की भी सुविधा दी है। अटैक के बाद से मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब कार्ड बनवाने गई तो कहा गया कि दोनों आंखों से दिव्यांग होने पर ही कार्ड बनना संभव है। हालांकि औरों को इसका लाभ मिला। अलीगढ़ की एक सवाईवर है, उसका कार्ड तुरंत बन गया। लेकिन सभी सवाईवर्स को समान रूप से सहयोग की जरूरत है।

लोगों के दिमाग में भरे एसिड को दूर करना है...: ऋतु कहती हैं, मेरा चेहरा देख रही हैं 15 सर्जरी के बाद ऐसा दिखता है। मैं ऐसा ही चेहरा लेकर कुछ दिन पहले एक दुकान से एसिड लेने गई, दुकान वाले ने मेरे से एक सवाल तक नहीं किया और बोतल पकड़ा दी। अब इसे क्या कहेंगे? हालांकि दुकान पर बिक्री से ज्यादा जरूरी लोगों के दिमाग में भरे एसिड को दूर करना है, दुकानों पर तो खुद बिकना बंद हो जाएगा। सरकार के स्तर पर सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलता है। उप्र की स्थिति बताती हूं हमसे जुड़ी कई सर्वाइवर हैं, जिन्हें कार्ड के माध्यम से इलाज तो मिलता है, लेकिन वहां तकनीकी कमी कहें या डॉक्टर्स का कम अनुभव, सर्वाइवर को कष्ट झेलना पड़ता है। वहीं मुझे देखिए मैं रोहतक, हरियाणा से हूं, यहां राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में देश-विदेश में कहीं भी इलाज की सुविधा दी हुई है, तो मैं दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज करा रही हूं। जहां सर्जरी महंगी तो है, लेकिन बहुत किफायत बगैर शारीरिक मानसिक कष्ट के इलाज होता है।

लचर है व्यवस्था, नहीं मिलता पूरा न्याय...: ऋतु ने कहा, जरूरत इस बात की है ऐसे मामलों को सरकार, समाज और न्यायालय बेहद संवेदनशील होकर देखें-बरतें। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हों ताकि बिना आर्थिक बोझ डाले समुचित उपचार मिल सके। पूरा न्याय मिले, अपराधी छूटने न पाएं। समाज की संवेदना और स्वीकार्यता मिले। क्योंकि जिस वक्त एक लड़की पर अटैक होता है तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरह से उसकी हालत दयनीय होती है। जरूरत सुलभ माहौल की है। हम खुद तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन समाज के इस शोषण के खिलाफ जरूरत है सरकारी, स्वास्थ्य और कानूनी सहयोग की। एक बेहद अहम बात और कहूंगी, मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, आरोपित को पांच साल की सजा हुई, लेकिन कुछ साल बीते हाईकोर्ट के जरिए वो छूट गया। मेरे पास नोटिस तक नहीं पहुंचा। अब यदि मुझे आगे लड़ाई लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट जाऊं। तो बताइए क्या इतना लड़ने के बाद मुझमें हिम्मत होगी कि अब मैं एक बार फिर न्याय की लंबी प्रक्रिया से जूझ सकूं? मैंने सैंकड़ों एसिड पीड़िता देखीं, लेकिन लक्ष्मी वाले मामले को छोड़ दें तो कभी किसी को मिसाल वाला न्याय नहीं मिल सका। आरोपित कुछ दिन बाद ही जेल के बाहर होते हैं।

जिन्होंने दी सर्वाइवर्स को हिम्मत

- छांव फाउंडेशन, शीरोज रेस्त्रां लखनऊ व आगरा
- मीर फाउंडेशन
- एसिड सर्वाइवर्स एंड वीमेन वेलफेयर फाउंडेशन, कोलकाता

दस साल की सजा

इसमें भारतीय दंड संहिता की 326ए और 326बी धाराएं जोड़ी गई थीं। इन धाराओं के तहत गैर-जमानती अपराध मानते हुए इसके लिए न्यूनतम सजा 10 साल रखी गई।

30 रुपये में मिल जाती है एसिड की बोतल

- छांव फाउंडेशन के संचालक आशीष बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आरटीआइ दाखिल कर जब एसिड बिक्री को लेकर स्थिति का आकलन किया गया तो अमूमन हर जिले से नकारात्मक जवाब मिला। लखनऊ में तो हाल ही में कोर्ट में इसी मामले पर हमारी याचिका के बाद जिला अधिकारी को फटकार तक लगी थी।
- मध्य प्रदेश में याचिकाकर्ता और वकील ने सर्वे किया, जहां 50 से ज्यादा दुकानदार बिनी किसी पहचान पत्र और पूछताछ के एसिड देने को तैयार हो गए।

एसिड बिक्री के नियम

- 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जा सकता।
- एसिड व्यापारी खरीदने आए हर ग्राहक से पूछे, उसे क्यों चाहिए?
- व्यापारी हर ग्राहक का पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से ले।
- जो विक्रेता नियमों का पालन नहीं करें, उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना।

एक एसिड सर्वाइवर को जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश करतीं सर्वाइवर इबाला (बाएं)।

निश्शुल्क मिले इलाज

वर्ष 2013 में लक्ष्मी अग्रवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को गंभीर अपराध माना था और सरकार, एसिड विक्रेता और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।

दिव्यांग की श्रेणी में सर्वाइवर्स

सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए उसमें एसिड अटैक्स सर्वाइवर्स को भी शारीरिक दिव्यांग के तौर पर शामिल करने का प्रावधान किया। इससे शिक्षा और रोजगार में उनको 3 फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

बदलती तस्वीर : एसिड अटैक पीड़िता दिल्ली निवासी लक्ष्मी अग्रवाल। ● फाइल

कानून ही पर्याप्त नहीं, पालन भी हो...

एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल, जिन्होंने इस विषय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी, उस के बाद एक ऐसा कानून बन सका कि अस्पताल में सर्वाइवर्स के इलाज के लिए कुछ सहूलियत होने लगी। लक्ष्मी कहती हैं कि आज कुछ चीजें बदली तो हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अब भी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाएं ज्यादा शिकार हो रही हैं। दुकानों पर एसिड की खुली बिक्री पर प्रतिबंध के लिए नियम बना, लेकिन क्या हुआ? आज भी आसानी से सभी जगह मामूली सी कीमत पर एसिड मिल जाता है। लक्ष्मी ने दुख जताते हुए कहा, हाल ही का वाकया बताती हूं फिल्म छपाक आई, उसकी शूटिंग के दौरान टीम के लोगों को दुकानों पर एसिड खरीदने के लिए भेजा गया तो उन्हें बगैर कोई प्रमाण दिखाए एसिड की 24 बोतलें आसानी से मिल गईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी नियमों का यह हाल है तो ऐसे कानून का क्या फायदा?

रूढ़ीवादी सोच के खिलाफ जारी है संघर्ष

विनय कुमार ● कोलकाता

संविधान भले नागरिकों को समानता का अधिकार देता हो लेकिन समाज में व्याप्त कुरीतियां और रुढ़ीवादी सोच आज भी महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। स्वयं ने इसी के खिलाफ बंगाल में पिछले ढाई दशक से मुहिम छेड़ रखी है। यह संस्था भेदभाव की शिकार महिलाओं को कानूनी सलाह व सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रहने की जगह और रोजगार मुहैया करा रही है।

संस्था से मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर के तौर पर जुड़ी सुचंद्रा चटर्जी ने बताया, हम शोषण की शिकार महिलाओं को निश्शुल्क कानूनी सलाह प्रदान करने के साथ ही उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ते हैं। इस मुहिम में कलकत्ता रेस्क्यू नामक संस्था भी साथ मिलकर काम कर रही है। दरअसल, शोषित महिलाएं आवाज उठाने से डरती हैं। इसका कारण कहीं न कहीं समाज में पुरुषवादी सोच का हावी होना भी है। न्याय की आस में दर-दर भटक रहीं महिलाओं की मदद के लिए स्वयं हरसंभव प्रयास कर रही हैं।

सुचंद्रा चटर्जी। ● जागरण

'स्वयं' से मिला सहारा: नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर लैंगिक भेदभाव की शिकार एक महिला ने बताया-%परिवार में मेरे साथ वह सब हुआ, जो एक सभ्य महिला पसंद नहीं करेगी। मैं उत्पीडन् से मानसिक रूप से टूट चुकी थी। ऐसे में स्वयं ने सहारा दिया। स्वयं ने मुझे निश्शुल्क कानूनी सलाह प्रदान की और न्यायालय तक मेरी लड़ाई लड़ी। आज मैं सम्मान से जीवन यापन कर रही हूं।' एक अन्य महिला ने बताया-%बस्ती इलाके में महिला उत्पीडन् और घरेलू ड्क्षहसा के खिलाफ आवाज बनकर उभरी इस संस्था से जुडने् के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार से मुझे जीने का नया आधार मिला है।'

डायन कुप्रथा पर कर रहे प्रहार

दिलीप कुमार ● जमशेदपुर

अंधविश्वास आधारित कुरीति डायन कुप्रथा के खिलाफ कड़ा कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जमशेदपुर, झारखंड के प्रेमचंद इस लड़ाई में लंबे समय से रत हैं और प्रभावी तरीके से आवाज उठा रहे हैं। प्रेमचंद की संस्था फ्लैक (फ्री लीगल एड कमेटी) ने ही बिहार सरकार को डायन कुप्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1995 का ड्राफ्ट सौंपा था। इसी के आधार पर बिहार सरकार ने 1999 में कानून बनाया था।

देश में यह पहली सरकार थी, जिसने डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। बाद में इसी कानून को सात राज्यों ने अपनाया। जिसमें बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और ओडिशा शामिल हैं। अब भी जहां कहीं भी डायन के नाम पर हत्या या उत्पीडन् की शिकायत मिलती है, प्रेमचंद वहां पहुंच जाते हैं। वह पीड़ित की मदद करने के साथ प्रताड़ित करने वालों को सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अंधिवश्वास के खिलाफ जागरूकता को कक्षा छह से लेकर पीजी तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए विभाग को पत्र लिखा है।

अंधिवश्वास के खिलाफ जागरुकता जरूरी: प्रेमचंद कहते हैं कि डायन कुप्रथा का अस्तित्व अशिक्षा और अंधिवश्वास के कारण है। जागरूकता इसके खिलाफ एक बड़ा हथियार है। झारखंड में डायन-बिसाही के नाम पर महिला-पुरुषों को प्रताड़ित करने और पीट-पीट कर मार डालने की घटनाएं आम हैं। अमानवीय प्रताड़ना का सिलसिला आज भी जारी है। हिंसा की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही होती हैं। आम लोगों के सहयोग से ही इसपर पूरी तरह अंकुश लग सकता है। राज्य में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 बना, बावजूद इसके डायन-बिसाही के नाम पर प्रताड़ना और हत्या के मामलों में कमी नहीं आ रही है, लेकिन इस कानून ने पीड़ितों को सहारा जरूर दिया है।

राष्ट्रीय कानून की वकालत: प्रेमचंद कहते हैं कि यह सामान्य नहीं, सामाजिक मनोविज्ञानिक समस्या है। इसे खत्म करने के लिए मिशन आधारित कार्यक्रम चलाना होगा। सरकार को राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। ग्रासरूट से लेकर ऊपर के स्तर तक काम करने, इसके रोकथाम के लिए सभी में इच्छाशक्ति का संचार होना चाहिए। ओझा-गुनी की प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग किए जाने की जरूरत है ताकि वे कुप्रथाओं को बढ़ावा देने के बजाय इनके उन्मूलन में सहायक बनें। ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक रूप से जड़ी-बूटियों के जानकार लोगों की काबिलियत को सही दिशा में मोड़कर उनका लाभ उठाने, गांवों में हर्बल पार्क विकसित करने जेसी रणनीति भी मददगार साबित हो सकती है।

संघर्ष के बाद मिली सफलता: प्रेमचंद बताते हैं कि वर्ष 1991 की एक घटना ने उन्हें और उनके साथियों को अंदर से हिला दिया। तब जमशेदपुर के मनीकुई गांव में एक महिला को डायन होने के आरोप में पीटा जाने लगा, बचाव करने पर उसके पति व एक बेटे को भी पीट-पीट कर मार डाला गया। इस घटना के बाद मैंने तय कर लिया कि डायन कुप्रथा के खिलाफ जो भी हो सके, करना है।

प्रेमचंद उम्मीद जताते हैं कि आधुनिक समाज एक दिन अवश्य चेतेगा क्योंकि ऐसी क्रूरता किसी सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है।

> फ्लैक संस्था ने इस विषय को कक्षा छह से स्नातकोत्तर तक की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की मांग की है, ताकि इसकी भयावहता को विद्यार्थी जान सकें। टीवी सीरियल और फिल्मों में भूत-पिचाश और डायन आदि के प्रदर्शन पर रोक लगाना भी जरूरी है। ओझा गुनी को ही गांव में इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
> **प्रेमचंद**, सामाजिक कार्यकर्ता, जमशेदपुर

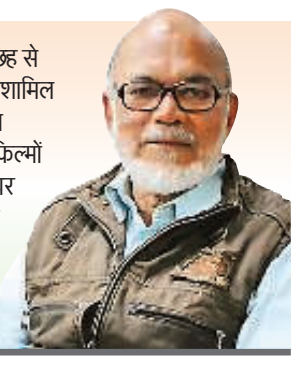

चार जिलों में मिले थे 176 मामले

वर्ष 2000 में यूनिसेफ के साथ मिलकर फ्लैक संस्था ने झारखंड के चार जिले पूर्वी सिंहभम, रांची, बोकारो और देवघर में जन-जागरण और सर्वेक्षण का काम किया। चार जिलों के 26 प्रखंड की 191 पंचायतों और 332 गांवों में सघन अभियान चलाकर डायन-बिसाही के कुल 176 मामलों का पता लगाया गया। चारों जिलों में 176 महिलाओं पर प्रताडना का मामला अपने आप में बड़ा मामला था। प्रेमचंद कहते हैं कि इस आधार पर पूरे राज्य में यह आंकड़ा हजारों में होगा। टीम के लोगो अभियान में लगातार मिल रही सफलता से उत्साहित हैं। प्रेमचंद बताते हैं कि हमारा सपना झारखंड को इस कुप्रथा से मुक्त बनाने का है।

मानव तस्करों से लड़ बचाया सैकड़ों बच्चों का भविष्य

फहीम अख्तर ● रांची

झारखंड में मानव तस्करों ने अपना जाल चारों ओर फैला रखा है। गरीब बच्चे-बच्चियों का बचपन इस जाल में उलझकर रह जा रहा। तस्कर इन्हें झारखंड से ले जाकर दूसरे बड़े शहरों में बेच देते हैं। वहां इन बच्चों का जमकर शोषण होता है। तस्करों के खिलाफ राज्य में बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं सीता स्वांसी। सीता की संस्था दीया सेवा संस्थान ने अब तक दूसरे राज्यों से 950 लड़के-लड़कियों को रेस्क्यू कराया है।

सौ से अधिक मानव तस्करों को जेल भिजवा चुकीं सीता कहती हैं, हिंसा और यौन शोषण का शिकार बच्चों के चेहरे पर रिहाई के बाद जब मुस्कान देखती हूं तो जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तस्करों से मिलने वाली धमकी और खतरे इस खुशी के आगे कुछ भी नहीं। सीता ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर सैकड़ों पीड़ितों को न्याय और मुआवजा समेत सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है।

कई स्कूली बच्चों का कराया नामांकन: सीता ने बाल मजदूरी और मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया। उनके अभिभावकों को आर्थिक मदद दिलाई गई ताकि दोबारा ये बच्चे गरीबी के कारण दलालों के चंगुल में न फंसे। एक दशक पहले जब सीता की संस्थान ने मानव तस्करी, बाल मजदूरी, महिला हिंसा, यौन शोषण और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ काम शुरू किया था, तब लोगों को यह असंभव लगता था। वे बताना नहीं भूलते थे कि इस काम में कितना खतरा है, लेकिन सीता ने हौसला नहीं छोड़ा।

हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है: सीता स्वांसी ने मिसिंग चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है ताकि इस पर लोग जानकारी दे सकें। रोज दर्जनों फोन मानव तस्करी के खिलाफ आते हैं। तस्करी के शिकार बच्चे-बच्चियों को छुड़ाने के लिए पुलिस, सीआइडी, बाल संरक्षण आयोग, महिला आयोग से लेकर मानवाधिकार आयोग तक की मदद ली जाती है। टीमों का गठन कर छापेमारी कर बच्चों का रेस्क्यू कराया जाता है। दलालों के लिए सीता खौफ का दूसरा नाम है। संस्था के प्रयासों से मानव तस्करी के मामले में कमी आई है।

महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश: 3000 से अधिक महिलाओं को कानून की जानकारी देकर सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक किया गया है। डायन कुप्रथा के खिलाफ भी संस्था लंबे समय से काम कर रही है।

बचपन बचाओ आंदोलन के साथ जुड़कर कराया रेस्क्यू

सीता स्वांसी की संस्था दीया सेवा संस्थान की ओर से मानव तस्करी के 350 से अधिक मामले झारखंड के विभिन्न थानों में दर्ज कराए गए हैं, जिनकी लगातार मॉनीटरिंग की जाती है। लापता बच्चों को ढूंढ़ने में भी संस्था अहम भूमिका निभा रही है। सीता ने वर्ष 2013 में कैलाश सत्यार्थी के बचपन बचाओ आंदोलन के साथ जुड़कर 284 बच्चों को रेस्क्यू कराया था। 2012 में झारखंड के अलावा असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की 22 लड़कियों को भी तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। 950 बच्चों क रेस्क्यू करा चुकी हैं।

बिना बीआइएस मार्क वाले प्रेशर कुकर नहीं बिकेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग एवं आंतरिक कारोबार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने घरेलू प्रेशर कुकर के लिए गुणवत्ता से संबंधित नए मानक जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इस वर्ष पहली अगस्त से ऐसे किसी भी प्रेशर कुकर का उत्पादन, बिक्री, कारोबार या आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिस पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआइएस) मार्क नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्हें प्रेशर कुकर पर क्वालिटी स्टैंडर्ड की पूरी जानकारी देनी होगी।

बीती तिमाही में बायोलॉजिक्स और स्माल मॉलीक्यूल्स बिजनेस के दम पर हमारा रेवेन्यू बढ़ा। हमने बायोसिमिलर बिजनेस के मूल्यांकन की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।

— किरण मजूमदार शॉ
चेयरपर्सन व एमडी, बायोकॉन

सेंसेक्स	41,386.40	▲ 271.02	निफ्टी	12,180.35	▲ 73.45	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 40,723	▲ ₹63	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 47,082	▼ ₹95
$ डॉलर	₹ 71.26	▲ ₹0.07	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 62.44							

भारतीय अर्थव्यवस्था उड़ान भरने को पूरी तरह तैयार : पीयूष गोयल

अच्छे संकेत ▶ बदले परिदृश्य में भारत में निवेश को लेकर बना है जबर्दस्त माहौल

चार से पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में पैसा लगाने की तैयारी में

दावोस, प्रेट्र : भारतीय अर्थव्यवस्था उड़ान भरने को तैयार है। यहां निवेश को लेकर जबर्दस्त माहौल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के वार्षिक सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी भारत सरकार चर्चा करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चीजें फिर बढ़ती हुई दिखने लगी हैं। अर्थव्यवस्था उड़ान भरने को पूरी तरह तैयार है। चार से पांच बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में उनके आधे से ज्यादा कर्मचारी भारत में काम कर रहे होंगे। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) को लेकर गोयल ने कहा कि यह असंतुलित व्यापार समझौता है। यह उन सिद्धांतों को पूरा करता नहीं दिख रहा, जिन पर आठ साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए भारत ने इससे नहीं जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'भारत ने पहले ही आसियान देशों, जापान और कोरिया से द्विपक्षीय कारोबारी समझौता किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत चल रही है। अगले छह से आठ महीने में ऑस्ट्रेलिया से द्विपक्षीय कारोबारी समझौता हो जाने की उम्मीद है। आरसेप का कुल प्रभाव भारत और चीन के बीच एफटीए जितना ही रह जाता। मुझे नहीं लगता कि अभी भारत इसके लिए तैयार है, जब तक चीन से कारोबार में पारदर्शिता और भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार में पहुंच सुनिश्चित नहीं हो जाती है।' केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि व्यापार पर होने वाली बातचीत जटिल मुद्दा है। ऐसी बातचीत जल्दबाजी में या किसी डेडलाइन के साथ नहीं हो सकती है।

मंत्री नहीं होता तो एयर इंडिया के लिए लगा लेता बोली : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, 'इसके पास कुछ सबसे बेहतरीन बाइलेटरल्स हैं। इन बाइलेटरल्स के इस्तेमाल के लिए शानदार विमानों से लैस, बेहतर तरीके से प्रबंधित और दक्ष एयर इंडिया किसी सोने की खदान जैसी है। यदि मैं मंत्री नहीं होता तो इसके लिए बोली लगा लेता।' बाइलेटरल्स उस समझौते को कहा जाता है, जिसके तहत दो देश एक-दूसरे की विमानन कंपनियों को परिचालन की अनुमति देते हैं। गोयल ने कहा कि राजग सरकार को काफी खराब हालत में चल रही अर्थव्यवस्था संभालने को मिली थी। पहले अर्थव्यवस्था को सुचारु करने के लिए कदम उठाए गए। उस समय यदि सरकार एयर इंडिया को बेचती, तो सही मूल्य नहीं मिल पाता।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दावोस में चल रही डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक में एक सत्र को संबोधित करते हुए। प्रेट्र

सुधर रही है बैंकों की स्थिति

सत्र के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रंच के सवाल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार ने भरोसा जताया कि क्रेडिट मार्केट जल्द ही सामान्य स्थिति में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, 'कई कदम उठाए गए हैं। बैंकों में पूंजी डाली गई है। सरकारी बैंक भी मुनाफे की राह पर लौट रहे हैं। जिन चीजों को वक्त के साथ ठीक हो जाना था, वे ठीक हो गई हैं और बैंक अब पहले से ज्यादा सावधान हैं। हम कर्ज देने के लिए तैयार हैं।'

ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल में नरमी से आम जनता को होगा फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चीन में फैले वायरस व औद्योगिक मांग घटने की आशंका से कच्चे तेल के भाव में आ रही गिरावट
- एक महीने में नौ फीसद सस्ता हुआ क्रूड, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आगे भी राहत तय

राजकोषीय मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कच्चे तेल के दाम में मौजूदा गिरावट से काफी राहत मिल रही होगी। पिछले एक महीने में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल कीमतों में बढ़ोतरी की सारी संभावनाएं हवा हो चुकी हैं। वैश्विक मंदी की वजह से मांग पहले ही कमजोर थी और अब चीन में वायरस फैलने की डर इसमें और गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में तीन फीसद की गिरावट देखी गई। इस महीने कच्चे तेल की कीमतों में नौ फीसद की गिरावट आ चुकी है। इससे आम जनता को पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में आगे भी राहत मिलने के आसार हैं।

पिछले वर्ष नवंबर में भारतीय तेल कंपनियों ने औसतन 62.54 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा था। दिसंबर में इसकी औसत कीमत 65.52 डॉलर प्रति बैरल की थी। इस सप्ताह बुधवार के आंकड़े बता रहे हैं कि यह कीमत 64.31 डॉलर प्रति बैरल रही है। गुरुवार की तीन फीसद गिरावट के बाद इस महीने की औसत कीमत और नीचे आएगी। इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में साफ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष 11 जनवरी के बाद से दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 1.36 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 1.31 रुपये प्रति लीटर घट चुकी है।

प्रतीकात्मक फोटो

तेल कंपनियों के अधिकारी बताते हैं कि खुदरा कीमत में अभी और गिरावट होगी। वैश्विक मांग घटने की वजह से कई देश भारत के साथ बहुत ही अच्छी शर्तों पर कच्चे तेल का सौदा करने को तैयार हैं। ईरान-अमेरिका तनाव की वजह से जो हालात पैदा हुए थे वे क्षणिक साबित हुए हैं और अभी पूरी तरह से तेल खरीद करने वाले देशों के लिए उपयुक्त बाजार है।

कच्चे तेल में मंदी की निश्चित तौर पर एक वजह यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तरफ से मांग कम हुई है। कच्चे तेल के उत्पादक और निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष के अंत तक मांग के मुताबिक क्रूड का उत्पादन 10 लाख बैरल प्रति दिन का हो रहा था। ओपेक देशों की समस्या यह है कि उत्पादन में कटौती की जाए या नहीं, इस बारे में वे इस वर्ष मार्च से पहले फैसला नहीं कर सकेंगे। इसी बीच चीन में वायरस की वजह से औद्योगिक मांग में और कमी की आशंका है। गुरुवार को कच्चे तेल में गिरावट के लिए इसे ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अपनी जरूरत का 83 फीसद कच्चा तेल आयात करने वाले देश भारत के लिए यह शुभ समाचार है।

न्यूज गैलरी

रिलायंस रिटेल की फुल पैसा वसूल सेल शुरू

नई दिल्ली : रिलायंस रिटेल की फुल पैसा वसूल सेल फिर शुरू हो गई है। रिलायंस फ्रेश और रिलायंस स्मार्ट स्टोर्स पर 22 जनवरी से शुरू हुई इस सेल का फायदा 26 जनवरी तक उठाया जा सकता है। रिलायंस रिटेल साल में दो बार फुल पैसा वसूल सेल का आयोजन करती है। रिलायंस रिटेल तेजी से मेट्रो और छोटे कस्बों में उपस्थिति बढ़ा रही है। इस विस्तार के साथ ग्राहकों के बीच इस सेल का आकर्षण भी बढ़ता जा रहा है। पांच दिन की इस सेल में देशभर के ग्राहकों को रिलायंस फ्रेश और स्मार्ट स्टोर्स में फल, सब्जी, रसोई व घरेलू वस्तुओं समेत संपूर्ण प्रोडक्ट रेंज पर शानदार ऑफर का लाभ मिलेगा। देशभर में रिलायंस फ्रेश और स्मार्ट के 700 से ज्यादा स्टोर्स हैं। (वि.)

डीएचएफएल को 6,641 करोड़ रुपये का घाटा

नई दिल्ली : कर्ज के बोझ तले दबी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) में 6,640.62 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड शुद्ध घाटा हुआ है। एक वर्ष पहले की समान अवधि में कंपनी को 439.51 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी परिचालन आय गिरकर 2,106.71 करोड़ रुपये रह गई, जो उससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 3,483.32 करोड़ रुपये थी। (प्रेट्र)

नेशनल डाटा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा नीति आयोग

नई दिल्ली : नीति आयोग ने कहा है कि वह नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इस पर सभी सरकारी आंकड़े इस तरह रखे जाएंगे कि जिन्हें जरूरत हो उन्हें आसानी से मिल जाए। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) का विजन दस्तावेज लांच करते हुए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म आंकड़ों की सत्यता, निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा। डाटा ही नए युग की सबसे बड़ी संपत्ति है। (प्रेट्र)

घर खरीदारों को मिले अतिरिक्त छूट

बजट से उम्मीदें

- मांग बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को सहयोग की दरकार
- अर्थव्यवस्था को गति देने गति के लिए इस सेक्टर की मजबूती जरूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : नकदी संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से घर खरीदारों को टैक्स में अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए। उद्योग चैंबर सीआइआइ ने सरकार से यह अपील की है। चैंबर का कहना है कि अर्थव्यवस्था में छह से सात फीसद की विकास दर हासिल करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर मजबूत योजना जरूरी है। सेक्टर को नकदी के मोर्चे पर ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है।

सीआइआइ का कहना है कि घर खरीदारों को टैक्स में अतिरिक्त छूट के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आय सीमा को बढ़ाना भी सेक्टर के विकास के लिए अच्छा कदम हो सकता है। बजटपूर्व सुझावों में उद्योग चैंबर ने रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए एक्शन प्लान भी सुझाया है। सीआइआइ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, 'रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों मोर्चे पर रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था में कुल मांग पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।' सीआइआइ ने होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन के लिए सीमा को दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में एमआइजी 1 व 2 श्रेणियों के लिए आय सीमा को 12 और 18 लाख से बढ़ाकर क्रमशः 18 और 25 लाख करने का भी सुझाव दिया है। इससे समाज का बड़ा तबका लाभान्वित होगा और सेक्टर में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। उद्योग चैंबर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप और हाउसिंग सेक्टर को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की अपील भी की है। इससे डेवलपर्स को कम लागत में प्राथमिकता से फंड जुटाने का मौका मिल सकेगा।

प्रतीकात्मक फोटो

आयकर दरें कम होने की आस

मुंबई, प्रेट्र : अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार इस बार आम बजट में आयकर की दर में कटौती कर सकती है। कॉरपोरेट टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने पिछले साल बड़ी राहत दी थी। अब उद्योग जगत आयकर में राहत की उम्मीद कर रहा है। कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी की ओर से किए गए सर्वेक्षण में ज्यादातर लोगों ने भरोसा जताया कि इस बार आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये सालाना से बढ़ाने का बजट में एलान हो सकता है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाने और होम लोन पर अतिरिक्त छूट की भी उम्मीद है। सितंबर में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर को पुरानी कंपनियों के लिए 30 से 25 फीसद कर दिया था। अन्य छूट व इन्सेंटिव छोड़ने पर 22 फीसद की दर लागू होगी। नई कंपनियां सभी छूट व इन्सेंटिव छोड़ने की शर्त पर 15 फीसद की दर से कॉरपोरेट टैक्स भर सकती हैं।

एजीआर बकाया नहीं चुकाने वाली कंपनियों पर अभी कार्रवाई नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के मद में बकाए का भुगतान नहीं किया है। भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी की अंतिम तारीख तय की थी। हालांकि भुगतान की समयसीमा बढ़ाने की टेलीकॉम कंपनियों की याचिका पर शीर्ष अदालत ने अगले हफ्ते सुनवाई तय की है। इस बीच दूरसंचार विभाग ने बकाया नहीं चुकाने वाली कंपनियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया है।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर एजीआर के मद में 88,624 करोड़ रुपये का बकाया है। दोनों कंपनियों ने विभाग को बताया कि वे सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपनी याचिका पर आने वाले फैसले के अनुरूप बकाए का भुगतान करेंगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को अपने फैसले में दूरसंचार विभाग द्वारा एजीआर की गणना में गैर-दूरसंचार सेवाओं से मिलने वाले राजस्व को जोड़ने के फैसले को सही ठहराया था। इस मद में टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया है।

भारत से कच्ची चीनी की खरीद बढ़ाएगा मलेशिया

- पाम ऑयल पर नई दिल्ली के साथ तकरार कम करने का प्रयास
- इस वर्ष भारत से 1.3 लाख टन कच्ची चीनी खरीदने की तैयारी

मुंबई, प्रेट्र : मलेशिया की सबसे बड़ी शुगर रिफाइनिंग कंपनी एमएसएम मलेशिया होल्डिंग्स बरहाद इस वर्ष भारत से 1.3 लाख टन कच्ची चीनी खरीदेगी, जिसकी कीमत 4.92 करोड़ डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) होगी। पिछले वर्ष कंपनी ने भारत से लगभग 88,000 टन कच्ची चीनी खरीदी थी। माना जा रहा है कि एमएसएम की तरफ से चीनी आयात बढ़ाना भारत के साथ पाम ऑयल पर चल रहा विवाद शांत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

एमएसएम दुनिया की सबसे बड़ी पाम ऑयल उत्पादक एफजीवी होल्डिंग्स की चीनी रिफाइनरी शाखा है, जो मलेशियाई सरकार के स्वामित्व वाली यूनिट है। हालांकि कंपनी ने चीनी आयात बढ़ाने के फैसले को पाम ऑयल पर बढ़ी तनातनी से जोड़ने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन उद्योग जगत मानता है कि मलेशियाई सरकार का यह कदम भारत के साथ वर्तमान विवाद घटाने की दिशा में एक कदम है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है। लेकिन, पिछले महीने नई दिल्ली ने मलेशियाई रिफाइंड पाम ऑयल का आयात रोक दिया। असल में मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मुहमम्द ने पिछले कुछ समय के दौरान भारत सरकार की कश्मीर समेत कई अन्य सामयिक नीतियों पर बयान दिए हैं। मलेशिया से रिफाइंड पाम आयात पर प्रतिबंध को भारत सरकार की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत की अहमियत इसलिए : मलेशिया वैसे पाम तेल निर्यात के लिए भारत के अलावा अन्य बाजार तलाशने की कोशिश में है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि भारत पिछले पांच वर्षों से मलेशियाई पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। पिछले वर्ष भारत ने 44 लाख टन पाम ऑयल की खरीद की है।

भारत को मलेशिया का निर्यात पिछले वर्ष 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में 10.8 अरब डॉलर (करीब 75,600 करोड़ रुपये) था, जबकि आयात कुल 6.4 अरब डॉलर था।

गैस पाइपलाइन में होगा चार लाख करोड़ रुपये का निवेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कच्छ से कोहिमा और कोच्चि से कश्मीर तक गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना

देश की अर्थव्यवस्था को गैस आधारित बनाने में अगले दो वर्ष काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। अगले दो वर्षों में सरकार की योजना कच्छ से लेकर कोहिमा और कोच्चि से लेकर कश्मीर तक गैस पाइपलाइन बिछाने की है जो घरेलू गैस के साथ-साथ उद्योग और यातायात को भी गैस आधारित बनाने में काफी मदद करेगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक राष्ट्रीय आयोजन में कहा कि देशभर में गैस पाइपलाइन का ढांचा तैयार करने से चार लाख करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ होगा। अभी देश की अर्थव्यवस्था में गैस आधारित गतिविधियों की हिस्सेदारी महज 6.2 फीसद है जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 15 फीसद किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन में कई राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा गैस उद्योग से जुड़ी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया।

प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार गैस आधारित इकोनोमी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इसके तहत घरेलू गैस उत्पादन को बढ़ाकर 34.55 अरब क्यूबिक मीटर किया गया है। कीमत तय करने की छूट कंपनियों को दी गई है। पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में गैस पाइपलाइन के लिए 10,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दो वर्षों में देश के अधिकांश हिस्से में गैस पाइपलाइन बिछ जाएगी। उन्होंने शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर कहा कि 11वें दौर की निविदा जल्द ही जारी की जा रही है जिसके बाद 475 शहरों में गैस पाइपलाइन का ढांचा तैयार हो जाएगा।

हाईवे के कार्यों को रफ्तार देगा 'गति'

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास को अब 'गति' के माध्यम से तेजी मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा तैयार ऑनलाइन वेब पोर्टल 'गति' को लांच किया। इसे पीएमओ के प्रगति पोर्टल से प्रेरित होकर तैयार किया है।

पोर्टल तक एनएचएआइ की वेबसाइट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पोर्टल पर एनएचएआइ की परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं को उठाया जा सकेगा। समस्या सामने आते ही संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से उस पर काम करेंगे। एनएचएआइ में अधिकारियों की एक टीम द्वारा समस्याओं की दैनिक निगरानी की जाएगी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी समीक्षा की जाएगी। इससे न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग को गति देने के निर्णय में तेजी आएगी।

रबी सीजन में भारी पैदावार के अनुमान ने भंडारण को लेकर बढ़ाई चिंता

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- चालू सीजन में गेहूं की पैदावार 10.5 करोड़ टन से अधिक रहने का अनुमान
- इस सीजन की खरीद से पहले पांच करोड़ टन पुराना स्टॉक रहेगा

चालू रबी सीजन में गेहूं समेत अन्य फसलों की भारी पैदावार के अनुमान के बीच खाद्यान्न भंडारण की गंभीर चुनौती होगी। इसे लेकर सरकार के माथे पर अभी से बल पड़ने लगे हैं। रबी सीजन की खरीद शुरू होने के दिन तक भंडारण क्षमता का 75 प्रतिशत हिस्सा पुराने अनाज से भरा हुआ होगा। इसी के मद्देनजर भंडारण के अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय लगातार अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत करा रहा है। खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के लिए निर्धारित शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव भी नाकाफी माना जा रहा है। सरकार ने रेलवे के खाली पड़े कुछ गोदामों और शेड के उपयोग की बात कही, लेकिन विशेषज्ञों ने उसे खारिज कर दिया। इन गोदामों का उपयोग अनाज भंडारण के काबिल नहीं है। इसी तरह अनाज के मूल्य में लगभग डेढ़ रुपये प्रति किलो की कटौती कर खुले बाजार में बेचने के मसौदे पर भी सहमति नहीं बनी।

इस वर्ष की शुरुआत में सेंट्रल पूल में कुल 5.65 करोड़ टन अनाज था। अगले तीन महीने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए कुल लगभग 75 लाख टन अनाज की जरूरत होगी। इसे घटाने के बावजूद पुराने अनाज की मात्रा बहुत होगी। दरअसल, सरकार के पास बफर स्टॉक के मानक रूप में हर वर्ष पहली जनवरी को कुल 2.14 करोड़ टन अनाज होना जरूरी होता है। इसमें 1.64 करोड़ टन ऑपरेशन स्टॉक और 50 लाख टन स्ट्रैटेजिक स्टॉक होना चाहिए। इस वर्ष पहली जनवरी को पूल में केंद्रीय एजेंसियों के पास 3.19 करोड़ टन और राज्य एजेंसियों के पास 2.45 करोड़ टन अनाज का भंडार है। पूल के खाद्यान्न स्टॉक में 2.37 करोड़ टन चावल और 3.27 करोड़ टन गेहूं है। केंद्र व राज्य एजेंसियों के पास भंडारण की सुविधा का अभाव उनकी गेहूं खरीद में बाधा पैदा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी दशा में अस्थायी भंडारण का बंदोबस्त करना होगा, जो खुले में तिरपाल से ढंक कर किया जा सकता है।

सबसे ज्यादा मुश्किलें गेहूं उत्पादक राज्यों के सामने हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में केंद्रीय पूल का अनाज पड़ा हुआ है।

सुधरा हाल

बैंकिंग और ऑयल स्टॉक्स की मजबूती से बाजारों को मिला फायदा, सेंसेक्स में 271, निफ्टी में 73 अंकों का उछाल दर्ज किया गया

निचले स्तर पर खरीदारी से शेयर बाजार संभले

मुंबई, प्रेट्र : तीन लगातार सत्रों की गिरावट के बाद बैंकिंग और ऑयल स्टॉक्स के दम पर गुरुवार को सेंसेक्स ने सधी वापसी की। निचले स्तर पर निवेशकों द्वारा चुनिंदा स्टॉक्स में की गई खरीदारी के दम पर बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 271.02 अंक यानी 0.66 प्रतिशत चढ़कर 41,386.40 पर पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला निफ्टी चार लगातार कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद गुरुवार को 73.45 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 12,180.35 अंक पर स्थिर हुआ।

दिन के कारोबार में सेंसेक्स पैक में सबसे ज्यादा 2.98 प्रतिशत का उछाल लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) के शेयरों में दर्ज किया गया। भारती एयरटेल के शेयर भी 1.8 प्रतिशत उछले। बैंकिंग शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयर 2.26 प्रतिशत तक उछले। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल के दाम में गिरावट के चलते ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के शेयरों के प्रति निवेशकों की जबर्दस्त रुचि देखी गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, इन्फोसिस और अल्ट्राटेक सीमेंट को भी निवेशकों ने निराश नहीं किया। हालांकि टेक महिंद्रा, पावरग्रिड, टीसीएस, बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और मारुति सुजुकी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

प्रतीकात्मक फोटो

विशेषज्ञों का कहना था कि एशिया के अन्य बाजारों में निराशा के माहौल के बावजूद घरेलू बाजार में स्टॉक-केंद्रित खरीदारी ने बाजार का सकल रुख सकारात्मक रखा। गुरुवार को शेयर बाजारों की चाल के बारे में जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि बैंकिंग, ऑटो और मिड व स्मॉलकैप शेयरों में निचले स्तर पर खरीदारी से बाजार का पिछले कई सत्रों से गिरा मनोबल एक बार फिर ऊंचा हुआ। हमें लगता है कि निकट भविष्य में बाजार सतर्कता के साथ कारोबार करता दिखेगा।

सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो मैनेजर (इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स) हेमंग कापसी का कहना था कि गुरुवार को शॉर्ट-कवरिंग के चलते निफ्टी में थोड़ी मजबूती देखी गई। हालांकि निफ्टी का सकल प्रदर्शन कुछ सप्ताह से अच्छा नहीं रहा है। मिडकैप ने पिछले एक महीने में आठ प्रतिशत रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी का रिटर्न नकारात्मक रहा है।

इनमें गहमागहमी

भारती एयरटेल : कंपनी ने डीओटी को बताया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक एजीआर देनदारी का भुगतान नहीं करेगी। इसके चलते गुरुवार को सेंसेक्स में कंपनी के शेयरों में 1.8 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।

एलएंडटी : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान बेहतर वित्तीय नतीजों के चलते कंपनी के शेयर बीएसई में 2.98 प्रतिशत मजबूत हुए। निफ्टी में भी कंपनी के शेयरों में 2.80 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ दोगुना होने की खबरों के बाद इसके शेयर गुरुवार को 9.93 प्रतिशत उछलकर 52 सप्ताह के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। एनएसई में कंपनी के शेयरों में 10.03 प्रतिशत का उछाल दिखा।

ब्राजील के बाजारों में जल्द पहुंचने लगेगा भारतीय प्याज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ब्राजील की कृषि मंत्री ने तोमर व पासवान से मुलाकात कर जताई इच्छा
- चीनी, एथनॉल और पशु जर्म प्लाज्मा क्षेत्र में होंगे शीघ्र समझौते

भारत व ब्राजील के बीच कृषि क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की दिशा में सफलता मिली है। इसके तहत जल्द ब्राजील के बाजारों में भारतीय प्याज पहुंच सकता है। ब्राजील की कृषि मंत्री टेरीजा क्रिस्टीना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने मुलाकात कर भारतीय कृषि क्षेत्र में साझा व्यापार करने पर अपनी सहमति दी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को बहुत कम बताते हुए उसे बढ़ाने पर जोर दिया। विचार-विमर्श के दौरान व्यापार दोनों देशों की मौजूदा संभावनाओं के दोहन पर सहमति बनी।

कृषि मंत्री तोमर ने मुलाकात के दौरान ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल से भारतीय कृषि उत्पादों के आयात का आग्रह किया। इनमें खासतौर पर गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन, प्याज, किशमिश/मुनक्का और कपास है, जिनका ब्राजील आयात करता है। जबकि भारत में इन जिंसों की बहुतायत है। खाद्य मंत्री पासवान ने ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद बताया कि चीनी व एथनॉल संबंधित आधुनिक तकनीक व अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच अनुभव को साझा करने पर आम राय बनी। ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय चीनी संस्थान के साथ आम सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को हामी भरी। दुग्ध उत्पादन और भैंस प्रजनन की आधुनिक प्रौद्योगिकी पर दोनों देशों के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। ब्राजील ने भारतीय मुर्रा भैंसों में रुचि दिखाई है।

290 किलोमीटर तक मार कर सकती है बैलेस्टिक मिसाइल गजनवी। पाकिस्तान ने गुरुवार को इसका परीक्षण किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, प्रधानमंत्री इमरान खान और तीनों सेना के प्रमुखों ने परीक्षण के लिए सैन्यकर्मियों और देश को बधाई दी है।

चीन ने वुहान में पूरी तरह बंद की आवाजाही

कोरोना का प्रकोप ▶ एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इसी शहर से फैल रहा वायरस

अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत, करीब 600 संक्रमित

बीजिंग, एजेंसियां : चीन ने रहस्यमय कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र माने जा रहे एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले वुहान और समीप के 75 लाख की आबादी वाले हुआंगगांग शहरों में आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। गुरुवार से इन दोनों शहर में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई। सांस लेने में परेशानी का कारण बनने वाला यह वायरस चीन के कई शहरों को अपनी चपेट में लेने के बाद अमेरिका तक पहुंच गया है। चीन में इस वायरस के प्रकोप से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 600 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों को आशंका है कि चीन के नए साल (लूनर न्यू ईयर) की छुट्टियों के दौरान लाखों चीनी नागरिकों की देश-विदेश में आवाजाही से वायरस का प्रसार बढ़ सकता है। चीनी नया साल शनिवार से शुरू होगा। मध्य चीन के वुहान शहर के प्रशासन ने बताया कि शहर में सभी परिवहन नेटवर्क और बाहर जाने वाली उड़ानों को गुरुवार सुबह दस बजे से निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे वुहान से बाहर ना जाएं। इस एलान के कुछ घंटे बाद ही वुहान से 70 किलोमीटर दूर हुआंगगांग में भी इसी तरह की बंदिशें लगा दी गईं। वुहान के एक बाशिंदे ने बताया कि प्रमुख हाईवे पर सुरक्षाकर्मी गश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया में डाले गए वीडियो में वुहान में खाने-पीने और जरूरी सामान जमा करने के लिए सुपर मार्केट के साथ ही गैस स्टेशनों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं।

वुहान में चार हजार मामलों का अनुमान : चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बुधवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के 571 मामलों की पुष्टि की, लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अकेले वुहान में वायरस संक्रमण के करीब चार हजार मामले होने का अनुमान है।

ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी पर विचार कर रहा डब्ल्यूएचओ : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इस तरह की घोषणा होने पर कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास तेज कर दिए जाएंगे।

भारत समेत पूरी दुनिया में एयरपोर्ट पर हो रही जांच : कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रयास में भारत समेत लगभग पूरी दुनिया के एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को वुहान नहीं जाने की सलाह दी है।

अमेरिका में 16 लोग निगरानी में : अमेरिका के वाशिंगटन में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। इस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले 16 लोगों को निगरानी में रखा गया है।

सांप से इंसानों में वायरस पहुंचने का अंदेशा

समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार, नए प्रकार के कोरोना वायरस के सांप से इंसानों में पहुंचने का अंदेशा है जबकि चीनी अकादमी ऑफ साइंसेज की ओर से कराए गए एक दूसरे अध्ययन का दावा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चमगादड़ या सांप से हो सकती है।

चीन ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए वुहान शहर में सख्त पाबंदियां लागू की हैं। तस्वीर में मध्य चीन के हुबेई प्रांत के शहर वुहान में बंद रेलवे स्टेशन के बाहर बेंच को एक स्वास्थ्यकर्मी जीवाणु रहित कर रहा है। एपी

केरल की नर्स भी वायरस की चपेट में आई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सऊदी अरब के अस्पताल में काम करने वाली करीब 100 भारतीय नर्सों की जांच की गई। केरल निवासी एक नर्स चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि प्रभावित नर्स का असीर नेशनल अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से खाड़ी देश के सामने मामला उठाने और विशेष उपचार सुनिश्चित कराने की मांग की है। विदेश राज्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि अल-हयात अस्पताल में काम करने वाली नर्सों में से ज्यादातर केरल की हैं। करीब 100 भारतीय नर्सों की जांच कराई गई जिनमें से एक संक्रमित पाई गई है। अस्पताल प्रबंधन और सऊदी विदेश मंत्रालय से संपर्क रखा जा रहा है। वाणिज्य दूत को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

उड़ान में सबने पहना था मास्क

सिडनी, एएफपी : आवाजाही बंद किए जाने से ठीक पहले गुरुवार को चीन के शहर वुहान से रवाना हुई अंतिम उड़ानों में एक ऑस्ट्रेलिया की थी। इस पूरी यात्रा के दौरान विमान में सवार सभी लोग मास्क पहने रहे। सिडनी एयरपोर्ट पर विमान से उतरने पर सभी यात्रियों को सबसे पहले स्वास्थ्य अधिकारियों का सामना करना पड़ा। मास्क पहने यात्रियों ने बताया कि सभी की गहन जांच की गई। उनसे संक्रमण के बारे में सवाल पूछे गए।

पाक में महिला संरक्षण केंद्र भेजी गई नाबालिग हिंदू लड़की

▶ जबरन धर्मांतरण के बाद मुस्लिम से करा दिया गया था निकाह

▶ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जकोबाबाद जिले की है यह घटना

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का एक और मामला सामना आया है। 15 साल की एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर ना सिर्फ जबरन इस्लाम धर्म कुबूल कराया गया बल्कि एक मुस्लिम पुरुष से निकाह भी करा दिया गया। अदालत के आदेश पर अब लड़की को महिला संरक्षण केंद्र भेज दिया गया है।

यह घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जकोबाबाद जिले की है। नौवीं की छात्रा महक कुमारी को अली रजा नाम के एक व्यक्ति ने गत 15 जनवरी को अगवा कर लिया था। महक के पिता विजय कुमार ने एफआइआर में कहा था कि अली ने अगवा करने के बाद उनकी बेटी से जबरन निकाह कर लिया। जिले की एक अदालत में गुरुवार को महक और अली को पेश किया गया, जहां से महक को महिला पुलिस संरक्षण केंद्र भेज दिया गया। अदालत ने चंदका मेडिकल कॉलेज अस्पताल को महक की उम्र को लेकर तीन फरवरी तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, सिंध प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हरिराम किशोरी लाल ने महक के परिवार को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में नाबालिग हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण आम बात हो गई है। लाल ने अधिकारियों से हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय की रोकथाम और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण का शिकार हिंदू नाबालिग लड़की महक कुमारी। ट्विटर से

नाबालिग की नहीं हो सकती शादी : अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री लाल ने बताया कि पाकिस्तान के बाल विवाह रोधी कानून के तहत महक की 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं हो सकती। इस कानून के तहत महक की शादी एक अपराध है। उन्होंने कहा मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

न्यूज गैलरी

दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का
स्विट्जरलैंड ने मात्र 2.96 मिलीमीटर (करीब 0.12 इंच) का सोने का सिक्का जारी किया है। इस सिक्के का वजन 0.063 ग्राम है। इस पर प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जीभ बाहर निकाले हुए तस्वीर बनी हुई है। एपी

रोहिंग्या की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे म्यांमार

हेग : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में म्यांमार से रोहिंग्या आबादी को सुरक्षा देने के लिए कहा है। कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनका नरसंहार रोका जाए। न्यायालय ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि म्यांमार सरकार रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। पीठासीन न्यायाधीश अब्दुलकावी ने कहा- प्रत्येक चार महीने में सुरक्षा उपायों की न्यायालय को जानकारी दी जाए। (रायटर)

ताइवान के पास से गुजरे चीनी लड़ाकू विमान

ताइपे : ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को चीन के कई लड़ाकू विमान उसके दक्षिणी क्षेत्र के पास से गुजरे। चीन के एच-6 और केजे-500 बमबर्षक विमान बाशी चैनल के ऊपर से उड़ते हुए वापस चीन की ओर चले गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारा रक्षा तंत्र क्षेत्र के आसमान में हुई सारी हरकतों पर नजर रख रहा था। ताइवान में हाल ही में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने दोबारा जीत दर्ज की है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। (रायटर)

जर्मनी ने नाजी समर्थक संगठन पर लगाया प्रतिबंध

बर्लिन : जर्मनी की सरकार ने नाजी समर्थक दक्षिणपंथी संगठन कॉम्बैट 18 पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक ट्वीट में बताया गया कि हाल में एक स्थानीय और लोकप्रिय नेता वाल्टर ल्यूबेक की हत्या में शामिल रहे कॉम्बैट 18 पर गृह मंत्री हर्स्ट सीहोफर ने पाबंदी लगा दी है। (रायटर)

तुलसी गबार्ड ने हिलेरी पर किया मानहानि का मुकदमा

▶ पूर्व विदेश मंत्री ने अमेरिका की पहली हिंदू सांसद को रूस की पसंद कहा था

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर मानहानि का मुकदमा किया है। गबार्ड ने हिलेरी से उनकी छवि खराब करने के लिए पांच करोड डॉलर (करीब 350 करोड़ रुपये) के हर्जाने की मांग की है। डेमोक्रेट सांसद ने आरोप लगाया कि हिलेरी ने यह कहकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया कि वह 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस की पसंद हैं। अमेरिका में आगामी नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में गबार्ड विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवारी पाने की होड़ में शामिल हैं। हिलेरी 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थीं और उन्हें रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

मानहानि का यह मुकदमा बुधवार को न्यूयॉर्क की अदालत में दायर किया गया। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की सदस्य गबार्ड ने अपने समर्थकों से कहा, 'हिलेरी का मुझे रूसी संपत्ति कहने का इरादा मेरी छवि खराब करना और राष्ट्रपति पद के लिए मेरी मुहिम को पटरी से उतारना है।' 72 वर्षीय हिलेरी क्लिंटन ने गत अक्टूबर में एक इंटरव्यू में तुलसी गबार्ड का नाम लिए बिना कहा था, 'रिपब्लिकन पार्टी एक डेमोक्रेटिक दावेदार को तीसरे दल के उम्मीदवार के तौर पर तैयार कर रही है। वह रूसियों की पंसद है।'

अमेरिकी सीनेटर तुलसी गबार्ड और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन (दाएं)। फाइल/एपी

तुलसी-हिलेरी में मतभेद पुराना

38 साल की भारतवंशी सांसद तुलसी गबार्ड और हिलेरी क्लिंटन के बीच मतभेद नई बात नहीं है। 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में गबार्ड ने हिलेरी की जगह सीनेटर बर्नी सैंडर्स का समर्थन किया था।

ट्रंप को सीनेट में घेरने में जुटे विपक्षी डेमोक्रेट

▶ महाभियोग के दो आरोपों के अतिरिक्त चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप मढ़ा

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी संसद सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अस्वीकार करने की मांग के बीच डेमोक्रेट नेता एडम स्किफ ने जोरदार तर्कों के साथ अपनी बात रखी। सीनेट अपने इतिहास में तीसरी बार किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर बहस कर रहा है।

प्रतिनिधि सभा की नामित सांसदों की टीम के अगुआ स्किफ ने ट्रंप पर आरोपों को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश की। स्किफ ही वह वरिष्ठ सांसद हैं जिनके नेतृत्व में जांच दल ने डोनाल्ड ट्रंप पर निजी हित के लिए पद के दुरुपयोग और संसदीय जांच को बाधित करने के आरोप लगाए हैं। प्रतिनिधि सभा से आए विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने यह जानते हुए कि 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, बावजूद इसके उन्होंने ट्रंप के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। चुनावी साल में हो रही बहस और टीवी पर हो रहे इसके टेलीकास्ट ने उन्हें राष्ट्रपति पर हमला बोलने का बेहतर मौका दे दिया है। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के 53 जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 सांसद हैं।

स्किफ ने महाभियोग के दो आरोपों के अतिरिक्त ट्रंप पर 2016 का चुनाव जीतने में भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। कहा कि वह आने वाले चुनाव में भी वैसा ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा, वह जो बात कह रहे हैं-पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। स्किफ ने कहा वह शक्ति का दुरुपयोग करने वाले राष्ट्रपति हैं। इसीलिए 435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा ने बीती 18 दिसंबर को उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया।

यूक्रेन की चर्चित कंपनी का डाटा चुराने की कोशिश

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग प्रक्रिया के बीच रूसी सेना के हैकरों ने यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी से डाटा चुराने की कोशिश की है। यह वह कंपनी है जिसमें अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार जो बिडेन का बेटा हंटर निदेशक है। रूसी हैकरों की हरकत की जानकारी अमेरिकी साइबर सिक्युरिटी फर्म ने दी है। इसी बरिस्मा होल्डिंग्स लिमिटेड की जांच के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने जुलाई में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर फोन कर दबाव डाला था।

गर्भवती महिलाओं के वीजा पर पाबंदी लगाएगा ट्रंप प्रशासन

▶ अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए आने वाली महिलाओं को आसान नहीं होगा अब वीजा पाना

वाशिंगटन, एपी : ट्रंप प्रशासन वीजा पर और शिकंजा कसने जा रहा है। इस कदम के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं को वीजा देने पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आना चाहती हैं ताकि उनके बच्चे को अमेरिका का पासपोर्ट मिल जाए। विदेश विभाग के नए नियमों के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए पर्यटन वीजा पाना कठिन होगा। उनके साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया जाएगा, जैसा अमेरिका में उपचार कराने के लिए आने वाले विदेशियों के साथ होता है। आवेदकों को यह साबित करना होगा कि वे चिकित्सा उपचार के लिए आ रही हैं और खर्च का भुगतान करने के लिए उनके पास धनराशि है। अमेरिका में आकर शिशु को जन्म देना कानूनी तौर पर वैध है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सभी तरह के आव्रजन पर बंदिशें लगा रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर कड़ा रुख अपना रखा है। उनका इरादा गैर अमेरिकी नागरिकों के बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने के साथ यहां की मिलने वाली नागरिकता के अधिकार को खत्म करना है।

अमेरिका समेत दुनिया के कई दूसरे देशों में बर्थ टूरिज्म का कारोबार काफी तेजी से फल-फूल रहा है। अमेरिकी कंपनियां इसके लिए विज्ञापन देती हैं। वे होटल और चिकित्सा सुविधा के खर्च के तौर पर 80 हजार डॉलर (करीब 55 लाख रुपये) तक वसूलती हैं। रूस और चीन जैसे कई देशों से गर्भवती महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं। ट्रंप ने इस चलन पर भी सख्त रवैया अपना रखा है।

इस्माइल गनी को अमेरिका ने दी चेतावनी

▶ अमेरिकी लोगों को मारने के खिलाफ किया आगाह

▶ कहा-सुलेमानी की राह पर चले, तो उनके जैसा हाल होगा

दुबई, रायटर : अमेरिका ने कहा है कि यदि ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी ने अमेरिकी लोगों की हत्या जारी रखी, तो उनका भी वही हाल कर दिया जाएगा, जो उनके पूर्ववर्ती का हुआ था। वाशिंगटन सुलेमानी पर क्षेत्र के अमेरिकी बलों पर ईरान समर्थक मिलिशियाओं के जरिये हमले कराने का आरोप लगाता रहा है। पिछले साल दिसंबर में मिसाइल हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तीन जनवरी को सुलेमानी पर ड्रोन हमले का आदेश दिया था।

अमेरिका ने ठेकेदार पर हमले के लिए इराक में ईरान समर्थक मिलिशिया पर आरोप लगाया था। सुलेमानी की मौत से बिफरे ईरान ने आठ जनवरी को इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था। हालांकि, इसमें किसी अमेरिकी सैनिक की जान नहीं गई थी।

सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इस्माइल गनी को आनन-फानन में कुद्स फोर्स का नया प्रमुख बनाया है। गनी ने सुलेमानी के काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अमेरिका के विशेष दूत ब्रायन हुक ने अरबी भाषा के दैनिक समाचार पत्र अशरक अल-अवसत से कहा कि यदि गनी ने सुलेमानी के रास्ते पर चलना जारी रखा, तो उनका भी वैसा ही हाल कर दिया जाएगा। दावोस में दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका के लोगों या अमेरिकी हितों पर हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ईरानी शासन इस बात को अब समझने लगा है कि वह अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए वह इससे दूर ही रहेगा।

इस्माइल गनी। फाइल

इराक में बने रहेंगे सैनिक

दावोस, एएफपी : हालिया तनातनी के बावजूद इराक में हजारों अमेरिकी सैनिक आगे भी तैनात रहेंगे। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके इराकी समकक्ष बरहाम सालेह के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया कि इराक में सुरक्षा को लेकर अमेरिकी सहयोग पहले की तरह जारी रहेगा। ज्ञात हो कि बगदाद में अमेरिकी मिसाइल हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराकी संसद ने एक प्रस्ताव पास कर अमेरिकी सेना को देश से बाहर जाने को कहा था। फिलहाल इराक में करीब पांच हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों राष्ट्रप्रमुखों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) से लड़ाई के मुद्दे पर इराक को अमेरिकी मदद जारी रखी जाएगी। इसके अलावा इराक की संप्रभुता के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

भारतीय मूर्तिकारों ने बनाया बर्फ का शेषनाग

अमेरिकी प्रांत कोलोराडो के ब्रेकेनरिज में 30वी वार्षिक अंतरराष्ट्रीय स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप में 12 देशों के कलाकार बर्फ को तराशकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हिस्सा ले रही भारतीय टीम के कलाकारों ने शेषनाग की थीम पर कलाकृति तैयार की है, जिसे 'ट्राइंफ ओवर एविल' नाम दिया गया है। बर्फ की कलाकृतियों को दर्शक 24-29 जनवरी के बीच देख सकेंगे। एपी

ब्रेक्जिट के प्रस्ताव को महारानी ने दी औपचारिक स्वीकृति

▶ ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में आज होंगे समझौते पर दस्तखत

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन में गुरुवार को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय यूनियन (ईयू) छोड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दे दी। राजशाही के सम्मानार्थ सरकार ने यह प्रस्ताव महारानी के पास भेजा था।

ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी होने पर 31 जनवरी के बाद ब्रिटेन पड़ोसियों के साथ दशकों पुराने आर्थिक और व्यापारिक गठबंधनों से अलग हो जाएगा। यह प्रक्रिया करीब चार साल की खींचतान और तीन घोषित तारीखों के गुजर जाने के बाद पूरी होगी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के दो प्रमुख अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को इस सिलसिले में होने वाले समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे। बुधवार को संसद के दोनों सदनों से यूरोपीय यूनियन से होने वाले समझौते की स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, एक समय लगता था कि ब्रेक्जिट प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन हम ने इसे पूरा कर लिया। लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अब हमें सुनहरा और गर्मजोशी भरे भविष्य के निर्माण में जुटना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि यूरोपीय यूनियन छोड़ने में अब एक सप्ताह का समय बचा है। ज्यादा स्वतंत्र रूप पाने के बाद हम भविष्य की रूपरेखाओं पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों से अलग-अलग वार्ता करेंगे और बेहतर समझौते करेंगे। ब्रेक्जिट को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के लिए सबसे मुश्किल कार्य माना जा रहा था। इसके चलते प्रधानमंत्रियों (डेविड कैमरन और टेरीजा मे) को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन बोरिस जॉनसन ने आम चुनाव में जीत दर्ज कर इसकी राह आसान कर दी है।

आग बुझाने में जुटा कनाडाई विमान दुर्घटनाग्रस्त

मेलबर्न, रायटर: ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने में लगा एक कनाडाई सी-130 हरक्युलिस वाटर टैंकर विमान गुरुवार को अल्पाइन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार चालक दल के तीन अमेरिकी सदस्यों की मौत हो गई।

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत के रूरल फायर सर्विस कमिश्नर शेन फित्सीमोंस ने बताया कि इस विमान हादसे में कोई जीवित नहीं बचा। यह विमान कनाडा की हवाई अग्निशमन कंपनी कूल्सन एविएशन से लीज पर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया परिवहन सुरक्षा ब्यूरो के अनुसार, हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट आने में करीब 30 दिन का समय लग सकता है।

सी-130 हरक्युलिस विमान मूल रूप से सैनिकों और उनके साजो-सामान के परिवहन के लिए बनाया गया है। चार इंजन वाले इस अमेरिकी विमान को जंगलों की आग पर पानी की बौछार करने के काम में लगाया गया था।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटा सी-130 हरक्युलिस वाटर टैंकर विमान। फाइल/एएफपी

कैनबरा एयरपोर्ट बंद, लोग परेशान

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग राजधानी कैनबरा के एयरपोर्ट तक पहुंच गई है। इसके चलते गुरुवार को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गत सितंबर से आग लगी है। इसमें अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। ढाई हजार घर तबाह होने के साथ ही लाखों जानवर और जर्मनी के एक तिहाई भूभाग जितने इलाके के पेड़-पौधे इस आग की भेंट चढ़ गए हैं।

लंदन में उच्चायोग के सामने प्रदर्शन भारत ने ब्रिटेन के समक्ष उठाया मुद्दा

▶ विरोध प्रदर्शनों और गणतंत्र दिवस पर उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

नई दिल्ली, प्रेट्र : लंदन में अपने उच्चायोग के सामने कुछ पाकिस्तानी और खालिस्तान समर्थक समूहों के नियोजित प्रदर्शन के मद्देनजर भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने ब्रिटेन के सामने यह मुद्दा उठाया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे, जिससे कि किसी तरह की अप्रिय घटना न होने पाए।

भारत की उच्चायुक्त रूचि घनश्याम ने बुधवार को ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस और अन्य दिनों पर लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग इंडिया हाउस के सामने सुनियोजित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। उच्चायोग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तान समर्थक समूहों के विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछने पर कहा कि पहले भी प्रदर्शन के दौरान कुछ घटनाएं हुई हैं। भारत ने इस मुद्दे को बहुत की मजबूती के साथ ब्रिटेन के समक्ष उठाया है।

लंदन में भारतीय उच्चायोग। फाइल

उन्होंने कहा कि लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने एक बार फिर यह मसला ब्रिटेन के समक्ष उठाया है। हमने उन्हें अपने परिसरों, वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील किया है। उम्मीद है कि ब्रिटेन सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करेगा, ताकि पहले की तरह किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने पाए।

ये भी जानिए

न्यूजीलैंड ने पिछले पांच टी-20 मुकाबलों में से दो जीते व दो हारे हैं। उसका एक मुकाबला टाई रहा। वहीं, भारत ने अपने पिछले पांच टी-20 मैचों में चार जीते और एक हारा।

भारत के आज न्यूजीलैंड से तीन मुकाबले, इरादा सिर्फ जीत

भारतीय क्रिकेट के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। सुबह 3.30 बजे से लेकर रात आठ बजे तक भारत और न्यूजीलैंड की तीन अलग-अलग टीमें तीन अलग-अलग जगहों पर तीन मुकाबले खेलने उतरेंगी। जहां विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ऑकलैंड में पांच मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज करेगी तो उधर न्यूजीलैंड के ही एक अन्य शहर क्राइस्टचर्च में भारतीय-ए टीम न्यूजीलैंड-ए पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। वहीं, युवा अंडर-19 टीम दक्षिण अफ्रीका में चल रहे विश्व कप में न्यूजीलैंड पर जीत हासिल करके आत्मविश्वास के साथ क्वार्टर फाइनल मैच में उतरना चाहेगी।

लय बरकरार रखना चाहेगी अंडर-19 टीम

पोचेस्ट्रूम (दक्षिण अफ्रीका), प्रेट्र: लगातार दो जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी गत चैंपियन भारतीय टीम आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप-ए के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के सामने उतरेगी तो उसका लक्ष्य जीत की लय कायम रखने का होगा। चार अंक लेकर ग्रुप में शीर्ष पर चल रही भारतीय टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को 90 रन से हराने के बाद जापान को 10 विकेट से मात दी थी।

प्रियम गर्ग की अगुआई वाली टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को जापान से अंक बांटने पड़े क्योंकि मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। उसने श्रीलंका को हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। न्यूजीलैंड 2018 में अपनी मेजबानी में हुए अंडर-19 विश्व कप में आठवें स्थान पर रहा था। अब वह अपनी सीनियर टीम की तरह प्रदर्शन करना चाहेंगे जो 2019 पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। भारत के लिए पिछले मैच में लेग स्पिनर रवि विश्नोई ने चार, जबकि तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने तीन और आकाश सिंह ने दो विकेट लिए थे। चार बार की चैंपियन टीम ने जापान को 41 रन पर आउट कर दिया, जो अंडर-19 विश्व कप में दूसरा न्यूनतम और अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास में तीसरा न्यूनतम स्कोर था।

न्यूजीलैंड के खिलाफ आज पहला टी-20 खेलेगी कोहली सेना, विकेटकीपर के तौर पर केएल राहुल होंगे पहली पसंद

ऑकलैंड, प्रेट्र: टी-20 विश्व कप की तैयारियों को पुख्ता करने के लक्ष्य को लेकर विराट कोहली की अगुआई में टीम इंडिया यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में उतरेगी। न्यूजीलैंड की टीम खिलाड़ियों की चोटों से परेशान हैं, लेकिन मेहमान टीम के लिए यहां के विकेट बड़ी चुनौती साबित होंगे।

भारतीय टीम के अधिकतर विदेशी दौरों की तुलना में न्यूजीलैंड का दौरान हमेशा उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। पांच दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया कीवी दौरे का पहला मैच खेलने उतरेगी। टीम इंडिया मंगलवार को ऑकलैंड पहुंची और बुधवार को टीम ने आराम यि। उसने गुरुवार को अभ्यास किया। इसका हालांकि सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि इस कार्यक्रम से टीम प्रबंधन को चयन प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार के चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया को अपनी बैंच स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने का भी मौका मिलेगा। केएल राहुल ने शीर्ष क्रम पर उतरकर चोटिल धवन की कमी नहीं महसूस होने दी थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। इसके बाद जब रोहित शर्मा को आराम दिया गया तो उन्होंने धवन के साथ शानदार साझेदारी की। अब टी-20 सीरीज में एक बार फिर रोहित और राहुल ओपनिंग करते दिखेंगे।

कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में कहा था कि राहुल जिस तरह से विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे हैं उससे उन्हें काफी विकल्प मिले हैं। कोहली की मानें तो राहुल वनडे और टी-20 में विकेटकीपिंग करना जारी रखेंगे, लेकिन टी-20 में वह सलामी बल्लेबाज और वनडे में मध्य क्रम में उतरेंगे। ऐसे में पांच फरवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में पृथ्वी शॉ को ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर वनडे में पदार्पण करने का मौका मिल सकता है। कप्तान ने मध्य क्रम में भी बदलाव का संकेत देते हुए कहा था कि राहुल जब विकेटकीपिंग कर रहे हैं तो फिट हुए रिषभ पंत अंतिम-11 में अपना स्थान गंवा सकते हैं। मनीष पांडे के पांचवें विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेलने की संभावना है, तो वहीं श्रेयस अय्यर नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। अभ्यास के दौरान गुरुवार को पांडे, अय्यर और पंत ने एक साथ बल्लेबाजी की, जबकि संजू सैमसन भी मौजूद रहे, लेकिन उनके पहले टी-20 में खेलने की संभावना कम है। शिवम दुबे विकल्प बन सकते हैं। तेज गेंदबाजों में मुहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जबकि शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में से किसी एक को मौका मिलेगा।

न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को पिछली बार 2-1 से हराया था। श्रीलंका दौरे पर भी न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ घर में उन्होंने 2-2 से सीरीज बराबरी पर छोड़ी थी। सीमित ओवर प्रारूप में शानदार प्रदर्शन करने वाली न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराकर झकझोर दिया था। इससे कप्तान केन विलियमसन की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो गए थे। सीमित ओवर प्रारूप में अपने ऑलराउंडर पर ज्यादा भरोसा करने वाली मेजबान टीम को ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन की अनुपस्थिति में कुछ अच्छे तेज गेंदबाज खिलाने होंगे। यह भी देखना होगा कि ईडन पार्क की छोटी बाउंड्री को देखते हुए दोनों स्पिनर ईश सोढ़ी और मिशेल सेंटनर टीम में खेलते हैं या नहीं।

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान (बायें से) भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा ● ट्विटर

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित, केएल राहुल, मनीष पांडे, पंत, सैमसन, श्रेयस, शिवम, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, चहल, मुहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और वाशिंगटन सुंदर।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), गुप्टिल, टेलर, स्कॉट कुग्गेलिन, मुनरो, कोलिन डि ग्रैंडहोम, टॉम ब्रूस, डेरेल मिशेल, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट, हैमिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, ब्लेयर टिकनर।

बढ़त बनाने उतरेगी भारतीय-ए टीम

नई दिल्ली, जेएनएन: भारत-ए टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर पहले अनाधिकृत वनडे में न्यूजीलैंड-ए को पांच विकेट से हराया था। अब जब शुक्रवार को भारतीय टीम न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरे मैच में क्राइस्टचर्च में उतरेगी तो उसकी निगाहें तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होंगी।

पहले मुकाबले में भारत-ए की ओर से तेज गेंदबाज मुहम्मद सिराज ने तीन विकेट लिए। सीनियर टीम से जुड़ने की वजह से संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड-ए को 230 रनों पर ही पवेलियन भेज दिया था। जवाब में भारत-ए ने 39.3 ओवर में पांच विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया था। इस जीत में पृथ्वी शॉ ने 35 गेंद पर 48 और संजू सैमसन ने 21 गेंद पर 39 रनों की पारी खेली थी। संजू के टीम में नहीं रहने से दूसरे मुकाबले में सूर्यकुमार यादव से बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जिन्होंने पहले वनडे में 18 गेंद पर 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल पहले मुकाबले में नहीं चल पाए थे। शुभमन चाहेंगे कि वह इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलें।

12 टी-20 अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए हैं। भारत ने तीन और न्यूजीलैंड ने आठ में जीत दर्ज की है। एक मैच रद रहा

2016 जनवरी से न्यूजीलैंड ही एक अकेली टीम है जिसने भारत को तीन द्विपक्षीय टी-20 सीरीज में हराया है

07 टी-20 पारियों में भारत के खिलाफ मार्टिन गुप्टिल ने मात्र 108 रन बनाए हैं, इस बीच उनका औसत 15.43 और स्ट्राइक रेट 101.88 का रहा

07 पारियों में भारत के खिलाफ 11 विकेट लिए हैं लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने। ऑस्ट्रेलिया से हुई वनडे सीरीज में जांपा ने कोहली को आउट किया। कीवी टीम चाहेगी कि सोढ़ी को जल्द से जल्द गेंदबाजी कराएं। सोढ़ी ने कोहली और रोहित को एक-एक बार आउट किया है

2018 से नंबर पांच पर टी-20 में बल्लेबाजी कर रहे हैं रॉस टेलर। उन्होंने इस दौरान 119.40 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इस नंबर पर यह स्ट्राइक रेट बेहद कम है

उम्मीदों की थकान से दूर रहना होगा

गौतम गंभीर
फ्लिक

एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर मैंने दो तरह की विमान से हुई थकान वाली यात्राएं की हैं। कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाते वक्त पहली तो बेहद आम है और हम सब इसे जानते हैं। दूसरी मेरी खुद की खोज है और मैंने इसे उम्मीदें नाम दिया है।

इससे पहले कि मैं आपको उम्मीदों वाली विमान से हुई थकान वाली यात्रा के बारे में बताऊं, मैं आपको पहले एक कहानी के बारे में बता देता हूं। 2009 के समय जब हम न्यूजीलैंड का दौरा कर रहे थे तो हमारी टीम का एक साथी पेट की बीमारी से जूझ रहा था। वह टीम बैठक, टीम बस, डेसिंग रूम और यहां तक कि मैदान पर भी गंदी गैस छोड़ रहा था। मैंने इससे पहले इससे बुरा कुछ नहीं सूंघा था। कुछ दवाइयां दी गईं, सिरप दिए गए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। इस खिलाड़ी ने कंधा उठाते हुए कहा कि जेट लेग है यार, मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी टीम के एक साथी ने कहा कि मैंने नेपियर में 11 घंटे तक बल्लेबाजी की क्योंकि मैं डेसिंग रूम में बदबू के कारण नहीं लौटना चाहता था। मैं यह कहानी आपके निर्णय के लिए छोड़ देता हूं। उम्मीदों भरी थकान के बारे में अब बात करने का समय है जहां भारतीय टीम विदेशी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा थकान भरी कई घरेलू सीरीज के बाद कर रही है। सपाट पिचों पर बल्लेबाजी अच्छी थी। टी-20 में 180-200 के बीच रन बने, लेकिन न्यूजीलैंड दौरा जुदा होगा। यहां पर स्विंग, सीम और हवा होगी। बल्लेबाजों को उम्मीदों भरी थकान से जल्द बाहर निकलना होगा।

#WhatDrivesYou
EXIDE

वह दिन दूर नहीं, जब सीधे मैदान पर लैंडिंग करनी होगी : कोहली

ऑकलैंड, प्रेट्र : भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि क्रिकेटर अब उस स्थिति के करीब पहुंच रहे हैं जब स्टेडियम पर ही सीधे उतरकर खेलना शुरू करना होगा। भारत पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मैच में शुक्रवार को न्यूजीलैंड से खेलेगा। इससे पांच दिन पहले ही भारत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म हुई है।

कोहली ने पहले टी-20 से पूर्व कहा कि अब हम उस स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं कि सीधे स्टेडियम पर लैंडिंग करके खेलना होगा। कार्यक्रम इतना व्यस्त हो गया है, लेकिन इतनी यात्रा करके अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता। मुझे यकीन है कि भविष्य में इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ऐसा ही है, जहां लगातार खेलना होता है। कोहली ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज वनडे सीरीज थी तो हम मैदान पर काफी समय रहे। उससे पहले कुछ टी-20 खेले। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में क्रिकेटरों को दूसरे देशों की तरह सिर पर नहीं बिठाया जाता, लिहाजा यहां खेलना इत्मीनान से भरा होता है। न्यूजीलैंड दौरे पर राहत रहती है। हर दौरे पर इसकी बानगी मिलती है कि वहां क्रिकेट का क्या दर्जा है। यहां इसे काम की तरह लिया जाता है। यह जीवन का सबसे अहम पहलू नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यह कीवी संस्कृति का हिस्सा है और यह एक खेल ही है। उन्होंने हालांकि कहा कि लेकिन कीवी टीम भी हर मैच जीतने के इरादे से उतरती है। सब कुछ काफी संतुलित है और यहां खेलना बहुत अच्छा लगता है। कीवी खिलाड़ी काफी शांतचित्त और पेशेवर रहते हैं।

कोहली ने किया केन का समर्थन : कोहली ने न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का बचाव करते हुए कहा कि टीम के खराब प्रदर्शन करने पर सवाल हमेशा उठते हैं, लेकिन कप्तान का आकलन हमेशा नतीजों के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में न्यूजीलैंड की शर्मनाक हार के बाद विलियमसन की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं। न्यूजीलैंड को उस सीरीज में 0-3 से पराजय झेलनी पड़ी। ब्रैंडन मैकुलम ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि अब उन्हें कप्तानी में मजा नहीं आ रहा और उन्हें कम से कम टी-20 प्रारूप में कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तीनों प्रारूपों में भारत के कप्तान कोहली ने कहा कि कई बार लोग टीम की विफलता का ठीकरा तुरंत कप्तान पर फोड़ देते हैं। इस तरह की बातें अक्सर तब होती हैं, जब टीम खराब प्रदर्शन कर रही होती है। यह तीनों प्रारूपों में कप्तानी की जिम्मेदारी का हिस्सा है। मैं अपना फोकस इसी पर रखता हूं कि टीम के लिए क्या कर सकता हूं और उसे कैसे आगे ले जा सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि कप्तानी का आकलन हमेशा नतीजों से किया जा सकता है।

> कहा, कार्यक्रम इतना व्यस्त हो गया है, लेकिन इतनी यात्रा कर अलग टाइम जोन वाले देश में आकर तुरंत ढलना आसान नहीं होता

मैं आखिरी दहाड़ के लिए तैयार : पेस

साक्षात्कार

कहते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। लिएंडर पेस की उम्र यूं तो 46 के पार जा चुकी है लेकिन उनके अंदर अभी भी खेल का जो जज्बा है, उसके सामने 22 साल के एथलीट भी पानी भरते हैं। अपने करियर के अंतिम साल में प्रवेश कर चुके पेस पांच अलग-अलग दशक में खेलने के बेहद करीब हैं। एक खेल भरे माहौल में पैदा हुए पेस की फिटनेस उनके करियर में अहम हिस्सा रही लेकिन इसमें कई लोगों की मेहनत रही। 18 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन और देश के इकलौते व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता टेनिस खिलाड़ी पेस इस साल संन्यास ले लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आखिरी बार खेलने के लिए मेलबर्न जाने से पहले **लिएंडर पेस** से **अभिषेक त्रिपाठी** ने उनके करियर और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पेश है उस बातचीत के प्रमुख अंश-

संन्यास के बाद बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली की तरह टेनिस संघ में भी भूमिका तलाश सकते हैं लिएंडर। द्रविड़ और गांगुली की तरह देश में खेल के विकास को लेकर कुछ करना चाहते हैं। भारत को एक खेल प्रधान देश बनते देखना चाहते हैं पेस

- **आप इस साल संन्यास लेंगे। आप आखिरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने जा रहे हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है? आप कैसे टेनिस कोर्ट को अलविदा कहना चाहेंगे?**

-ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह रही है जहां मैंने अपना पहला ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट खेला था। 1989 में मैंने अपना पहला ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेला था। तब से लेकर आज तक मैं पांच अलग-अलग दशकों में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने के बेहद करीब हूं। यह पल मेरे लिए बेहद खास है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा से मेरे लिए खास रहा है और इस बार जब मैं वहां खेलने उतरूंगा तो उस खास अहसास का अनुभव करूंगा।

- **आपने डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में कुल 18 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। आप डेविस कप में डबल्स के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। आपके नाम ओलंपिक पदक भी दर्ज है। अब कोई ऐसी चाहत है जो आप अपने करियर के अंतिम वर्ष में हासिल करना चाहते हैं?**

-जब भी मैं टेनिस कोर्ट में कदम रखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार और अपने देश भारत के लिए खेल रहा हूं। मैं जब भी कोर्ट पर उतरता हूं तो मैं खुद को गौरवान्वित करने के लिए खेलता हूं। तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक देश के लिए खेलना मेरे लिए बहुत खास है और इस आखिरी साल को मैं एक आखिरी दहाड़ के रूप में मानता हूं। मेरे टेनिस करियर का यह आखिरी साल है और मैं इस पूरे सत्र को वन लास्ट रोर (एक आखिरी दहाड़) का नाम दूंगा। मैं सही मायने में मेरे उन समर्थकों के साथ जश्न मनाना चाहता हूं जिन्होंने अब तक मेरे करियर में मेरी जीत और हार में मेरा साथ दिया है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं।

- **आज भी आपको एक 46 साल का लड़का माना जाता है। ऐसी क्या खास वजह है कि आप संन्यास के आखिरी साल में भी युवा टेनिस स्टारों को टक्कर देते हैं?**

-मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसे माता-पिता मिले। उन्होंने जैसे अनुवांशिक गुण (जींस) मुझे दिए और जैसा माहौल घर में दिया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हालांकि मुझे लगता कि पिछले 30 वर्षों में मुझे फिट रखने में कई लोगों की अहम भूमिका रही है। मेरे कोच रिक लीच व बॉब, मेरे फिटनेस ट्रेनर डेव हर्मन व वैभव डागा, मेरे साथ यात्रा करने वाले व मेरे योगा मास्टर संजय सिंह, मेरे पिता डॉक्टर पेस जो कि मेरे डॉक्टर भी हैं और मेरा प्रबंधन करने वाली मेरी टीम। ये सभी करीब 25-30 वर्षों से मेरे साथ रहे हैं और इन सभी ने मेरे करियर में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इन सभी की वजह से ही आज मैं इतने सारे खिताब जीत पाया और इसलिए इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।

- **संन्यास के बाद आपकी क्या योजना है। क्या आप कोचिंग देंगे या फिर प्रबंधन से जुड़ेंगे या कमेंट्री में हाथ आजमाएंगे या फिर एक फैमली मैन बनेंगे?**

-संन्यास के बाद मेरी कुछ योजनाएं हैं। अभी मैं कई कॉर्पोरेट सेक्टर में मनोबल बढ़ाने के लिए भाषण दे रहा हूं। स्वस्थ्य, फिटनेस, आहार और जीवन के तौर तरीकों को लेकर मैं काफी काम कर रहा हूं। मैं लोगों को उस अनुभव के बारे में बता रहा हूं जो मैंने पिछले 30 वर्षों में दुनियाभर में भ्रमण करते हुए हासिल किया ताकि वे भी चैंपियन बन सकें। मेरी योजना बच्चों को खेलों के जरिये सही शिक्षा देने की भी है। खेल शिक्षा मेरे लिए काफी अहम है जो एक आम बच्चे के जीवन को बदल सकता है। आप एक बच्चे के जीवन को स्कॉलरशिप देकर या फिर उसे शारीरिक रूप से सक्रिय बनाकर मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि खेल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप कई समुदायों को एक जगह ला सकते हैं। मेरा सपना है कि मैं भारत को एक खेल प्रधान देश के रूप में विकसित होता देखूं। मुझे लगता है कि भारत में ज्यादा बौद्धिक रूप से दक्ष, व्यावसायिक, चिकित्सीय रूप से दक्ष लोग हैं लेकिन हमारे पास खेलों में एक स्वस्थ्य समुदाय तैयार करने का अच्छा मौका है।

> **कोई दो राय नहीं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता पर मौजूदा समय में वह कौन है जो आपकी कमी को पूरा कर सकता है?**
> -देखिए मुझे लगता है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि चाहे मेरे डेविस कप में सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड हो या ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने का रिकॉर्ड या फिर मेरे इतने लंबे समय तक खेलने का रिकॉर्ड हो, मुझे लगता है कि एक दिन ये सारे रिकॉर्ड कोई ना कोई भारतीय टेनिस खिलाड़ी तोड़ देगा। यह इसलिए क्योंकि हम लगातार बेहतर हो रहे हैं।

लिएंडर पेस ● फाइल फोटो, ट्विटर

- **देश में मौजूदा समय में टेनिस के भविष्य को आप कैसे देखते हैं ?**

-मुझे लगता है कि देश में टेनिस का भविष्य उज्जवल है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो भी देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं, उन्हें टेनिस को बढ़ावा देने के लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ ने संन्यास के बाद भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को कोचिंग देकर विश्व चैंपियन बनाया। यह शानदार है। 1991 में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेरे साथ अभ्यास करने वाले सौरव गांगुली ना सिर्फ भारत के बेहतरीन कप्तान हुए बल्कि अब बीसीसीआइ के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं। वह अब प्रबंधन में आकर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसी तरह अगर आप पुलेला गोपीचंद को देखें तो उन्होंने ना सिर्फ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीता बल्कि साइना नेहवाल और पीवी सिंधू जैसे ओलंपिक पदक विजेता भी तैयार किए। ये वैसे लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि ये लोग वापस खेल समुदाय में लौटे और अपने अनुभव और ज्ञान के दम पर बदलाव लाने में सफल रहे।

- **क्या आप भारतीय टेनिस के अगले सौरव गांगुली होंगे?**

-अभी मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए संभावनाएं हैं और अपने करियर के अंतिम साल में मैं तमाम संभावनाओं पर विचार करूंगा और इसके बाद तय करूंगा कि संन्यास के बाद कौन सी वह सबसे सही चीज है जो की जा सकती है।

- **इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं?**

-मैं अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी भी ओलंपिक बहुत दूर है। मुझे लगता है कि ओलंपिक के लिए चयन और तैयारियां अभी काफी दूर हैं।

AO सुबह 5:30 बजे से
सोनी सिक्स व सोनी टेन-2

नडाल और किर्गियोस जीते

ऑस्ट्रेलियन ओपन

- **विश्व के नंबर एक खिलाड़ी राफेल ने दूसरे दौर में डेलबोनिस को सीधे सेटों में हराया**
- **ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक ने चार सेट में फ्रांस के जाइल्स सिमोन को हराया**

मेलबर्न, एएफपी: विश्व के नंबर एक खिलाड़ी राफेल नडाल और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस ने अपने-अपने मुकाबलों में आसानी से जीत के साथ गुरुवार को यहां ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बनाई।

रोड लेवर एरिना में शीर्ष वरीय नडाल को अर्जेंटीना के फेडेरिको डेलबोनिस के खिलाफ सीधे सेटों में 6-3, 7-6, 6-1 की जीत के दौरान अधिक पसीना नहीं बहाना पड़ा। स्पेन के खिलाड़ी नडाल अगले दौर में हमवतन पाब्लो केरेनो बुस्ता से भिड़ेंगे, जिनके साथ इस महीने एटीपी कप में उन्होंने डबल्स जोड़ी बनाई थी। नडाल ने कहा, 'यह मुश्किल मैच था। मैंने ब्रेक प्वाइंट पर कई मौके गंवा दिए, लेकिन दूसरा सेट जीतने में सफल रहा। तीसरे सेट में मैं अधिक शांत, अधिक आक्रामक था और बेहतर तरीके से खेल पाया।' विश्व के 76वें रैंकिंग के खिलाड़ी डेलबोनिस पर पिछले तीन मैचों में जीत दर्ज कर चुके हैं और उनके खिलाफ केवल 10 गेम ही हारे हैं। अर्जेंटीना के खिलाड़ी का मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 में रहा था जहां वह तीसरे दौर से ही बार हो गए थे।

नडाल का बॉल किड्स से प्यार : मैच खत्म होने के बाद नडाल इतने खुश थे कि वह कोर्ट पर मौजूद एक बॉल किड्स के पास गए और उन्होंने अपने माथे पर बंधी एक पट्टी को उतारकर उसे दे दिया। वह मैच खेलते समय उस पट्टी को बांधकर खेलते हैं। इस दौरान वह बॉल किड्स से बात करते रहे और उसे किस भी किया। इस पर नडाल ने कहा, 'उसके लिए यह एक अच्छा पल नहीं था। मैं उसके लिए बहुत डरा हुआ था और गेंद बहुत तेज थी और उसके पास चली गई। मैं खुश हूं कि वह ठीक है। वह बहादुर है।'

अन्य मुकाबलों में जंगलों में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए धनराशि जुटाने के प्रयास में अहम भूमिका निभाने के कारण लोकप्रिय हुए किर्गियोस ने चार सेट में फ्रांस के जाइल्स सिमोन को 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 से हराया। वहीं, जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फॉर्म में वापसी का संकेत देते हुए इगोर गेरासिमोव को 7-6, 6-4, 7-5 से हराया। पांचवीं वरीय डोमिनिक थिएम को हालांकि ऑस्ट्रेलिया के 140वें नंबर के खिलाड़ी एलेक्स बोल्ट के खिलाफ पांच सेट तक जूझना पड़ा। थिएम ने हालांकि धैर्य बरकरार रखते हुए 6-2, 5-7, 6-7, 6-1, 6-2 से जीत दर्ज की।

फिर मौसम का खलल: टूर्नामेंट में प्रदूषित वर्षा के रूप में नई चुनौती आई, जिससे कोर्ट कीचड़ के कारण खेलने योग्य नहीं रहे। इस साल टूर्नामेंट को जंगलों की आग के कारण फैले धुएं और राख, तेज बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा है। इससे पहले धूल-मिट्टी वाली बारिश के कारण मेलबर्न पार्क के कोर्ट पर कीचड़ की परत जम गई जिसे साफ करने में कई घंटे लग गए और कई बाहरी कोर्ट उपयोग में नहीं लाए जा सके।

चोट के कारण सानिया ने बीच में छोड़ा मैच, टूर्नामेंट से बाहर

मेलबर्न, प्रेट्र: मातृत्व अवकाश के बाद टेनिस कोर्ट पर लौटीं भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा पहले ग्रैंडस्लैम के शुरुआती दौर से ही बाहर हो गईं, जब चोट के कारण महिला डबल्स के पहले दौर का मैच उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा। सानिया और यूक्रेन की नादिया किचनोक ने पिछले सप्ताह ही होबार्ट अंतरराष्ट्रीय डबल्स खिताब जीता था। दोनों चीन की शिंयुआन हान और लिन झू से 2-6, 0-1 से पीछे चल रही थीं, जब सानिया ने कोर्ट छोड़ा। अभ्यास के दौरान सानिया के दायें पैर में चोट लगी। वह दो साल बाद टेनिस कोर्ट पर लौटी हैं। सानिया और किचनोक 2-4 से पीछे चल रही थीं, जब चीनी टीम ने सानिया की सर्विस तोड़ी और सेट जीत लिया। सानिया को पहले सेट के बाद मेडिकल टाइमआउट लेना पड़ा। दूसरे सेट के पहले ही गेम में उनकी सर्विस टूटी और वह आगे खेल नहीं सकीं। उन्हें मिक्स्ड डबल्स से भी नाम वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्हें रोहन बोपन्ना के साथ खेलना था। साइना के हटने के बाद अब बोपन्ना मिक्स्ड डबल्स में किचनोक के साथ जोड़ी बनाकर उतरेंगे। लिएंडर पेस भी मिक्स्ड डबल्स में भारत की चुनौती पेश करेंगे, जो 2017 फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको के साथ खेलेंगे। उन्हें शनिवार को पहले दौर में स्थानीय वाइल्ड कार्डधारी स्टोर्म सैंडर्स और मार्क पोलमैंस से खेलना है।

दैनिक जागरण
सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जनवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

परमजीत कौर धनोआ (लाहौर से पटियाला), व उषा भारद्वाज.... (लाहौर से दिल्ली)

उषा छाबड़ा (रावलपिंडी से दिल्ली)

सभी फोटो : जागरण

बंटवारें का दंश, प्रदर्शनी

एक हाथ संभाला तो दो छूट गए थे

ये उस वक्त की बात है जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बदहवास था हर शख्स। कोई खैर खबर न थी...सिर्फ अपनों की आस और तलाश थी। भटक रहे थे सब दर बदर। कैसा था वो मंजर... कैसा था वो बंटवारे का दंश...झेला जो इन लेजेंट महिलाओं ने। एक हाथ संभालते तो दो छूट जाते ऐसे हालात थे। कोई रंग नहीं दिखेगा इस मेट्रो स्टेशन पर लगी इस प्रदर्शनी में...सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जिंदगी दिखेगी...उनकीजुबानी वही रूह कंपा देने वाली कहानी दिखेगी, जिससे सबरंग के इस अंक में रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

मामूना मुस्तन्सर

पूरनचंद, अपनी पत्नी के साथ...गाजियाबाद में दो साल तक रहे थे

शोरगुल बहुत था शहर में...चरम पर अराजकता थी। जल रहा था हर कोई विभाजन की आग में। बात है सन् 1947 की। याद है हर मंजर उस दौर का। सिहर उठे थे मेरे पड़ोसी..कि यात्रा के दौरान उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है और सोचो कैसे कुछ गलत होने के भय ने मां-बाप को विवश कर दिया बेटी की सांसों को वहीं थाम दिया...नरिंदर कौर ओबराय की यह आपबीती हर पढ़ने वाले को झकझोर कर रख देती है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर नरिंदर कौर की तरह कई ऐसे महिला-पुरुषों की आपबीती प्रदर्शित की गई है जो 1947 में हुए बंटवारे की विभीषिका बयां करती है। महिलाओं की कहानियां गलियारे से गुजरते हर यात्री के कदमों को थाम लेती है। उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे लोगों ने उस दर्द को झेला होगा। कैसे मानवता शर्मसार हुई थी।

हर कहानी पढ़ सिहर जाएंगे : प्रदर्शनी में गोपी भाटिया की चित्र प्रदर्शनी भावुक कर देती है। गोपी कराची-सिंध से बाम्बे (अब मुंबई) का सफर तय किया। उनकी आपबीती यहां कुछ इस तरह दर्ज है 'बंटवारे के बाद हम कराची में ही रहा करते थे। 1948 की शुरुआत में धीरे-धीरे हमारे शहर में भी दंगे शुरू हुए। मेरे माता-पिता ने यहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा था। हमने दंगे खत्म होने का इंतजार करने का निर्णय लिया। हालात बिगड़ते देख मेरे पिताजी ने हमें किसी तरह बाम्बे में एक रिश्तेदार के यहां छोड़ा और खुद कराची लौट गए। यह कहकर कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक महीने तक उनकी खबर नहीं मिली। फिर एक दिन बाद अचानक वो वापस लौट आए और तब यह बात साफ हो गई कि अब वापस लौटने का कोई प्रयोजन नहीं है।'

बंटवारे का दर्द: परमजीत कौर धनोआ (लाहौर से पटियाला) 'विभाजन के समय मैं मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल में थी और हॉस्टल में रहती थी। हर तरफ दंगे फैल चुके थे। हमारा कॉलेज अनारकली बाजार के बीचो बीच था। हमनें लोगों को एक महीने तक मरते देखा, मदद मांगते हुए और रोते हुए देखा। वो दृश्य बहुत ही भयावह था। अगस्त में विभाजन की घोषणा के बाद मैंने कुछ दोस्तों के साथ विस्थापित होने का निर्णय किया। हम एक ट्रक पर सवार हुए जो अमृतसर जा रहा था, पूरा ट्रक भरा हुआ था। मैं किसी तरह अमृतसर आई और वहां से लुधियाना पहुंची, पर अपने परिवार को ढूंढने में असफल रही। तीन दिनों तक एक ट्रेन पर होने के बाद आखिरकार मैं जालंधर कंटोनेंट पहुंची और हजारों की भीड़ में किसी तरह अपने परिवार को ढूंढ पाई।'

शहर जल रहा था: उषा भारद्वाज (लाहौर से दिल्ली) 'मैं अपनी छुट्टियां बिताने कश्मीर गई हुई थी जब बंटवारे की घोषणा हुई। जैसे तैसे मैं हवाई जहाज पकड़ लाहौर रुकी और परिवार से मिली। वो शहर जिसे मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी आंखों के सामने दंगों से तहस नहस हो गया। मेरे भाई और बहन दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दंगों के बीच में प्लेटफार्म पर खड़े हमारे साथ के एक मुसाफिर हिंसक हो गए, तब मेरे पिताजी ने उन्हें शांत कराया। परिवार को वहां से निकालने की हड़बड़ाहट में मेरा भाई स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही छूटते-छूटते बचा। हमने यात्रा के दौरान बहुत सी दर्दनाक घटनाएं देखीं, जिन्हें भूल नहीं सकते।'

बच्चों को पढ़ाकर सुकून मिलता: उषा छाबड़ा (रावलपिंडी से दिल्ली) 'शुरुआत में मैं और मेरे भाई बहन अपनी चाची के पास गोयल बाजार में रहे। जब तक हमारे माता-पिता को ढूंढा ना गया। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। यहां मिंटो रोड पर एक तीन कमरे वाले मकान में कुछ रिश्तेदारों के साथ ठहरे। मैंने अपनी पढ़ाई 1948 में फिर से शुरू की और साथ ही साथ मिंटो रोड करोल बाग में समाजसेवा भी शुरू की। मेरी ज्यादातर सेवाएं शरणार्थियों के बच्चों को पढ़ाने की होती थी।

जिंदगी की जद्दोजहद: पूरनचंद, मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई और पिताजी गाजियाबाद से दिल्ली कपड़े बेचने के लिए जाया करते थे। मेरा परिवार गाजियाबाद में 2 साल तक रहा। तब हमें राजेंद्र नगर में यालपुर की संपत्ति के बदले में एक मकान मिला था। वह एक शरणार्थियों की कॉलोनी थी। हमारा घर 2 कमरों वाला छोटा मकान था। यहां मौजूद सभी शरणार्थियों की कहानी एक जैसी थी। सबने अपना घर पीछे छोड़ दिया था, जो कि पाकिस्तान बन गया था और यहां नई जगह बसने का प्रयास कर रहे थे। हमें बिजली नहीं मिल रही थी, पानी भी नहीं था। हमनें बहुत संघर्ष किया था।'

ऐसे बंटोरी कहानियां

1947 विभाजन के अभिलेखागार की संस्थापक गुनीता सिंह भल्ला कहती हैं कि प्रदर्शनी का डिजाइन वास्तुकार अर्घो ज्योति ने तैयार किया गया है। 'यह पहली बार है जब मेट्रो में इसका प्रदर्शन किया है, और मेट्रो स्टेशन पर इस काम को प्रदर्शित करने में बहुत बड़ा प्रतीक वाद है क्योंकि 1947 में सीमा पार करने के लिए लाखों लोग ट्रेनों पर निर्भर थे। कई लोग ट्रेनों में खो गए थे। सन् 2009 में पंजाब यात्रा के साथ विभाजन के मौखिक इतिहास का रिकार्ड संग्रहित शुरू किया। अब तक, आर्काइव ने 12 देशों की 36 भाषाओं में 8,000 कहानियों को रिकॉर्ड किया गया है।

आयोजन : विभाजन के दौरान महिलाएं
कहां : मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन
कब : 31 जनवरी तक, रात के 11 बजे तक।
प्रवेश : मेट्रो टोकन से।

इस बार यहां चलें

एक रहस्यमय ताकत

संवाद करना मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ऐसी चीज से संवाद करना जिसके पास जुबान ही न हो वो पागलपन नहीं कला कही जाएगी। जिसे वैज्ञानिकों ने एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का नाम दिया है। इस कला को चिकित्सा के एक सशक्त माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है।
- **कहां** : विजुअल आर्ट गैलरी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड।
- **कब** : 1 फरवरी तक, सुबह दस से शाम छह बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

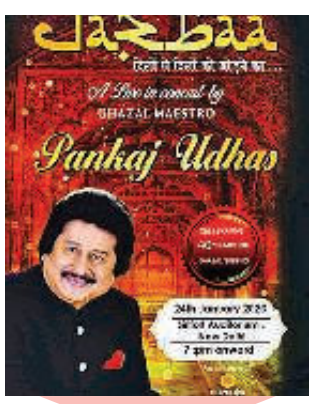

जज्बा

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस मधुर संगीत से सजी शाम में गायक पंकज उधास अपनी मीठी आवाज में प्रसिद्ध गजल चिट्ठी आई है, इक तरफ उसका घर, जैसी गजलों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। अगर आप भी इस मौसीकी का लाइव लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कार्यक्रम में जरूर जाएं।
- **कहां** : सिरीफोर्ट आडिटोरियम।
- **कब** : 24 जनवरी, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : आनलाइन बुकिंग द्वारा।

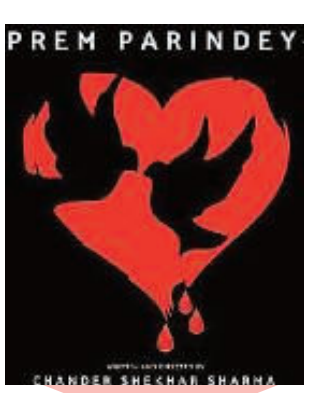

प्रेम परिंदे

एक युवा प्रेमी जोड़े के इर्द-गिर्द घूमता यह नाटक, जिसमें प्रेमी जोड़े एक-दूसरे से बिना शर्त प्यार करते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं। किस्मत पांच साल बाद उन्हे फिर से साथ लाती है।
- **कहां** : स्टूडियो सफदर, ग्राउंड फ्लोर, न्यू रंजीत नगर।
- **कब** : 25 जनवरी, शाम 6.30 एवं 7.55 बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

मोहिनीअट्टम

यदि सप्ताहांत नृत्य संगीत से सजी शाम में बिताना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में जरूर जाएं। जहां वाणी भल्ला पहवा अपने गुरु पद्मश्री भारती शिवाजी द्वारा कोरियोग्राफ की गई कुछ आत्मीय रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत करेंगी। संस्कृति के विविध पक्ष देखने का अवसर मिलेगा।
- **कहां** : सीडी देशमुख आडिटोरियम, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर।
- **कब** : 30 जनवरी, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

दिल्ली से दिल का रिश्ता : स्मिता बंसल

स्मिता बंसल...कई टीवी सीरियल के जरिए दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। और अब सीरियल्स में कामयाब पारी खेलने के बाद नाटक 'हैलो जिंदगी' से पहली बार स्क्रिप्ट राइटिंग में हाथ आजमा रही हैं। नाटक का नाम ही कहता है कि इसका ताना बाना जिंदगी के इर्दगिर्द घूमता है...जिसे पांच महिलाओं की कहानी के माध्यम से रचा गया है। कमानी आडिटोरियम में इसका नाटक का मंचन होगा। नाटक समेत दिल्ली से जुड़ी यादों पर स्मिता बंसल से संजीव कुमार मिश्र ने बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

26 जनवरी को कमानी आडिटोरियम में हैलो जिंदगी नाटक का मंचन होगा

- **अचानक टीवी सीरियल्स से स्क्रिप्ट राइटिंग? आखिर कहानी लिखने का आइडिया कहां से आया।**

फिलहाल मैंने एक्टिंग से ब्रेक लिया हुआ है। दिमाग में कहानियां तो कई थीं लेकिन कभी लिख नहीं पाई। मेरी बेटी छोटी है। उसे स्कूल छोड़ते वक्त वहां बाकि बच्चों की मां से बात होती थी। अधिकतर मां की यही कहानी थी कि कभी वो प्रोफेशनल थीं और बेहतरीन करियर था लेकिन फिर पारिवारिक उलझनों में उलझ गईं। इन्हीं मांओं की कहानी को मैंने केंद्र में रखते हुए लिखा। खासकर दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम महिलाएं ऐसी ही जिंदगी जीती हुई दिख जाएंगी। जब कई कहानियां मिलीं तो लगा कि नाटक का तानाबाना बुना जा सकता है। यह 30-35 वर्ष पार कर चुकी महिलाओं की कहानी है।

- **खुद अभिनेत्री हैं लेकिन नाटक में खुद अभिनय नहीं किया?**

(हंसते हुए) दरअसल, मैं अपनी कहानी को स्टेज पर मंचित होते देखना चाहती थी। मैंने स्टेज पर बहुत परफार्म किया है। अब दर्शकों के बीच रहकर अपने नाटक पर उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। जब दर्शक आपके द्वारा लिखे गए किरदारों पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो शानदार लम्हा होता है।

- **दिल्ली से आपका काफी पुराना नाता है?**

मेरे पिता का जयपुर में कारोबार है। लेकिन एक्सपोर्ट के सिलसिले में वो दिल्ली आए, यह वर्ष 1991-92 की बात होगी। हम ट्रांस यमुना में पटपड़गंज में रहते थे। उन दिनों नए-नए अपार्टमेंट बन रहे थे। पूरे सप्ताह रविवार का ही इंतजार करते थे। पिता जी की छुट्टी होती थी। हम सब घूमने जाते थे। ट्रांस यमुना में उस समय बहुत सुविधाएं नहीं थी, लिहाजा कहीं आने जाने के लिए कुछ दिन पहले से प्लानिंग करनी पड़ती थी। अब अधिकतर काम के सिलसिले में दिल्ली आना जाना होता है। तब की दिल्ली और अब की दिल्ली में जमीन आसमान का अंतर भरी है। अब तो दिल्ली बहुत बदल गई है। फ्लाईओवर और मेट्रो का जाल बिछ गया है।

- **स्कूली दिनों की किस तरह की यादें हैं?** सुना है पहली बार फिल्म आपने भागकर देखी थी? स्कूली दिनों की यादें तो आज भी गुदगुदाती हैं। ट्रांस यमुना में सुविधाएं थी नहीं, इसलिए जब बारिश होती थी तो पानी भर जाता था। आप ये सुनकर हंसेंगे कि उस समय हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि खूब बारिश हो, पानी भर जाए। ताकि हमें स्कूल न जाना पड़े। और यदि स्कूल में होते हुए बारिश हो जाए तो सभी बच्चों को हॉल में बैठाया जाता था। जहां सब मिलकर अंताक्षरी खेलते थे। एक सहेली के साथ पहली बार दिल्ली में क्लास बंक कर मैंने हम आपके हैं कौन फिल्म देखी थी। हालांकि बाद में हम पकड़े गए थे और घर पर खूब डांट पड़ी थी।

- **आप अपनी बेटी के साथ दिल्ली आई हैं। कहीं घूमने का प्लान है?**

मैं उन्हें निरूला लेकर जाना चाहूंगी। मुझे वहां की चाट, दही भल्ले, छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। उसके बाद अक्षरधाम भी जाएंगे। मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी भी दिल्ली घूमे और इसकी खासियत से रूबरू हो।

कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी स्मिता बंसल ने हैलो जिंदगी की स्क्रिप्ट राइटिंग की है
सौजन्य : आयोजक

बंटवारें का दंश, प्रदर्शनी

कश्मीरी पंडित फेस्ट में खास है करी मछली

खुश किस्मत है कश्मीर, धरा का स्वर्ग यहीं जो दिखता है...सिर्फ खूबसूरती की चादर में नहीं लिपटा है बल्कि मसालों की मिसाल भी कश्मीर बनता है। बेवरेजेज से लेकर साग और डेजर्ट्स तक के स्वाद व प्रजेंटेशन में कश्मीरी सौंदर्य का नायाब नमूना है। भोजन की यही महक और खूबसूरती आपको एरोसिटी के होटल नवोटल में 'होमशेफ सीजन थ्री कश्मीरी पंडित क्यूजीन' में मिलेगी। पढ़कर ही उसकी लजीजियत का एहसास होने लगा न? सात दिवसीय इस आयोजन में शेफ बेहतरीन डिशेज को शोकेस कर रहे हैं।

आसां नहीं कश्मीरी क्यूजीन का सफर : कश्मीरी भोजन ऐसे ही नहीं स्वाद और सौंदर्य का प्रतीक बना है। इस भोजन ने एक यात्रा को पूरा किया है जिसमें इसका धीरे-धीरे उद्भव हुआ है। इस भोजन के विकास के इतिहास को बताने के लिए शेफ झिंसी ने इस आयोजन का भ्रमण किया और उन्होंने बताया कि आज कश्मीरी मसालों और वहां की माटी की सुगंध जो जायकों में हैं वह पीढ़ियों की मेहनत की खुशबू है जो आज जाकर इस कश्मीरी पंडित जायके को सुगंधित कर रही है।

कश्मीरी पंडितों का मांसाहारी जायका: कश्मीरी पंडित देश के ऐसे कुछ ब्राह्मण समुदायों में से हैं जो कि मांसाहारी हैं लेकिन लहसुन, प्याज, टमाटर तथा अंडे जैसी चीजों का कम प्रयोग करते हैं। बगैर लहसुन-प्याज के ही मांसाहारी डिश भी बनाते हैं। इसके बदले मसालों और दही से स्वाद में इजाफा करते हैं। इस फूड फेस्टिवल में कश्मीरी क्यूजीन में मटन और फिश को प्रमुखता दी गई है। एरोसिटी में प्रदर्शित डिशेज में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हाक का साग बनाया जा रहा है। यह पालक और सरसों के साग की तरह ही दिखता है। इसके अलावा यहां पर आपको मछली की डिशेज का जायका मिलेगा। रानी झिंसी के मुताबिक कश्मीरी पंडित मछली के शौकीन हैं और ऐसे में वे विभिन्न प्रकार की मछलियों की अलग-अलग डिशेज बनाते हैं। इसमें मछली को पैन फाई करने से लेकर उसे ग्रिल करके और करी के साथ भी मछली की डिशेज बनती है। इन सभी प्रकार की मछली की डिशेज को नवोटल फूड एक्सचेंज के कश्मीरी विशेष लंच और डिनर में रखा जा रहा है। कश्मीरी पंडित स्टाइल चमन पकौड़ा मूलतः पनीर पकौड़ा होता है जिससे कि कश्मीरी मसालों की खुशबू और स्वाद से सजाया जाता है।

मटन से लेकर पालक मेथी तक का स्वाद: होम शेफ सीजन थ्री में कश्मीरी पंडित विशेष जायके में केवल मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि शाकाहारी क्यूजीन को भी शामिल किया गया है। आपने दम आलू खाया होगा लेकिन कश्मीरी दम आलू का स्वाद और प्रजेंटेशन देखकर आप पहले का स्वाद भूल जाएंगे। इसमें आलू के कश्मीरी स्वाद के साथ इसके मसालों की खुशबू और कश्मीरी मिर्च की लाली डिश को बेहतरीन लुक देती है। कश्मीरी पंडित विशेष कलेजी, यखनी मटन, कश्मीरी खीर जैसी डिशेज देखने से ही मुंह में पानी ला देती हैं।

मसालों की सुगंध के बिना अधूरा है स्वाद: 24 जनवरी तक चल रहे नवोटल फूड एक्सचेंज के जीएमडी बिश्वजीत चक्रवर्ती का कहना है कि कश्मीरी फूड में खुशबूदार मसालों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इस आयोजन के लिए विशेष रूप से कश्मीरी मसालों को मंगवाया गया है। इसी तरह से हर डिश में यहां पर कश्मीरी मिर्च और सरसों के तेल का स्वाद दिया जा रहा है।

– प्रियंका दुबे मेहता

शेफ रानी झिंसी....होमशेफ सीजन थ्री कश्मीरी पंडित क्यूजीन तैयार करते हुए। सभी फोटो : शेफ रानी झिंसी

मटन एपेटाइजर

कश्मीरी पंडित क्यूजीन

विभिन्न विधाओं का संगम

कला की अनेक विधाओं की प्रदर्शनी तो खूब देखी होगी लेकिन क्या कपड़ों पर आधारित प्रदर्शनी देखी है? नहीं, तो वस्त्रम जरूर देखें। वस्त्रों को लेकर भारतीय समाज में बड़ा इतिहास है। क्या पहने क्या ना पहनें की इस जटिल गुत्थी से इतर यह प्रदर्शनी आपको एक नया नजरिया देगी।
- **कहां** : कन्वेंशन सेंटर।
- **कब** : 24 से 27 जनवरी, सुबह दस से शाम सात।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

सिम्फनी ईट्स

यहां चाइनीज, नार्थ इंडियन जायका ग्राहकों को पसंद आता है। चाइनीज स्नैक में वेज स्प्रिंग रोल, हनी चिली पोटेटो, चिली पनीर ड्राइ, रोल, चिली चाप है। वहीं मेन कोर्स में वेज मंचुरीयन, पनीर ग्रेवी का स्वाद से सकते हैं। इंडियन मेन कोर्स में दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, तवा चाप मसाला, मलाई कोफ्ता आदि लाजवाब है।
- **कहां** : रोहतक रोड, पश्चिम विहार।
- **कब** : सुबह साढ़े ग्यारह बजे से रात ग्यारह बजे तक।
- **प्रवेश** : 550 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

दरियागंज का कबाब

दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में दरियागंज की सांसे धड़कती है। स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर भी है, जहां तंदूरी फ्रूट चाट, चिकन पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं। यहां के कबाब का तो क्या कहना। कबाब में पनीर टिक्का, दही कबाब, मशरूम कुरकुरे, हरा भरा कबाब आदि है। यही वजह है कि एनसीआर से भी ग्राहक यहां आते हैं।
- **कहां** : रीगल बिल्डिंग, कनॉट प्लेस।
- **कब** : सुबह 11 से रात 12 बजे तक।
- **प्रवेश** : प्रति दो व्यक्ति लगभग 1500 रुपये।

संविधान सभा ने जन-गण-मन को चुना राष्ट्रगान

1950 में आज ही राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया। रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे बांग्ला में लिखा और हिंदी अनुवाद अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया।

देश की पहली कमर्शियल पायलट प्रेम माथुर

1947 में आज ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की प्रेम माथुर को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। देश की पहली महिला कमर्शियल पायलट बन डेक्कन एयरवेज से सह-पायलट के तौर पर जुड़ीं। इससे पहले आठ कंपनियां उनकी अर्जी ठुकरा चुकी थीं। वे राष्ट्रीय हवाई दौड़ की विजेता भी रहीं।

जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में लगाया था शराब पर प्रतिबंध

आज ही के दिन 1924 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से मशहूर समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ। पढ़ाई छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में कूदे। 26 महीने जेल में बिताए। स्वतंत्रता के बाद अपने गांव में शिक्षक रहे। 1952 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और जून 1977 से अप्रैल 1979 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया था। 17 फरवरी 1988 को पटना में उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

लंदन में शख्स ने खोजी अपनी ही कब्र

लंदन, एजेंसी : उस शख्स की मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, जो अपनी ही कब्र ढूंढ ले। एलन हट का कहना है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे तीन-चार महीने से फोन क्यों नहीं आ रहे हैं और न ही कोई मुझसे मिलने आता है। बाद में पता चला कि लोग सोच रहे हैं कि मैं मर गया हूं। न्यूमोंथिल कब्रिस्तान में मेरी कब्र बना दी गई, जबकि मैं जिंदा हूं। मैंने खुद अपनी कब्र ढूंढी। उन्होंने पूर्व पत्नी पर कब्र के पत्थर पर अपना नाम लिखवाने का आरोप लगाया। हट फोरफर 75 साल के रिटायर्ड वेल्डर हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी जानकारी के बिना किया गया। अब उनकी कब्र को ढकने की योजना है। उनका आरोप है कि पूर्व पत्नी ने कब्र की जगह अपने साथ दफनाने के लिए खरीदी थी और इसी इरादे से कब्र का पत्थर लगाया है। उनके दोनों नाम इस पत्थर पर नजर आते हैं।

नई तकनीक से होगा पार्किंसंस का इलाज

तलाशी राह ▸ विशेष रसायनों के जरिये प्रभावित कोशिकाओं को बनाया जा सकता है लक्ष्य

यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने विकसित की विधि

वाशिंगटन डीसी, एएनआइ: वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस बीमारी के इलाज के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। यह ऐसी विधि है, जिसमें शरीर के किसी हिस्से में चिकित्सीय उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह मस्तिष्क कोशिका के उस खास समूह को लक्ष्य बनाती है, जिसकी वजह से इस बीमारी के लक्षण विकसित होते हैं।

पार्किंसंस तंत्रिका तंत्र का तेजी से फैलने वाला विकार है, जो हमारी गतिविधियों को प्रभावित करता है। यह हाथ में होने वाले कंपन से शुरू होता है, लेकिन जब कंपकपी पार्किंसंस का मुख्य संकेत बन जाती है, तो यह विकार अकड़न या धीमी गतिविधियों का भी कारण बन जाता है।

ऐसे विकसित की विधि : यह अध्ययन न्यूरोथेरेप्यूटिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने 2015 की शुरुआत में जीन थेरेपी विकसित की, जो बीमारी से प्रभावित तंत्रिका कोशिका के समूह को लक्ष्य बनाता है। इस प्रक्रिया को कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहा जाता है। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, ये कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं।

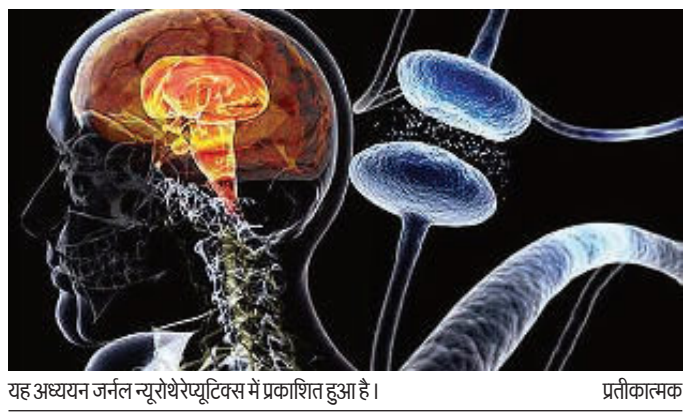

यह अध्ययन जर्नल न्यूरोथेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

ब्रेन इमेजिंग तकनीक के आने के बाद वैज्ञानिकों ने अब उन तरीकों को खोजा है, जो विशेष प्रकार के रसायन पैदा करने वाली कोशिकाओं को लक्ष्य बनाते हैं। इससे कोशिका-से-कोशिका के संपर्क के जरिये सफलतापूर्वक अन्य प्रकार के न्यूरॉन को उत्तेजित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में फार्माकोलॉजी के लेक्चरर डॉक्टर पियनार और इंपीरियल कॉलेज लंदन के उनके सहयोगियों ने मस्तिष्क में दो बड़ी न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को खोजा। पार्किंसंस बीमारी में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डोपामाइन उत्पन्न करता है, लेकिन इसे निष्क्रिय स्तर तक कम किया जा सकता है, जो अंततः मर जाता है। यह दुर्बल गतिविधि सहित कई तरह के लक्षणों का कारण बन सकता है।

दवाइयां नहीं होती कारगर : पार्किंसंस को फिलहाल दवाइयों से नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन यह पांच वर्षों के बाद बेअसर हो जाती है। इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिलता है। लेकिन, भविष्य में नई तकनीक से पार्किंसंस के मरीजों का अधिक प्रभावी तरीके से इलाज किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा, नई तकनीक का अभी मनुष्यों पर परीक्षण बाकी है। यदि यह तकनीक चिकित्सकीय परीक्षण के सभी चरणों पर खरी उतरती है तो पार्किंसंस मरीजों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगी।

चूहों पर किया अध्ययन

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं की टीम ने पार्किंसंस से पीड़ित एक चूहे के मॉडल में जीन थेरेपी का प्रयोग किया। डॉ. पियनार और उनकी सहयोगी ने इस प्रयोग के दौरान कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को लक्ष्य बनाया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या थेरेपी का प्रभाव डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पर भी पड़ता है। इसमें मूल रूप से उत्तेजित कोशिका दूसरी कोशिका पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए डोपामिनर्जिक कार्य को बहाल करने में सक्षम था। इस प्रक्रिया में दोनों तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजित होने के साथ पूरी तरह ठीक होते हुए देखा गया। उन्होंने कहा, 'जब हमने ब्रेन इमेजिंग का प्रयोग किया, तो हमने पाया कि जैसे ही कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को सक्रिय किया, वे प्रत्यक्ष रूप से डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के संपर्क में आ गए।' उन्होंने कहा कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मस्तिष्क में नई तंत्रिका प्रणाली के बारे में बताता है। साथ ही, इसकी मदद से हम पार्किंसंस से पीड़ित लोगों की मस्तिष्क की दो बड़ी प्रणालियों को ठीक कर सकते हैं।

फोटो न्यूज

अंतरिक्ष में पहली बार बेक की चॉकलेट कुकीज

अंतरिक्ष में सब्जियां उगाने के बाद पहली बार चॉकलेट चिप कुकीज भी बेक कर ली गई है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच (दाएं) और इटली के लुका परमिटानो (बाएं) को कुकीज बेक करने में दो घंटे का वक्त लगा। जबकि धरती पर इसे बेक करने में महज 20 मिनट लगते हैं। इस की जानकारी को क्रिस्टीना कोच ने ट्वीट के जरिये साझा किया। हालांकि इसका स्वाद कैसा है, कोई नही जानता। दरअसल, इसे बेकिंग पाउच में सील करके स्पेस फ्लाइट कंटेनर में डाल दिया गया है। वह अगले सप्ताह स्पेस एक्स के कैप्सूल के जरिये धरती पर पहुंचेगा। एपी

... तो इसलिए ब्लैकहोल डिस्क से निकली तरंगें बदल देती हैं एक्स-रे की प्रकृति

जागरण संवाददाता, कानपुर

- आइआइटी कानपुर के प्रो. जेएस यादव ने बनाया एक्स-रे डिटेक्टर
- इसरो के एस्ट्रोसेट सेटेलाइट के साथ घूम रहा अंतरिक्ष में, प्रतिक्षण भेज रहा डाटा

अभी तक रहस्य बना ब्लैक होल का राज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर की मुट्ठी में आ रहा है। वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना वह सवाल, आखिर ब्लैक होल की एक्स-रे अपनी प्रकृति क्यों बदलती हैं, आइआइटी कानपुर के प्रोफेसरों ने हल कर लिया है। यह संभव हुआ है, भौतिक विभाग के प्रो. जेएस यादव के बनाए एक्स-रे डिटेक्टर से। यह डिटेक्टर ब्रह्मांड से ब्लैक होल संबंधी डाटा भेज रहा है। भौतिक विज्ञान विभाग के ही प्रो. पंकज जैन ने डाटा का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को ब्लैक होल की स्थिति के बारे में पूर्व जानकारी मिल सकेगी। खगोलीय पिंडों के ब्लैक होल से टकराने की घटना भी पहले पता चल जाएगी और उसका अध्ययन किया जा सकेगा।

खगोलीय पिंडों को निगलने की क्षमता रखने वाले ब्लैकहोल वैज्ञानिकों के लिए हमेशा शोध का विषय रहे हैं। कानपुर आइआइटी में भी शोध चल रहा था। उसी कड़ी में एक्स-रे डिटेक्टर बनाया गया। एक्स-रे डिटेक्टर के आंकड़ों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान के प्रो. पंकज जैन ने बताया कि ब्लैक होल के आसपास एक डिस्क बनती है, जिससे हमेशा ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा की तरंगें कभी विरल तो कभी सघन होती हैं। इससे दबाव का स्वभाव बदलता है। तरंगें डिस्क से निकलने वाली एक्स-रे पर प्रेशर डालती हैं और दबाव की यही प्रकृति एक्स-रे की प्रकृति बदल देती है। एक्स-रे डिटेक्टर से मिले डाटा से ऊर्जा उत्सर्जन का समय, उसके अधिकतम व न्यूनतम होने के कालखंड की भी जानकारी मिल रही है।

इसरो ने एस्ट्रोसेट सेटेलाइट के साथ भेजा था डिटेक्टर : प्रो. जेएस यादव ने विदेशी सेटेलाइट से प्राप्त डाटा के जरिये ब्लैक होल पर अध्ययन किया। इसी आधार पर एक्स-रे डिटेक्टर बनाया, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में विकसित किया गया। इसरो ने इसे एस्ट्रोसेट सेटेलाइट के साथ ब्रह्मांड में भेजा। डिटेक्टर वहां से पल-पल का डाटा रिकार्ड कर भेज रहा है। प्रो. यादव का कहना है कि इससे पहले दुनिया में कोई भी ऐसा सेटेलाइट नहीं था, जो एक्स-रे की बदलती प्रकृति के बारे में बता सके। इस डिटेक्टर से ब्रह्मांड के ब्लैक होल, उनकी स्थिति और प्रकृति का भी पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट में कानपुर आइआइटी की शोध छात्रा दिव्या रावत और द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के प्रो. रंजीव मिश्रा भी शामिल हैं।

अब ट्विटर पर संदेशों के साथ इमोजी भी भेज सकेंगे

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अब यूजर संदेशों के साथ इमोजी भी भेज सकेंगे। कंपनी ने आइओएस और एंड्रॉइड पर सभी यूजर्स के लिए प्रत्यक्ष संदेशों के लिए नई इमोजी रिएक्शन (प्रतिक्रिया)शुरू कर दी है। यह ठीक वैसा ही विकल्प होगा, जैसे फेसबुक ने 2017 में मैसेंजर के साथ जोड़ा था। आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने इस नए फीचर को लाइव होने के बाद उपलब्ध होने वाले इमोजी के स्ट्रिंग को साझा करते हुए इसकी जानकारी दी है।

इमोजी रिएक्शन जोड़ने के लिए, संदेश पर आते हुए दिल यानी हार्ट बटन पर क्लिक करें जिसे रिएक्शन बटन भी कहा जाता है। इसके साथ ही यूजर्स संदेश पर दो बार क्लिक करते हुए पॉप-अप के बाद एक इमोजी का चयन कर सकते हैं। कंपनी ने एक ट्वीट के जरिये इमोजी को चयन करने के बारे में जानकारी दी है।

इस नए फीचर में सात नई प्रतिक्रियाएं शामिल की हैं और कोई भी यूजर किसी भी प्रकार के संदेश में इमोजी रिएक्शन जोड़ सकता है। यह टेक्स्ट या मीडिया अटैचमेंट के साथ किया जा सकता है।

अपडेट न करें एप : ट्विटर ने एंड्रॉइड यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म यूजर्स ट्विटर एप को अपडेट न करें। इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना यूजर्स के लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। दरअसल, कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि एप को अपडेट करने के बाद से उनका ऐप क्रैश होना शुरू हो गया। कंपनी का कहना है ट्विटर एप के 8.28 वर्जन में एक बग के कारण ऐसा हो रहा है। कपंनी का कहना है कि वो उस बग को ठीक करने पर काम कर रही है। ट्विटर की सपोर्ट टीम ने यूजर्स से माफी मांगी है और ट्वीट कर कहा है कि वे एंड्रॉइड एप में आए इस बग की जांच कर रहे हैं।

बालों को सफेद होने से रोकने की जगी उम्मीद

शोध अनुसंधान

शोधकर्ताओं ने पहली बार उस तंत्र की पहचान की है, जिसमें तनाव के कारण बालों का रंग सफेद होने लगता है। इससे ऐसी नई दवाओं के विकास की उम्मीद जग सकती है, जिनसे बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह निष्कर्ष काले चूहे पर किए गए शोध के आधार पर निकाला गया है। चूहे पर कई हफ्ते तक रेसिनिफेराटॉक्सिन नामक रासायनिक पदार्थ को आजमाया गया। इसके चलते चूहे के बाल पूरी तरह सफेद हो गए।

शोधकर्ताओं ने पाया कि संवेदी तंत्रिका तंत्र बाधित होने पर बाल सफेद होने लगते हैं। यह तंत्रिका तंत्र घातक स्थितियों से निपटने में शरीर की अनैच्छिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। तनाव से यह तंत्र सीधे प्रभावित होता है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता थिएगो मैटर ने कहा, 'लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि तनाव से बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इस धारणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था।' -प्रेट्र

दांतों को सड़ने से रोकेगा नया पेप्टाइड जेल

दांतों में कैविटी और सड़न की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसा बायोएक्टिव पेप्टाइड जेल विकसित किया है, जिसे लगाने से ना सिर्फ दांतों को सड़न और कैविटी से बचाने में मदद मिल सकती है बल्कि उन्हें ठीक भी किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में दांतों की सड़न और कैविटी की समस्या सबसे आम गैर-संचारी बीमारी है। शोधकर्ताओं के अनुसार, पारंपरिक उपचार में खराब टिश्यू को निकालने के बाद कैविटी को भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में स्वस्थ टिश्यू को नुकसान भी पहुंच सकता है और तकलीफ भी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखकर हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह जेल तैयार किया है। उनका यह एंटी-कैविटी कोटिंग जेल प्राकृतिक रोगाणु रोधी एच5 नामक पेप्टाइड पर आधारित है। इससे दांतों को कई रोगों से बचाया जा सकेगा। -आइएएनएस

फिल्म रिव्यू

अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है डांस

स्ट्रीट डांसर 3डी

प्रमुख कलाकार: वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा, नोरा फतेही, पुनीत पाठक, धर्मेश येलांडे, सलमान युसुफ खान, सुशांत पुजारी, राघव जुयाल
निर्देशक: रेमो डिसूजा
अवधि: 150 मिनट

'एबीसीडी' और 'एबीसीडी 2' के बाद डांस पर रेमो डिसूजा अपनी अगली फिल्म 'स्ट्रीट डांसर 3डी' लेकर आए हैं। इसे वह 'एबीसीडी' फ्रेंचाइजी में कुछ कारणों की वजह से शामिल नहीं कर पाए, लेकिन यह फिल्म उसी जोन में बनी है।

कहानी शुरू होती है लंदन में होने वाली एक डांस प्रतियोगिता ग्राउंड जीरो के साथ। डांस करते वक्त इंदर (पुनीत पाठक) घायल हो जाता है। स्ट्रीट डांसर ग्रुप का ग्राउंड जीरो जीतने का सपना वहीं टूट जाता है। दो साल बाद कहानी आगे बढ़ती है, जब इंदर का भाई सहज (वरुण धवन) भारत से पैसे कमाकर लंदन लौटता है। वह इंदर के लिए डांस क्लास खोलता है। स्ट्रीट डांसर्स का ग्रुप दोबारा इकट्ठा होता है।

लंदन में एक दूसरा पाकिस्तानी डांस ग्रुप रूल ब्रेकर्स भी हैं। जिसकी मुख्य डांसर इनायत (श्रद्धा कपूर) है। दोनों ग्रुप्स की आपस में बनती नहीं है। दोनों के बीच अक्सर प्रभु अन्ना (प्रभुदेवा) के रेस्तरां में भारत-पाकिस्तान का मैच देखते वक्त झड़प होती रहती है। प्रभु के रेस्तरां में इनायत कुछ लोगों को देर रात जाते देखती है। उसे पता चलता है कि वे अवैध आप्रवासी हैं, जो सड़कों पर भूखे रहने को मजबूर हैं। प्रभु अन्ना उन्हें बचा हुआ खाना खिलाते हैं। इनायत उनकी मदद करने की सोचती है। प्रभु अन्ना इनायत और सहज से कहता है कि वे मिलकर डांस करे, तो ग्राउंड जीरो जीत सकते हैं...।

रेमो डिसूजा की पहली दोनों फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में डांस का जोश थोड़ा कम नजर आया। 3डी में फिल्म को बनाने की कोशिश अच्छी जरूर है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल डांस में कम दिखा। इस फिल्म के जरिये गैरकानूनी तरीके से लंदन में रहने वाले अवैध आप्रवासियों का दर्द, उन्हें उनके देश पहुंचाने की कोशिश, भारत-पाकिस्तान के लोगों में आपसी कड़वाहट के बीच भाई का सपना पूरा करने की जद्दोजहद जैसी कई चीजों को समेटा गया है, जिसकी वजह से फिल्म लंबी हो गई है। फिल्म का पहला हिस्सा धीमा है, दूसरे में रेमो डिसूडा डांस दिखाने में कामयाब रहे। सेमी फाइनल्स का डांस रोंगटे खड़े करता है। फाइनल्स का मुकाबला नाटकीय है, लेकिन संदेश दे जाता है कि डांस का असली मजा ढोल और भारतीय गानों पर ही आता है। रेमो डिसूजा ने इस फिल्म के जरिये यह बताया है कि डांस अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है। फिल्म वह सीन अच्छा है, जिसमें प्रभुदेवा का किरदार भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मॉरल साइंस और इतिहास के जरिये यह बात मजेदार तरीके से समझाता है कि भारत और पाकिस्तान के डांसरों को साथ में डांस क्यों करना चाहिए।

प्रभुदेवा का 'मुकाबला...' गाने पर डांस फिल्म की जान है। वरुण धवन सहज के किरदार को महसूस करते हैं। नोरा फतेही जब डांस करती हैं, तो दर्शकों की उनसे नजरें हटाना मुश्किल है। श्रद्धा इनायत के किरदार में जंची हैं। पुनीत पाठक को भले ही डांस करने का मौका कम मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय से चौंकाया है। मिले सुर मेरा तुम्हारा..., हाय गर्मी..., बेजुबान कबसे मैं रहा... जैसे गाने कर्णप्रिय हैं।

प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में पंगा लेने की जरूरत नहीं : रिचा चड्ढा

सात सवाल

रील लाइफ में फिल्म 'पंगा' में कबड्डी खिलाड़ी बनी अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने असल जिंदगी में लिए गए पंगों पर बात की :

जिंदगी का पहला पंगा कब लिया था?

- मैं बचपन से शरारती हूं। मुंबई आकर एक्टर बनी। मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी, मेरे माता-पिता इस शहर के नहीं थे। मेरी जिंदगी में इससे बड़ा पंगा और कुछ भी नहीं है। मैं चार भाइयों के बीच इकलौती बहन हूं। लड़कों की तरह ही रहती थी। मैंने कुछ शरारती पंगे जरूर लिए है। जैसे किसी से कहना कि तुम गोद लिए हो। या किसी को कूड़ादान दिखाना कि मम्मी ने तुम्हें यहां से उठाया है। इस तरह की बहुत शरारतें की हैं।

फिल्म इंडस्ट्री में पंगे लेना कितना आसान हुआ है?

- अब मुझे फिल्म इंडस्ट्री में पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी के लिए मैं खुद को नहीं बदलती। मुझे जो ठीक लगता है, वही कहती और करती हूं। मुझे जो नहीं ठीक लगता, उसे नहीं करती।

किसी दूसरे का कौन-सा पंगा बहुत अच्छा लगा?

- फिल्ममेकर जोया अख्तर से लोग कहते थे कि तुम सिर्फ अमीर लोगों की कहानियां बना सकती हो। तुम्हें क्रूज पर जाने वाले और महंगी शराब पीने वालों के ही दर्द की समझ है। उसके बाद उन्होंने धारावी में जाकर 'गली ब्वॉय' जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई। यह फिल्म देखने के बाद मुझे उनका यह सबसे अच्छा पंगा लगा।

जिंदगी में किन पंगों से हमेशा दूर रहना चाहेंगी?

- मारपीट और गाली-गलौज जैसे पंगों से हमेशा दूर रहना चाहूंगी। इसके अलावा किसी खास किस्म के कलेक्शन से दूर रहना चाहूंगी। मुझे नैतिकता की चिंता रहती है। मुझे कर्म में विश्वास है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जो अपने व्यवहार की वजह से बहुत ही जल्दी अर्श से फर्श पर आ जाते हैं।

आगे बढ़ने के लिए क्या पंगे लेना जरूरी है?

- आगे बढ़ने वाले ही सपने देखते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या अच्छी नौकरी के लिए पहले दिमाग में उसका विचार आना जरूरी है। यह विचार ही तो सपना है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जैसे लोगों ने भी पहले सोचा होगा। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर कर देना आसान नहीं होता। कहीं न कहीं यह विचार सपने देखने से ही आया होगा।

'पंगा' फिल्म से आपने क्या सीखा?

- मैंने इस फिल्म में सिर्फ कबड्डी सीखी है। बचपन में हम कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट आदि खेलते थे। पहली बार कबड्डी को पेशेवर तौर पर समझा। यह एक भारतीय खेल है, जिसमें भारत शीर्ष पर रहा है। पिछले विश्वकप में एक कोच आई थी, जिसे भारत ने नहीं रखा और ईरान ने अपनी टीम की कोचिंग के लिए रख लिया। पिछला विश्वकप ईरान जीत गया। हमारे यहां सिफारिश चलती है। इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए।

'पंगा' में आप सपोर्टिंग किरदार में पंगा ले रही हैं...

- लीड किरदार में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में मैं मां का किरदार निभा चुकी थी। साथ ही, मैं खेल से जुड़ी फिल्म करना चाहती थी, इसलिए इस फिल्म के लिए हां की।

स्मिता श्रीवास्तव

भूमि पेडणेकर ने शुरू की 'दुर्गावती' फिल्म की शूटिंग

मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर भूमि पेडणेकर ने अपनी आगामी फिल्म 'दुर्गावती' की शूटिंग गुरुवार से शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी अक्षय कुमार और भूमि पेडणेकर ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने एक तस्वीर साझा की, जिसमें भूमि मां दुर्गा के सामने हाथ जोड़े बैठी हैं। उन्होंने लिखा कि आशीर्वाद के साथ वह अपने करियर की सबसे खास फिल्म 'दुर्गावती' की शूटिंग शुरू कर रही हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म से बतौर प्रजेंटर जुड़े हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन जी. अशोक कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग भोपाल में शुरू होगी। इसके पहले भूमि ने एक तस्वीर में स्क्रिप्ट की कॉपी के साथ हैशटैग में भोपाल लिखा था। यह फिल्म वर्ष 2018 में रिलीज अनुष्का शेट्टी अभिनीत तेलुगु हॉरर फिल्म 'भागमती' की हिंदी रीमेक होगी, जिसका निर्देशन भी जी. अशोक ने ही किया था।

सलमान पर अब भी साइकिल मैकेनिक के उधार हैं एक रुपये पच्चीस पैसे...

सलमान खान साइकिल चलाने के कितने शौकीन हैं, इससे उनके फैंस वाकिफ हैं। अक्सर सलमान मुंबई में बांद्रा स्थित अपने घर के आसपास साइकिल चलाते हुए दिख जाते हैं। कम दूरी वाली जगहों पर वह साइकिल से ही जाते हैं। साइकिल के प्रति उनका यह प्यार बचपन का है। सलमान ने बताया कि अब भी उन पर एक साइकिल मैकेनिक का उधार है। दरअसल, सलमान ने जिस मैकेनिक से अपनी साइकिल ठीक करवाई थी, उसके एक रुपये पच्चीस पैसे उन्होंने आज तक नहीं दिए हैं। सलमान यह बात भूल भी गए थे। उन्हें यह बात खुद उस मैकेनिक ने याद दिलाई, जब सलमान सुपरस्टार बनने के बाद एक बार उसी साइकिल वाले के पास अपनी साइकिल का पहिया ठीक कराने पहुंचे थे। उस मैकेनिक को यह बात नहीं पता थी कि सलमान खान सुपरस्टार बन चुके हैं। सलमान शॉर्ट पैंट पहने पहुंचे थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने उस मैकेनिक से कहा कि वे साइकिल ठीक कर दें, पैसे वह बाद में

आकर दे देंगे। इस पर मैकेनिक ने कहा कि तुम बचपन में भी ऐसा ही करते थे। बहुत पहले तुमने साइकिल ठीक करवाई थी और आज तक पैसे नहीं दिए। आज भी 1.25 रुपये उधार हैं। सलमान ने कहा कि यह सुनकर उन्हें बहुत शर्म आई। जब वह उस मैकेनिक के पैसे लौटाने गए, तब उसने पैसे लेने से इन्कार कर दिया। पुरानी बातें साझा करते हुए सलमान ने यह भी बताया कि पैसे बचाने के लिए वह अपने स्कूटर में आधा पेट्रोल और आधा केरोसीन डाला करते थे। सलमान फिलहाल अपनी आगामी फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' की शूटिंग में व्यस्त हैं।

पिता जैकी श्रॉफ के साथ पहली बार स्क्रीन पर दिखेंगे टाइगर

टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखा है, तब से अक्सर उनसे यह सवाल पूछा जाता रहा है कि वह कब अपने पिता के साथ फिल्म करेंगे। जैकी श्रॉफ से भी यह सवाल पूछा जाता है। दोनों यही कहते थे कि जब कोई स्क्रिप्ट आएगी, तो जरूर करेंगे। आखिरकार वह स्क्रिप्ट दोनों को मिल ही गई। खबरें हैं कि टाइगर 'बागी' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'बागी 3' में अपने पिता के साथ स्क्रीन साझा करने की तैयारी में हैं। यह कमाल साजिद नाडियाडवाला ने कर दिखाया है। सूत्रों की मानें तो साजिद ने जब जैकी श्रॉफ को किरदार के बारे में बताया, तब उन्होंने तुरंत हां कर दी। 'बागी 3' में

जैकी श्रॉफ रितेश देशमुख और टाइगर श्रॉफ के पिता की भूमिका में होंगे। रितेश पुलिस अफसर का किरदार निभाएंगे। पहले खबरें आ रही थीं कि यह फिल्म 'रामलखन' की तर्ज पर बन रही है, लेकिन रितेश ने साफ कर दिया था कि फिल्म 'रामलखन' जैसी बिल्कुल नहीं है। दो भाइयों की कहानी की वजह से शायद लोगों को ऐसा लग रहा हैं, लेकिन यह फिल्म भाइयों के बीच के रिश्तों को दर्शाते हुए बागी फ्रेंचाइज के फ्लेवर को बरकरार रखेगी।

जब कुणाल खेमू ने प्रतियोगी को तोहफे में दिया अपना लॉकेट...

बतौर बाल कलाकार करियर शुरू करने वाले कुणाल खेमू की बतौर हीरो पहली फिल्म 'कलयुग' थी, जो आज भी उनके दिल के बेहद करीब है। इस फिल्म की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं, जब कुणाल पहुंचे 'इंडियन आइडल 11' के सेट पर। वहां फिल्म 'मलंग' की पूरी टीम अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी और कुणाल खेमू अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। शो के प्रसिद्ध प्रतियोगी सनी हिंदुस्तानी ने जब कुणाल की पहली फिल्म का गाना 'जिया धड़क धड़क...' गाया, तब कुणाल इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी लक्ष्मी मां का लॉकेट सनी को तोहफे में दे

दिया। कुणाल ने कहा कि सनी के पास मां सरस्वती का आशीर्वाद है, जो उनकी आवाज में नजर आता है। वह चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी उन पर बना रहे, इसलिए वह लॉकेट उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। फिल्म 'मलंग' 7 फरवरी को रिलीज होगी। इसके बाद कुणाल खेमू 'गो गोवा गॉन' के सीक्वल में नजर आएंगे।